सिविल सर्विसेस मासिक

दिसंबर 2020

सिविल सर्विसेस परीक्षाओं के सभी समाधान एक स्थान पर

हवाना सिंड्रोम
विश्व एड्स दिवस
पैसेक्स अभ्यास
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020
एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (ABU) अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020
पहलो डाऊनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना
थारू आदिवासी
उप्र धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश इस्लामिक संगठन
शहद एफपीओ कार्यक्रम
3 आरएफ फ्रेमवर्क
सार्वजनिक वाई–फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI)
इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (GRIHA) समिट के लिए ग्रीन रेटिंग

विषय–सूची

प्रारंभिक परीक्षा

हवाना सिंड्रोम	1
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA)	6
पासेक्स अभ्यास	8
'गो फॉर ज़ीरों' नीति'	13
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020	25

सामान्य अध्ययन – 1

भारतीय हेरिटेज और संस्कृति, इतिहास और भूगोल विश्व और समाज

पहली डाउनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना	29
ऊर्जा, पर्यावरण और जल पर परिषद (सीईईवी)	31
भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन	32
आइसबर्ग A68	33

सामान्य अध्ययन – 2

शासन, संरक्षण, नीति, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध

उप्र धर्म परिवर्तन अध्यादेश	33
कश्मीर पर इस्लामिक सहयोग संगठन	35
पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग	36
छठां भारत–सीएलएमवी बिजनेस कॉन्क्लेव 202	38
भारत में तस्करी रिपोर्ट 2019–20	39
एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी (APVAX)	41
मोटर वार्षिक रिपोर्ट	41
यूनेस्को की भारत में 2020 की शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट	43
धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020	46

सामान्य अध्ययन – 3

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव–विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और प्रबंधन प्रबंधन

शहद एफपीओ कार्यक्रम	**46**
HSN कोड 69	**50**
तरलता समायोजन सुविधा	**52**
हाथियों के लिए गलियारे	**55**
सार्वजनिक वाई–फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI)	**56**
प्लास्मोडियम ओवल मलेरिया	**57**
सीएमएस – 01	**60**
स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट	**63**
कंपनियां (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (CARO)	**65**

प्रारंभिक परीक्षा संबंधित समसामयिकी – दिसंबर 2020

हवाना सिंड्रोम

समाचार –

- हाल ही में, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (एनएएस) की एक रिपोर्ट में, यूएसए ने निर्देशित स्पंदित माइक्रोवेव विकिरण (डायरेक्टेड पल्स्ड माईक्रोवेव रेडिएशन) को हवाना सिंड्रोम का कारण पाया।

हवाना सिंड्रोम –

- 2016 के अंत में, यूएसए के राजनयिकों एवं अन्य कर्मचारियों ने हवाना में (क्यूबा की राजधानी), अजीब आवाजे सुनने एवं अजीब शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव करने के बाद बीमार महसूस किया।
- लक्षणों में मतली आना, गंभीर सिरदर्द, थकान, चक्कर आना, नींद की समस्याएं एवं श्रवण शक्ति में हानि शामिल हैं, जिन्हें तब से हवाना सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है।
- हवाना कर्मियों द्वारा झेली गई अधिक पुरानी समस्याओं में मुख्य रूप से श्रवण एवं संज्ञानात्मक समस्याओं के साथ अनिद्रा एवं सिरदर्द शामिल थे।
- कुछ कर्मचारियों के लिए यह लक्षण गंभीर साबित नही हुए जबकि इनसे कईयों के कार्यों में एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न हुई एवं उनके जीवन का सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ।

मुख्य निष्कर्ष –

- समिती के अनुसार निर्देशित स्पंदित माइक्रोवेव विकिरण ऊर्जा (डायरेक्टेड पल्स्ड माईक्रोवेव रेडिएशन) उन लोगों के बीच हवाना सिंड्रोम के मामलों की व्याख्या करने में सबसे स्वीकार्य तंत्र प्रतीत होती है।
- इसे 'निर्देशित' एवं 'स्पंदित' ऊर्जा कहकर, रिपोर्ट इस भ्रम के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है कि पीड़ितों को लक्षित किया गया था एवं माइक्रोवेव ऊर्जा सामान्य स्रोतों से उत्पन्न नही थी।
- रोगियों को सूचित किए गए तात्कालिक लक्षण, जिसमें दर्द एवं भिनभिनाहट की आवाजें शामिल हैं, जाहिर तौर पर विशेष दिशा, या किसी कमरे के एक विशिष्ट स्थान पर हुई थी।
- यह घटना भविष्य में ऐसी और घटनाओं के संभावना के बारे में चेतावनी देती है एवं यह कहते हुए कि भविष्य में इस तरह घटनाओं को और अधिक तथा तुरंत पहचान में ना आ सकने के स्तर पर फैलाया जा सकता है, इसी तरह की घटनाओं के लिए एक प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने की सिफारिश करती है।
- हालांकि, समिति अन्य संभावित तंत्रों को खारिज नहीं करती है एवं इस संभावना पर विचार करती है कि कुछ मामलों में कारकों की बहुलता हो सकती है।
- हालाँकि समिती ने माइक्रोवेव हथियारों पर महत्वपूर्ण शोध किया है फिर भी उत्सर्जित ऊर्जा के स्त्रोत का का भी उल्लेख नहीं करती।

माइक्रोवेव हथियार –

- 'माइक्रोवेव हथियार' को एक प्रकार का प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार माना जाता है, जो एक लक्ष्य पर ध्वनि, लेजर या माइक्रोवेव के रूप में अत्यधिक ऊर्जा केंद्रित करने का लक्ष्य रखता है।
- उच्च तीव्रता वाले माइक्रोवेव स्पंदनों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों ने भनाभनाहट की शिकायत की है, जैसे कि वह सिर के भीतर से आ रही हो। इन तरंगों से शारीरिक क्षति के संकेतों को छोड़े बिना तात्कालिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रभाव हो सकते हैं।

भांग को हानिकारक प्रदार्थों की सूची से हटाया गया

समाचार –

- संयुक्त राष्ट्र ने भांग एवं भांग की राल (रेसिन) को 'सर्वाधिक हानिकारक प्रदार्थों' की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव पारित किया।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 'सर्वाधिक हानिकारक प्रदार्थों' की सूची से भांग को निकालने के पक्ष में वोट किया।
- भारत, अमेरिका एवं यूरोपीय संघ के देशों सहित कुल 27 सदस्य देशों ने वोट का समर्थन किया, जबकि चीन, पाकिस्तान एवं रूस सहित 25 देशों ने विरोध किया।
- मादक द्रव्यों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 1961 मेंएकल कन्वेंशन के तहत अपने अनुसूची IV वर्गीकरण से भांग एवं भांग की राल को हटाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई सिफारिश को मंजूरी दी। इससे भांग अपने ही एक यौगिक हेरोइन एवं अन्य ओपियोइड की श्रेणी में चला गया।
- अनुसूची IV के रूप में वर्गीकृत पदार्थ अनुसूची I दवाओं का एक उपसुच्चय है। इसका अर्थ है कि न केवल उन्हें 'अत्यधिक नशे की लत एवं दुरुपयोग के लिए अत्यधिक उत्तरदायी माना जाता है' उन्हें 'विशेष रूप से हानिकारक एवं अत्यंत सीमित चिकित्सा या चिकित्सीय मूल्य' के रूप में भी अंकित किया जाता है।

भांग –

- भांग, जिसे अन्य नामों के मध्य मारियुआना के रूप में भी जाना जाता है, भांग के पौधे से प्राप्त एक साईकोएक्टिव ड्रग है जो मुख्य रूप से चिकित्सा या मनोरंजन प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती है।
- भांग का उपयोग धूम्रपान, भापपान, भोजन या अर्क के रूप में किया जा सकता है।
- भांग के विभिन्न मानसिक एवं शारीरिक प्रभाव होते हैं, जिसमें व्यंजना, मन की बदलती स्थिति एवं समय की भावना का अभाव, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, अल्पकालिक स्मृति एवं शरीर की गति, आराम एवं भूख में वृद्धि शामिल हैं।
- उच्च खुराक पर, मानसिक प्रभावों में चिंता, भ्रम (संदर्भ के विचारों सहित), मतिभ्रम, आतंक, व्यामोह एवं मनोविकार शामिल हो सकते हैं।

मादक द्रव्यां (नारकोटिक ड्रग्स) पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (CND)

- CND संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के कार्यात्मक आयोगों में से एक है एवं संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर केंद्रीय औषधि नीति बनाने वाली संस्था है एवं अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्यों के नियंत्रण सम्मेलनों के तहत महत्वपूर्ण कार्य करती है।
- CND का उद्देश्य मादक द्रव्यों से निपटने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं समझौतों के कार्यान्वयन की निगरानी में ECOSOC की सहायता करना है।
- CND को अतिरिक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कंट्रोल कार्यक्रम की शासी निकाय की भूमिका सौंपी गई है, जिसे संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा ड्रग्स एवं अपराध के लिए प्रशासित किया जाता है।

रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान

समाचार –

- रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने चीन, पाकिस्तान की सीमाओं पर केंद्रित अनुसंधान के लिए नई प्रयोगशाला बनाई।
- सरकार द्वारा विलय किए गए दो नई प्रयोगशालाएँ मनाली–मुख्यालय वाले हिमपात एवं हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान (स्नो एंड एवलांश स्टडीज़ स्टेबलिशमेंट – एसएएसई) हैं एवं दूसरा दिल्ली स्थित रक्षा क्षेत्र अनुसंधान प्रतिष्ठान है।
- इस नई प्रयोगशाला में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश एवं पाकिस्तान तक की सीमाओं के साथ इलाके एवं हिमस्खलन पर शोध करने पर ध्यान दिया जाएगा।

हिमपात एवं हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान (एसएएसई) –

- एसएएसई रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक प्रयोगशाला है। मनाली, हिमाचल प्रदेश के पास स्थित इसका प्राथमिक कार्य हिमस्खलन के क्षेत्र में अनुसंधान है जो भारतीय सशस्त्र बलों को हिमस्खलन नियंत्रण के उपाय एवं पूर्वानुमान सहायता प्रदान करता है।

रक्षा क्षेत्र अनुसंधान प्रतिष्ठान –

- इसे 1954 में स्थापित किया गया था। प्रयोगशाला का प्राथमिक कार्य समय सीमा का मूल्यांकन करना एवं दुर्गम क्षेत्रों की गतिशीलता क्षमता का आकलन करना है।
- इसने विश्वसनीय प्रणालियां विकसित की हैं जो आधुनिक तकनीकों के आधार पर भविष्यवाणी करती हैं।
- इसके अलावा प्रयोगशाला नवीनतम तकनीकों एवं अनुसंधान से संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करती है।
- प्रयोगशाला का मिशन उपयोगकर्ताओं के लिए 'क्षेत्र जानकारी रिपोर्ट' एवं विषयगत मानचित्र बनाना एवं उसे अद्यतन करना है।

BNT162b2

समाचार –

- ब्रिटेन फाइजर–बायोएनटेक कोविड–19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया। अगले सप्ताह की शुरुआत से इसका उपयोग शुरू किया जाएगा।
- अमेरिकी फार्मास्युटिकल दिग्गज फाइजर एवं जर्मन बायोटेक फर्म BioNTech द्वारा निर्मित संयुक्त वैक्सीन ने हाल ही में दावा किया था कि यह सभी उम्र एवं नस्लों के लोगों पर अच्छा काम करता है।

BNT162b2 -

- BNT162b2 बायोविटेक एवं फाइजर द्वारा विकसित एवं इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला कोविड–19 वैक्सीन उम्मीदवार है।
- यह एक आरएनए वैक्सीन है जो न्यूक्लियोसाइड–संशोधित mRNA से बना है जो कि SARSCoV–2 के स्पाइक प्रोटीन का उत्परिवर्तित रूप है, एवं लिपिड नैनोकणों में लिप्त है।

विवरण –

- ब्रिटिश नियामक, मेडिसिन एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी (MHRA) का कहना है कि कोविड–19 बीमारी के खिलाफ 95 प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करने का दावा करने वाला टीका भेजे जाने के लिए तैयार है।
- टीकों को दूसरी खुराक के सात दिनों बाद मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के साथ 21 दिनों के दो और खुराक की आवश्यकता होती है।
- एनएचएस – राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, में बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम देने का दशकों का अनुभव है एवं वे टीकाकरण के लिए पात्र सभी लोगों को देखभाल एवं सहायता प्रदान करने के लिए अपनी व्यापक तैयारी शुरू कर देंगे।

वैक्सीन प्राथमिकता समूह –

- टीकाकरण एवं प्रतिरक्षण पर यूके की संयुक्त समिति (JCVI) ने प्राथमिकता समूहों की सूचि प्रकाशित की है। टीका, स्वास्थ्यकर्मियों, बुजुर्गों एवं नैदानिक रूप से बेहद कमजोर व्यक्तियों को यह पहले लगाया जाएगा।

वैक्सीन का विवरण –

- Pfizer/BionTech सूत्र एक mRNA टीका है जो शरीर को कोविड–19 से लड़ने एवं प्रतिरक्षी बनाने के लिए महामारी वायरस से आनुवंशिक कोड के एक छोटे टुकड़े का उपयोग करता है।
- एक mRNA वैक्सीन को पहले कभी मनुष्यों में उपयोग के लिए अनुमोदित नहीं किया गया था, केवल लोगों ने उन्हें अब तक नैदानिक परीक्षणों में प्राप्त किया है।
- वैक्सीन को लगभग –70°C तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए एवं इसे विशेष बक्सों में ले जाया जाएगा, जिन्हें सूखी बर्फ में पैक किया जाएगा। एक बार पहुंचाने के बाद, इसे फ्रिज में पांच दिनों तक रखा जा सकता है।
- फाइजर एवं बायोएनटेक ने अंतिम परीक्षण के परिणामों की सूचना दी थी जिसमें दिखाया गया था कि उनका टीका कोविड–19 को रोकने में 95 प्रतिशत प्रभावी था।
- वैक्सीन का निर्माण BioNTech की जर्मन प्रयोगशालाओं में किया जा रहा है, साथ ही बेल्जियम में फाइजर की निर्माण स्थल भी है।

दवाएं एवं हल्थकेयर उत्पाद नियामक एजेंसी (MHRA)

- एमएचआरए यूनाइटेड किंगडम में स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल विभाग की एक कार्यकारी एजेंसी है जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि दवाएं एवं चिकित्सा उपकरण काम करते हैं एवं स्वीकार्य रूप से सुरक्षित हैं।
- MHRA का गठन 2003 में मेडिसिंस कंट्रोल एजेंसी (MCA) एवं मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी (MDA) के विलय के साथ हुआ था।
- अप्रैल 2013 में, इसका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल (NIBSC) के साथ विलय कर दिया गया था एवं इसे MRARA पहचान के साथ समूह के भीतर नियामक केंद्र के लिए पूर्णतः इस्तेमाल किया जा रहा था।

आदि महोत्सव

समाचार –

- जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 10–दिवसीय आदि महोत्सव का शुभारंभ किया गया।
- इस वर्ष का मुख्य लक्ष्य मध्य प्रदेश के आदिवासी शिल्प एवं संस्कृति है।
- कोविड–19 के कारण, TRIFED ने अपने वार्षिक कार्यक्रम आदि महोत्सव–2020 को ऑनलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया है।

आदि महोत्सव –

- आदि महोत्सव आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन एवं वाणिज्य की भावना का एक अनूठा उत्सव है। इसे 2017 में शुरू किया गया था।
- यह त्योहार देश भर में आदिवासी समुदायों के समृद्ध एवं विविध शिल्प एवं संस्कृति से लोगों को परिचित कराने का प्रयास है।

'प्रधानमंत्री मोदी एवं उनकी सरकार के सिखों के साथ विशेष संबंध' पुस्तक का विमोचन

समाचार –

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने गुरुपर्व के अवसर पर सिखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी सरकार के विशेष संबंध नामक पुस्तक का विमोचन किया।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक अंग्रेजी, हिंदी एवं पंजाबी भाषाओं में जारी की गई थी।
- पुस्तक गुरु नानक देव के संदेशों पर आधारित है।
- यह पुस्तक नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा भारत में सिख समुदाय के कल्याण के लिए उठाए गए कई कदमों का संकलन है।

सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस

समाचार –

- सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ सीमा पर भारत का प्राथमिक सीमा सुरक्षा संगठन है।
- यह भारत के तीन सीमा सुरक्षा बलों (बीएसएफ) में से एक है, एवं 1 दिसंबर 1965 को 'भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं वहां से जुड़े मामलों के लिए' के लिए 1965 के युद्ध के मद्देनजर उठाया गया था।

विवरण –

- यह एक सीमा रक्षक बल है जिसका उद्देश्य पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ भारतीय भूमि सीमा की रक्षा करना है।
- बीएसएफ अपने अधिकारियों को आईपीएस से कमान एवं नेतृत्व के स्तर पर लाता है, साथ ही, इसका प्रमुख, एक महानिदेशक (डीजी) के रूप में नामित होता है।
- यह वर्तमान में विष्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है।
- बीएसएफ को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कहा जाता है।

जंगली 'किवी'

समाचार –

- अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में उगाने वाले जंगली किवी देश में अपनी तरह का एकमात्र प्रमाणित जैविक फल है।
- अरुणाचल प्रदेश देश में दुर्लभ किवी फल के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत हिस्सा रखता है।
- जीरो घाटी के किवी – लोअर सुबनसिरी जिले में स्थित – एक मानक तीन वर्ष की प्रक्रिया के बाद जैविक के रूप में प्रमाणित हुए।

विवरण –

- इस क्षेत्र से उगाए गए किवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण मिशन अक्टूबर में पूर्वोत्तर क्षेत्र (MOVCD–NER) के लिए मिशन कार्बनिक मूल्य श्रृंखला विकास द्वारा दिया गया था।
- MOVCD–NER एक विशेष योजना है जो देश के उत्तर–पूर्व क्षेत्र में कृषि संबद्ध गतिविधियों के विकास एवं संवर्धन के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है।
- जैविक उत्पाद का प्रमाणन यह दर्शाता है कि फसल के उत्पादन में कोई भी उर्वरक, कीटनाशक एवं अन्य प्रकार के रसायनों का उपयोग नहीं किया गया था।
- प्रमाणन उत्पादकों एवं हैंडलर की मदद करता है, ताकि वे उत्पादों के लिए उत्क्रष्ठ मूल्य प्राप्त कर सके तथा ये तेजी से बढ़ते, स्थानीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रखते हैं।
- इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है।
- किवी भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फलों में से एक है।

जेब्राफिश

समाचार –

- पुणे स्थित अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने जेब्राफिश का उपयोग एक शोध मॉडल के रूप में किया है एवं ऐसे जीनों की पहचान की है जो हृदय उत्थान को बढ़ावा दे सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस पशु मॉडल का उपयोग करते हुए हृदय उत्थान प्रक्रियाओं को डिकोड करने की खोज की है।

जेब्राफिश –

- जेब्राफिश – 2–3 सेंटीमीटर लंबी एक छोटी मीठे पानी की मछली कुशलता से थोड़े समय के भीतर अपने क्षतिग्रस्त दिल को फिर से बना सकती है।
- जेब्राफिश उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मछली दक्षिण एशिया के इंडो–गंगा के मैदानों की मूल निवासी है, जहां वे ज्यादातर धान के खेतों एवं यहां तक कि स्थिर पानी एवं धाराओं में पाई जाती हैं।
- यह मछलीघर में रखी जाने वाली एक लोकप्रिय मछली है, जिसे अक्सर 'डैनियो' नाम से बेचा एवं जाना जाता है।
- मछली तीन महीने में वयस्क हो जाती है एवं एक प्रयोगशाला में 2–3 वर्ष तक जीवित रहती है।
- इस मछली की अनूठी विशेषताएं अपने गले के चरणों के दौरान इसकी पारदर्शिता में निहित हैं, जिससे दिल एवं रक्त परिसंचरण सहित सभी अंगों का निरीक्षण किया जा सकता है।
- मस्तिष्क, हृदय, आंख, रीढ़ की हड्डी सहित लगभग सभी अंगों की पर्याप्त पुनर्जनन क्षमता के कारण एक ज़ेब्राफिश विकासात्मक जीवविज्ञानी को आकर्षित करती है।

माउंट सेमरू

समाचार –

- माउंट सेमेरू इंडोनेशिया के पूर्व में जावा में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
- ज्वालामुखी सबडक्शन जोन में स्थित है जहाँ इंडो–ऑस्ट्रेलिया प्लेट यूरेशिया प्लेट के नीचे रहती है।
- माउंट सेमेरू एक मिश्रित ज्वालामुखी (स्ट्रैटोवॉल्केनो) है। 1818 के बाद से, माउंट सेमेरू में लगभग 55 विस्फोट दर्ज किए गए हैं।

मिश्रित ज्वालामुखी (स्टटोवॉल्केनो) –

- मिश्रित–ज्वालामुखी को शंक्वाकार ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इसे कठोर लावा की कई परतों द्वारा बनाया गया है। मिश्रित–ज्वालामुखी का लावा अत्यधिक चिपचिपा होता है। यह दूर तक फैलने से पहले ठंडा एवं कठोर हो जाता है। इसके अलावा, मिश्रित–ज्वालामुखी में आवधिक अपक्षय विस्फोट होते हैं।
- मिश्रित–ज्वालामुखी से लावा मनुष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा नहीं है क्योंकि वे अत्यधिक चिपचिपा हैं। दूसरी ओर नीयरागोंगो विश्व का एकमात्र खतरनाक मिश्रित–ज्वालामुखी है क्योंकि इसकी मैग्मा असामान्य रूप से सिलिका में कम है जो लावा को काफी तरल बनाती है। इससे लावा की प्रवाह दर बढ़ जाती है।

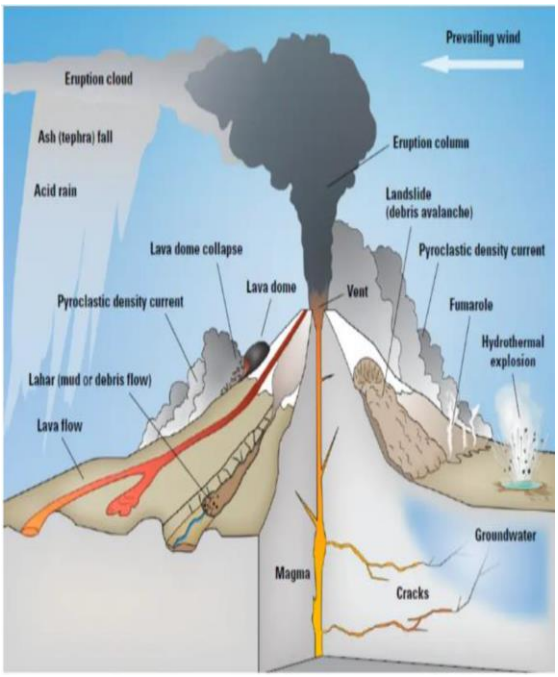

कोविड–19 मस्तिष्क में प्रवेश कर सकता हैं

समाचार –

- नया कोरोनावायरस नाक के माध्यम से लोगों के मस्तिष्क में प्रवेश कर सकता है।

जाँच के परिणाम –

- शोध में उल्लेख किया गया है कि SARS–CoV–2 न केवल श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, बल्कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) को भी प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप तंत्रिका संबंधी लक्षण जैसे कि गंध, स्वाद, सिरदर्द, थकान एवं मतली का अनुभव होता है।
- जर्मनी के शोधकर्ताओं ने कोविड–19 के कारण मृत 33 रोगियों (22 पुरुषों + 11 महिलाओं) नासोफैरनेक्स (गले का ऊपरी हिस्सा जो नाक गुहा से जुड़ता है तथा जो वायरल संक्रमण एवं प्रतिकृति का पहला संभावित स्थल होता है) की जांच की।
- शोधकर्ताओं ने SARS–CoV–2 RNA, वायरस की आनुवंशिक सामग्री एवं मस्तिष्क एवं नासोफरीनक्स में प्रोटीन की उपस्थिति को पाया।
- टीम ने घ्राण श्लेष्म परत के भीतर कुछ प्रकार की कोशिकाओं में SARS–CoV–2 स्पाइक प्रोटीन भी पाया, जहां यह मस्तिष्क में प्रवेश पाने के लिए एंडोथेलियल एवं तंत्रिका ऊतक की निकटता का लाभ उठा सकता है।
- कुछ रोगियों में, SARS–CoV–2 स्पाइक प्रोटीन न्यूरॉन्स के मार्करों को व्यक्त करने वाली कोशिकाओं में पाया गया था, जिससे यह परिणाम प्राप्त होता है कि घ्राण संवेदी न्यूरॉन्स के साथ ही मस्तिष्क क्षेत्रों के न्यूरॉन्स जो गंध एवं स्वाद संकेत प्राप्त करते हैं, भी संक्रमित हो सकते हैं।
- SARS–CoV–2 तंत्रिका तंत्र के अन्य क्षेत्रों में भी पाया गया था, जिसमें मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा (मस्तिष्क का प्राथमिक श्वसन एवं हृदय नियंत्रण केंद्र) शामिल है।

राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस

समाचार –

- प्रत्येक वर्ष, वर्ष 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात को हुए, भोपाल गैस त्रासदी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की याद में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
- जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई।
- मानव पर प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों एवं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।

उद्देश्य –

- औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन एवं नियंत्रण पर जागरूकता फैलाना
- औद्योगिक प्रक्रियाओं या मानवीय लापरवाही से उत्पन्न प्रदूषण को रोकना
- प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के महत्व के बारे में लोगों एवं उद्योगों को जागरूक करने के लिए भारतीय विधान द्वारा उठाए गए निवारक तरीकों से अवगत कराना जैसे कि –
  – जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974,
  – जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977,
  – वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981,
  – पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986,
  – पर्यावरण (संरक्षण) 1986 के नियम,
  – 1989 के खतरनाक रासायनिक नियमों का निर्माण,
  – भंडारण एवं आयात, खतरनाक सूक्ष्म जीवों का निर्माण, भंडारण, आयात, निर्यात एवं भंडारण,
  – आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीव या कोशिका नियम 1989,
  – रासायनिक दुर्घटनाएं (आपातकाल, योजना, तैयारी एवं प्रतिक्रिया) 1996 के नियम,
  – जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रबंधन) 1998 के नियम,
  – पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक निर्माण एवं 1999 के उपयोग के नियम,
  – ओजोन को हटाने वाले पदार्थ (विनियमन) 2000 के नियम,
  – 2000 का शोर प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम,
  – नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) 2000 के नियम,
  – बैटरियों (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) 2001 के नियम,
  – पर्यावरण प्रभाव आकलन 2006 की अधिसूचना,
  – राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010,
  – ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016,
  – खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं बाउन्ड्री आंदोलन) नियम 2016,
  – जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016,
  – प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016,
  – ई–वेस्ट (प्रबंधन) नियम 2016,
  – निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) –

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का गठन सितंबर, 1974 में जल (प्रदूषण एवं रोकथाम नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत किया गया था। इसके अलावा, CPCB को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत शक्तियां एवं कार्य सौंपे गए थे। यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

CPCB के कार्य –

- जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं रोक द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में धाराओं एवं कुओं की सफाई को बढ़ावा देना, एवं
- वायु की गुणवत्ता में सुधार करना एवं देश में वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना या रोकना।

वायु प्रदूषण के तथ्य –

- विश्व भर में दस में से नौ लोग सुरक्षित हवा में सांस नहीं लेते हैं।
- वायु प्रदूषण प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर 7 मिलियन लोगों की मृत्यू का कारण बनता है, जिनमें से 4 मिलियन लोग आंतरिक वायु प्रदूषण से मरते हैं।
- एक सूक्ष्म प्रदूषक (पीएम 2.5) इतना छोटा है कि यह फेफड़ों, हृदय एवं मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने के लिए बलगम झिल्ली एवं अन्य सुरक्षात्मक बाधाओं से गुजर सकता है।
- प्रमुख प्रदूषकों में कण पदार्थ, ईंधन के दहन से उत्पन्न ठोस एवं तरल बूंदों का मिश्रण, सड़क यातायात से ऊत्सर्जित नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उद्योगों एवं वाहन से हुए उत्सर्जन से प्रदूषकों के साथ सूर्य के प्रकाश की प्रतिक्रिया के कारण जमीनी स्तर पर ओजोन एवं सल्फर डाइऑक्साइड, एवं कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने से प्राप्त अदृश्य गैस, शामिल हैं।
- वायु प्रदूषण से बच्चे एवं बूढ़े व्यक्ति अत्यधिक प्रभावित होते हैं।
- जलवायु परिवर्तन के लिए वायु प्रदूषण भी जिम्मेदार है।

विश्व एड्स दिवस

समाचार –

- प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ताकि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम (एड्स) बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।
- यह रोग महामारी के कारण होता है जिसे ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी के कारण लोग असुरक्षित संक्रमण एवं बीमारियों के संपर्क में आ जाते हैं।
- यह दिवस सार्वजनिक एवं निजी भागीदारों के लिए एक अवसर है कि वे महामारी की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाएं एवं विष्व भर में एचआईवी/एड्स की रोकथाम, उपचार एवं देखभाल में प्रगति को प्रोत्साहित करें।

विषय –

- विश्व एड्स दिवस के लिए इस वर्ष की थीम 'एंडिंग द एचआईवी/एड्स एपीडेमिक – रिज़िलियंस एंड इम्पैक्ट' है।
- यह विषय एक अनुस्मारक भी है कि लोग किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे एचआईवी के उपचार एवं रोकथाम के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं को वितरित करने के लिए एक संयुक्त प्रयास करते हैं, जो जरूरतमंद हैं।

एचआईवी –

- यह महामारी रोग एचआईवी ऊतकों में पाया जाता है एवं यह रक्त, वीर्य, स्तन के दूध, आदि के माध्यम से प्रेषित होता है।

- यह रोग एक यौन संचारित रोग है एवं यह रक्त संचरण एवं अन्य चीजों के माध्यम से भी संचारित हो सकता है।
- एचआईवी के कई लक्षण हैं एवं उनमें से कुछ में जोड़ों का दर्द, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, वजन में कमी, कमजोरी, अन्य शामिल हैं।

दिवस का इतिहास –

- विश्व एड्स दिवस पहली बार 1987 में जेम्स डब्ल्यू. बुन एवं थॉमस नेट्टर द्वारा मनाया गया था, वे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन में एड्स पर वैश्विक कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक सूचना अधिकारी थे एवं उन्होंने डॉ. जोनाथन मान, एड्स पर वैश्विक कार्यक्रम के निदेशक को अपना विचार दिया।
- यह सुनने के बाद, डॉ. मान इस विचार से प्रभावित हुए एवं उन्होंने इसे अनुमोदित कर दिया एवं इस प्रकार, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर से मनाया जाने लगा।

विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

समाचार –

- 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDPD) के रूप में मनाया जाता है।
- इस दिवस को मनाने का उद्देश्य 2030 एजेंडा के मूल वादे – कोई पीछे ना छुट जाए, को पूर्ण करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को साकार करना है।

विषय –

- 2020 में, UN की थीम 'बिल्डिंग बैक बेटर – एक विकलांगता–समावेशी, सुलभ एवं टिकाऊ पोस्ट कोविड–19 वर्ल्ड' की ओर थी।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देने एवं समाज के सभी पहलुओं में विकलांगता के साथ लोगों की तत्काल जरूरतों का उत्तर देने के महत्व को रेखांकित करके इस विषय का समर्थन किया, खासकर कोविड–19 महामारी के दौरान।

इतिहास –

- 1992 में विकलांगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDPD) को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा समाज के सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एवं कल्याण को 'बढ़ावा देने' के संकल्प द्वारा घोषित किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA)

समाचार –

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स (IAIS) की सदस्यता प्राप्त की।

मुख्य विवरण –

- इस सदस्यता के साथ IFSCA की IAIS के वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच होगी एवं वे अन्य वैश्विक नियामकों के साथ विचारों एवं सूचनाओं का आदान–प्रदान करने में सक्षम होंगे।
- इससे GIFT सिटी में IFSC में एक जीवंत वैश्विक बीमा हब विकसित करने में मदद मिलेगी।
- वर्तमान में, 17 प्रमुख बीमा संस्थाएँ GIFT IFSC के अपतटीय बीमा एवं पुनर्बीमा व्यवसाय का संचालन कर रही हैं।
- यह सदस्यता वैश्विक बीमा संस्थानों के साथ IFSC को जोड़ने में एक लंबा रास्ता तय करेगी एवं अन्य वैश्विक केंद्रों के साथ वैश्विक बीमा व्यवसाय के संयुक्त विकास में IFSCA की सुविधा प्रदान करेगी।

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर (IAIS)

- 1994 में स्थापित, IAIS का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में 200 से अधिक न्यायालयों के बीमा पर्यवेक्षकों एवं नियामकों का एक स्वैच्छिक सदस्यता संगठन है, जिसमें विश्व का बीमा प्रीमियम का 97% हैं।
- यह बीमा क्षेत्र की देखरेख के लिए सिद्धांतों, मानकों एवं अन्य सहायक सामग्री के कार्यान्वयन में विकास एवं सहायता के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय मानक–सेटिंग निकाय है।
- अपनी सामूहिक विशेषज्ञता की मान्यता में, IAIS को जी 20 नेताओं एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय मानक निकायों द्वारा नियमित रूप से बुलाया जाता है।
- IAIS के कुछ प्रमुख सदस्य यूनाइटेड किंगडम – फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA), यूएसए – नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस कमिश्नर्स (NIAC), युएसए फेडरल इंश्योरेंस ऑफिस ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी (FIO), सिंगापुर–मॉनेटरी अथॉरिटी सिंगापुर (एमएएस), भारत–भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)हैं।

ग्रीन चारकोल हैकथॉन आयोजित

समाचार –

- NVVN (NTPC Vidyut Vyapar Nigam), NTPC Ltd (नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) की पूर्ण सहायक कंपनी ने ग्रीन चारकोल हैकाथॉन लॉन्च किया।

झलकियाँ –

- यह एक तकनीकी चुनौती है जिसका उद्देश्य एनवीवीएन एवं ईईएसएल (ऊर्जा दक्षता सेवा कं, लिमिटेड–एक 100% राज्य के स्वामित्व वाली ऊर्जा सेवा कंपनी) के तकनीकी विकास को जल्दी से बढ़ावा देना है।
- इस घटना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी अंतर को पाटने के लिए अभिनव भारतीय सोच का उपयोग करना है। इसके मुख्य लक्ष्य हैं –
  – खेत की आग को खत्म करके हवा को साफ करें एवं कृषि अवशेषों से अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करें।
  – स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना।
  – किसानों की आय को बढ़ाना।
- अंतिम लक्ष्य देश के कार्बन पदचिह्न को कम करना है।

- हैकाथॉन के अंत में, आयोजकों को एक आर्थिक एवं व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य मशीन का प्रस्ताव करने की उम्मीद है जो कृषि अवशेषों को उत्सर्जन के बिना लकड़ी का कोयला में बदल सकती है। इससे किसानों एवं पर्यावरण को लाभ होने की उम्मीद है।

डिएम

समाचार –

- फेसबुक–समर्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी लिब्रा को 'Diem' के रूप में इस बात पर जोर दिया गया है कि परियोजना को 'संगठनात्मक स्वतंत्रता' पर बल देकर नियामक अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।
- डियम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है 'दिन', डायम एक स्थिर सिक्का है।

विवरण –

- लिब्रा प्रोजेक्ट चलाने वाली स्वतंत्र संस्था, लिब्रा एसोसिएशन का भी नाम बदलकर डियम एसोसिएशन रखा जाएगा।
- पारंपरिक सरकार द्वारा संचालित वित्तीय प्रणालियों को खतरा होने की संभावना के कारण तुला को आलोचना मिली, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिरता एवं गोपनीयता की धमकी हो सकती है।
- अन्य क्रिप्टोकरंसीज के विपरीत, डियम को अनुमति ब्लॉकचैन का उपयोग करना है। अन्य क्रिप्टोकरेंसी की अधिकांश अनुमतिहीन ब्लॉकचैन का उपयोग करते हैं।

डियम पर प्रतिक्रिया –

- यूरोपीय संघ ने अभी तक स्थिर सिक्कों को अपने क्षेत्र में काम करने की अनुमति नहीं दी है। यूरोपीय संघ के अनुसार, यह राज्यों की मौद्रिक संप्रभुता के लिए खतरा हो सकता है।
- अमेरिकी मुद्रा को लॉन्च करने से फेसबुक को रोकना चाहता है क्योंकि क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में एक स्पष्ट नियामक ढांचे का अभाव है।

स्टेबल कॉईन –

- स्टेबल कॉईन क्रिप्टोकरेंसी हैं। स्टेबल कॉईन में एकमात्र अंतर यह है कि ये क्रिप्टोकरेंसी रिजर्व एसेट द्वारा समर्थित होते हैं। उनका बाजार मूल्य कुछ बाहरी संदर्भ पर निर्भर होता है।
- उदाहरण के लिए, इसे सोने के मूल्य, अमेरिकी डॉलर या लॉचर द्वारा रखी गई संपत्ति पर आंका जा सकता है।
- स्टेबल कॉईन संदर्भ संपत्ति की खरीद एवं बिक्री के एल्गोरिथ्म तंत्र के माध्यम से अपनी मूल्य स्थिरता प्राप्त करते हैं।

भारतीय नौसेना दिवस –

समाचार –

- प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय नौसेना दिवस 'इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एवं कोहेसिव' विषय पर मनाया गया।

इतिहास –

- 1971 में भारत–पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर हमले की याद में प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन, कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के हमले ने पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बल की अंतिम जीत में योगदान दिया।
- 3 दिसंबर, 1971 की शाम को भारतीय हवाई ठिकानों पर पाकिस्तानी हमले के बाद, 25 वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को तीन मिसाइल नौकाओं –निराघाट, वीर एवं निपात को कराची की ओर अधिकतम गति से भेजने का आदेश दिया गया था।
- 4 दिसंबर की आधी रात से पहले, नौसेना की मिसाइल नौकाओं ने सफल हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तानी विध्वंसक खैबर, माइनस्वीपर मुहाफिज एवं एमवी वीनस चैलेंजर के साथ–साथ कियारी तेल क्षेत्र का विनाश हुआ।
- कराची पर 7 एवं 8 दिसंबर को पश्चिम से फिर हमला किया गया। INS विनाश ने चार मिसाइलें दागीं, जिससे MV Gulf Star, MV को नुकसान पहुंचा।

ऑपरेशन ट्राइडेंट –

- ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर की रात में शुरू किया गया था। हमले के दौरान भारतीय नौसेना ने कराची स्थित पाकिस्तान नौसेना मुख्यालय में ईंधन भंडारण टैंकरों को तबाह कर दिया।
- भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौकाओं में से 4 को भी डुबो दिया एवं 500 पाकिस्तानी नौसेना को मार डाला। इसमें माईनस्वीपर शामिल था।
- 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पहली बार भारत ने एंटीशिप मिसाइल की तैनाती की एवं ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद ऑपरेशन पायथन किया गया।

ऑपरेशन पायथन –

- ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान पहले हमले के बाद, पाकिस्तान नौसेना ने व्यापारी जहाजों के साथ घुलमिलकर भारतीय नौसेना को बाहर करने का प्रयास किया। ऑपरेशन पायथन पाकिस्तानी नौसेना के इस कदम का मुकाबला करने के लिए शुरू किया गया था।

महत्वपूर्ण जानकारी –

- इससे पहले ब्रिटिश शासन के दौरान, रॉयल नेवी के ट्राफलगर दिवस के साथ अक्टूबर के महीने में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता था। ट्राफलगर दिवस 21 अक्टूबर को पड़ता है।

मलयन विशालकाय गिलहरी (मलयन जॉईंट स्क्विरल)

समाचार –

- एक बड़ी वृक्ष गिलहरी जिसे 'वन स्वास्थ्य संकेतक प्रजाति' माना जाता है, वह लुप्त हो रही है एवं इस सदी के मध्य तक भारत के पूर्वोत्तर के जंगलों में नहीं पाई जा सकती है, जिसकी यह मूल निवासी हैं।

विवरण –

- जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अनुमान लगाया है कि 2050 तक भारत में मलयन विशालकाय गिलहरी (रतुफा बाइकलर) की संख्या 90 प्रतिशत तक गिर सकती है, एवं यदि जरूरी कदम नहीं उठाए गए, तो बाद के दशकों में देश में प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं।

- मलयन विशालकाय गिलहरी विश्व की सबसे बड़ी गिलहरी प्रजाति है जिसकी उपरी भाग गहरा, नीचे के भाग पीले, तथा एक लंबी झबरीली पुँछ होती है तथा यह पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय एवं नागालैंड में पाई जाती है।
- भारत तीन विशाल गिलहरी प्रजातियों का घर है, अन्य दो – भारतीय विशालकाय गिलहरी और घड़ियाल विशालकाय गिलहरी – प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती हैं।
- निशाचर उड़ने वाली गिलहरियों के विपरीत, विशालकाय गिलहरी दिनचर होती है, लेकिन उड़ने वाली गिलहरीयों की तरह वानस्पितक एवं शाकाहारी होती है।
- मलयन विशालकाय गिलहरी दक्षिणी चीन, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बर्मा, मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा एवं जावा में पाई जाती है।
- यह ज्यादातर सदाबहार और अर्धवृत्ताकार जंगलों में पाई जाती है, जो मैदानी इलाकों से लेकर समुद्र तल से 50 मीटर से 1,500 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
- भारत में, प्रजातियों की आबादी का लगभग 20% 1,500 मीटर एवं 2,700 मीटर के बीच ऊंचाई पर पाया जाता है, बाकि मैदानों में 1,500 मीटर तक की ऊँचाई पर रहती हैं।
- एशिया में लगभग 1.84 लाख वर्ग किमी में गिलहरी की रेंज भारत में लगभग 8.5 प्रतिशत (15,635 वर्ग किमी) है। प्रजातियों को IUCN की 2016 की सूची में 'नियर थ्रेटेंड' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, एवं यह भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है।
- पिछले दो दशकों में भारत में गिलहरी की आबादी में 30 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- जबकि पूर्वोत्तर में वन क्षेत्र 1987 से 2013 तक 7,172 वर्ग किमी बढ़ा, दो वर्षों में इस क्षेत्र ने 628 वर्ग किमी जंगल खो दिए।

खतरा –

- मलयन विशालकाय गिलहरी एवं उसके निवास स्थान वनों की कटाई, जंगलों के विखंडन, फसल की खेती तथा भोजन की अधिक फसल, वन्यजीवों के अवैध व्यापार एवं उपभोग के लिए शिकार से खतरे में हैं। पूर्वोत्तर के कई इलाकों में झुम की खेती इनके आवास को नष्ट करने में योगदान करती है।

पासेक्स अभ्यास (PASSEX)

समाचार –

- भारतीय नौसेना (IN) ने 4 से 5 दिसंबर 2020 तक पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में रूसी संघ नौसेना (RuFN) के साथ पासेक्स अभ्यास (PASSEX) किया।
- इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर–अनुकूलता को बढ़ाना है, दोनों नौसेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को समझना और उनमें सुधार लाना है। इसमें उन्नत सतह तथा पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास, हथियार चलाना, सीमेनशिप अभ्यास एवं हेलीकाप्टर संचालन शामिल होंगे।

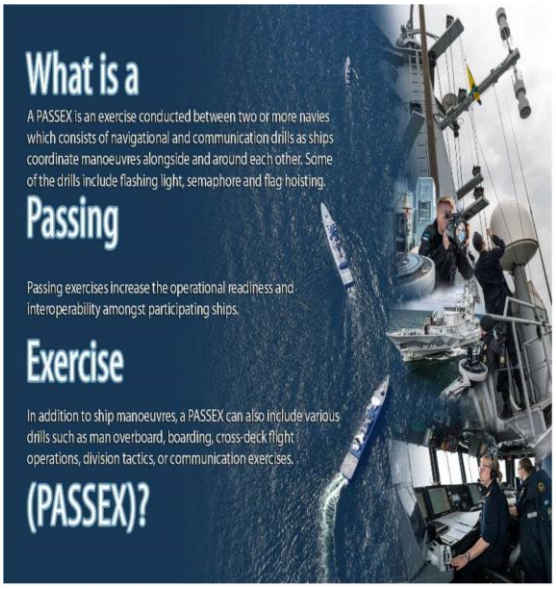

विवरण –

- इस अभ्यास में RuFN निर्देशित मिसाइल क्रूजर वैराग, बड़े एंटीसबमेरिन जहाज एवं मध्यम महासागर टैंकर की भागीदारी शामिल है।
- भारतीय नौसेना स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट शिवालिक, पनडुब्बी रोधी कार्वेट कदमत एवं हैलिकॉप्टरों के साथ इस अभ्यास में शामिल होगी।
- पासेक्स एक दूसरे के बंदरगाहों पर या समुद्र में एक यात्रा के दौरान यात्रा करते हुए, नियमित रूप से अनुकूल विदेशी नौसेना की इकाइयों के साथ भारतीय नौसेना द्वारा संचालित किया जाता है।

एसीबो दूरबीन –

समाचार –

- प्यूर्टो रिको की विशालकाय एर्सीबो दूरबीन, जो खगोल विज्ञान में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है, ढह गई है।
- एर्सीबो दूरबीन अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन की थी।
- प्यूर्टो रिको के एर्सीबो ऑब्जर्वेटरी में 305 मीटर टेलीस्कोप का इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म गिर गया है।

एर्सीबो दूरबीन –

- एर्सीबो दूरबीन का निर्माण पहली बार 1963 में किया गया था। दूरबीन पूरी विष्व में दूसरी सबसे बड़ी एकल–डिश दूरबीन है।

- एर्सीबो ने कई वर्षों तक ग्रहों एवं क्षुद्रग्रहों के अवलोकन में योगदान दिया।
- 1967 में, एर्सीबो ने यह पता लगाने में मदद की कि बुध ग्रह 59 दिनों में घूमता है। पहले यह सोचा गया था कि बुध ग्रह 88 दिनों में घूमता है।
- एर्सीबो दूरबीन के माध्यम से, पृथ्वी के निकट जाने वाले विशाल क्षुद्रग्रह देखे गए। दूरबीन अलौकिक जीवन की खोज का केंद्र बन गई।
- वैज्ञानिकों रसेल हुल्स एवं जोसेफ टेलर को 1993 में एर्सीबो दूरबीन वेधशाला पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- दूरबीन को जेम्स बॉन्ड की फिल्मों 'गोल्डन आई' एवं 'कॉन्टैक्ट' में दिखाया गया है।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस

समाचार –

- सशस्त्र सेना झंडा दिवस भारतीय सशस्त्र बल के कर्मियों के कल्याण के लिए भारत के लोगों से धन संग्रहण के लिए मनाया जाता है।
- यह 1949 से 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है।
- वर्षों से, भारत के सैनिकों, नाविकों एवं एयरमेन के सम्मान में इस दिन को मनाने की परंपरा बन गई है।

महत्व एवं उद्देश्य –

- झंडा दिवस मुख्य रूप से तीन बुनियादी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मनाया जाता है।
- युद्ध हताहतों का पुनर्वास
- सेवारत कर्मियों एवं उनके परिवारों का कल्याण
- पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों का पुनर्वास एवं कल्याण
- सशस्त्र सेना झंडा दिवस स्मरणोत्सव एवं झंडे के वितरण के माध्यम से धन का संग्रह
- यह भारतीयों के लिए भारत के वर्तमान एवं अनुभवी सैन्य कर्मियों के प्रति अपनी कृतज्ञता एवं प्रशंसा व्यक्त करने एवं देश की सेवा में मरने वालों को स्वीकार करने का समय है।

झंडा दिवस को"ा –

- रक्षा मंत्री समिति द्वारा मूल झंडा दिवस 1949 में स्थापित किया गया था। 1993 में, भारत के रक्षा मंत्रालय ने संबंधित कल्याण निधियों को एक सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में समेकित किया। उन निधियों में शामिल हैं – युद्धग्रस्त, युद्ध विकलांग एवं अन्य भूतपूर्व सैनिकों / सेवारत कार्मिकों के लिए विशेष कोष, झंडा दिवस कोष, सेंट डंस्टन्स (भारत) एवं केंद्रीय सैनिक बोर्ड कोष, भारतीय गोरखा पूर्व सैनिकों का कल्याण कोष।

आयुष उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

समाचार –

- आयुष निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य, उद्योग एवं आयुष मंत्रालयों ने निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया है।
- आयुष – आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय को भारत में स्वदेशी वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों के विकास, अनुसंधान एवं प्रसार के साथ रखा गया है।

उद्देश्य –

- भारत एवं विदेशों से बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए आयुष क्षेत्र में व्यापार एवं वाणिज्य में तेजी से वृद्धि करने की आवश्यकता है, एवं उन लोगों की बड़ी संख्या की सेवा करने के लिए जो अब अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इन प्रणालियों की तलाश कर रहे हैं।

विवरण –

- प्रस्तावित AEPC को आयुष मंत्रालय में रखा जा सकता है।
- आयुष के लिए एचएस कोड का मानकीकरण शीघ्र किया जाएगा एवं आयुष उत्पादों के साथ–साथ सेवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को विकसित करने के लिए आयुष मंत्रालय भारतीय मानक ब्यूरो के साथ मिलकर काम करेगा।
- आयुष एवं आयुष उद्योग मंत्रालय सर्वोत्तम अभ्यास की पहचान करेगा एवं उन्हें जनता के बीच बढ़ावा देगा।
- आयुष उद्योग, आयुष उत्पादों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने के साथ–साथ मूल्य प्रतिस्पर्धी बनने के लिए काम करेगा एवं आयुष ब्रांड इंडिया गतिविधियों का पता लगाएगा।
- भारत एवं विदेशों से बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए आयुष क्षेत्र में कोविड–19 महामारी के कठिन समय के दौरान रोग प्रतिरोध एवं उपचार के लिए आयुष आधारित समाधान एवं आह्वान किया गया।
- आयुष प्रतिरक्षा एवं आयुर्वेद एवं योग के लिए कोविड–19 के लिए राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल समय पर हस्तक्षेप थे जो आबादी के बड़े वर्गों को राहत प्रदान करते थे।

चक्रवात निवार

समाचार –

- चक्रवात निवार तमिलनाडु एवं पुदुचेरी से टकराया।

चक्रवात –

- मौसम विज्ञान में, एक चक्रवात एक बड़े पैमाने पर वायु द्रव्यमान है जो कम वायुमंडलीय दबाव के एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है।
- चक्रवात की विशेषता आवक सर्पिल हवाओं से होती है जो कम दबाव के क्षेत्र में घूमती हैं।
- सबसे बड़े निम्न–दबाव प्रणाली ध्रुवीय भंवर (पोलर वोर्टाईसेस) हैं एवं बड़े पैमाने के उष्णकटिबंधियेत्तर चक्रवात हैं।

चक्रवात निवार –

- बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान निवार एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में गंभीर प्रभाव डाला।
- 2020 के उत्तर हिंद महासागर चक्रवात के मौसम का आठवाँ अवसाद एवं चौथा नामांकित तूफान, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण (इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन) में गड़बड़ी से उत्पन्न हुआ।

अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण (इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन) –

- इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन (ITCZ), जो कि मल्लाहों द्वारा अपने नीरस मौसम के कारण डोलड्रम्स के रूप में जाना जाता है, वह क्षेत्र है जहां उत्तर–पूर्व एवं दक्षिण–पूर्व व्यापार हवाएं परिवर्तित होती हैं। यह तापीय भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी को घेरता है, हालांकि इसकी विशिष्ट स्थिति मौसमी रूप से बदलती है। जब यह भौगोलिक भूमध्य रेखा के पास होता है, तो इसे निकट–भूमध्यरेखीय गर्त कहा जाता है।
- जहां ITCZ मानसून परिसंचरण के साथ विलय होता है, उसे कभी–कभी मानसून गर्त (ऑस्ट्रेलिया में एवं एशिया के कुछ हिस्सों में अधिक उपयोग में आने वाला शब्द) के रूप में संदर्भित किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार, 2020

समाचार –

- व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) ने 'इन्वेस्ट इंडिया' को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रमोशन अवार्ड 2020 का विजेता घोषित किया है।

झलकियाँ –

- पुरस्कार समारोह जिनेवा में UNCTAD मुख्यालय में हुआ।
- यह पुरस्कार विष्व की निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानता है एवं उन्हें मनाता है।
- मूल्यांकन UNCTAD द्वारा विष्व भर में 180 राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन पर आधारित था।
- UNCTAD ने 'इन्वेस्ट इंडिया' जैसे बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम वेबिनार सीरीज, इसके सोशल मीडिया एंगेजमेंट एवं फोकस कोविड–19 रिस्पॉन्स टीमों के बाद अच्छी प्रथाओं को उजागर किया।
- राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया ने भी UNCTAD के उच्च–स्तरीय विचार–मंथन सत्रों में निवेश प्रोत्साहन, सुविधा एवं अवधारण के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों एवं प्रथाओं का पालन किया है।
- यह पुरस्कार प्रधानमंत्री के भारत के पसंदीदा निवेश गंतव्य को ध्यान में रखते हुए एवं व्यापार करने में आसानी दोनों पर ध्यान केंद्रित करने का दस्तावेज है। यह सरकार के भीतर उत्कृष्टता लाने का शपथ–पत्र है।
- UNCTAD केंद्रीय एजेंसी है जो निवेश संवर्धन एजेंसियों के प्रदर्शन की निगरानी करती है एवं वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करती है। जर्मनी, दक्षिण कोरिया एवं सिंगापुर अतीत में पुरस्कार के कुछ विजेता रहे हैं।

वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020

समाचार –

- वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में भारत से रणजीतसिंह डिसाले को घोषित किया गया। यह पुरस्कार लंदन स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था एवं इसे यूनेस्को के साथ साझेदारी में दिया जाता है।

झलकियाँ –

- भारतीय ग्राम शिक्षक रंजीतसिंह डिसाले, जिन्होंने भारत के जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय, परतावेदी, सोलापुर, महाराष्ट्र में युवा लड़कियों के जीवन की संभावनाओं को बदल दिया, को यूनेस्को की साझेदारी में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया।
- मिस्टर डिसाले को 12,000 से अधिक नामांकन एवं विश्व भर के 140 से अधिक देशों के अनुप्रयोगों से चुना गया था।
- वैश्विक शिक्षक पुरस्कार की स्थापना एक असाधारण शिक्षक को मान्यता देने के लिए की गई थी, जिसने इस पेशे में उत्कृष्ट योगदान दिया है एवं साथ ही समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षकों पर भी प्रकाश डाला है।
- अतीत में, डिसाले को वर्ष 2016 के अभिनव शोधकर्ता के रूप में नामित किया गया था एवं उन्होंने सत्या नडेला की पुस्तक 'हिट रिफ्रेश' में छापा था।
- कक्षा की पाठ्यपुस्तकों का अपनी विद्यार्थियों की मातृभाषा में अनुवाद करने के लिए डिसाले ने गाँव की स्थानीय भाषा सीखी।
- उन्होंने छात्रों को ऑडियो कविताओं, वीडियो व्याख्यान, कहानियों एवं असाइनमेंट तक पहुंच प्रदान करने के लिए पाठ्यपुस्तकों पर अद्वितीय क्यूआर कोड बनाए, जिससे स्कूल की उपस्थिति में काफी सुधार हुआ। उनकी क्यूआर तकनीक अब पूरे भारत में अधिक व्यापक रूप से लागु हो रही है।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020

समाचार –

- प्रधानमंत्री ने वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2020 में उद्घाटन भाषण दिया।
- IMC 2020 का आयोजन दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एवं सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) द्वारा किया गया था।

लक्ष्य –

- आईएमसी 2020 का उद्देश्य 'आत्मनिर्भर भारत', 'डिजिटल समावेशीता', 'सतत विकास', उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देना है।
- इसका उद्देश्य विदेशी एवं स्थानीय निवेशों को चलाना, दूरसंचार एवं उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है।

विवरण –

- आईएमसी 2020 में विभिन्न मंत्रालयों, दूरसंचार सीईओ, वैश्विक सीईओ एवं 5 जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, साइबर–सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटी एवं ऑटोमेशन से भागीदारी देखी जाएगी।
- आईएमसी भारत एवं दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है।
- इस घटना को 'भारत के स्टार्ट–अप एवं प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अग्रणी मंच' माना जाता है।

सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) –

- COAI संपूर्ण भारत में मोबाइल नेटवर्क के आधुनिक संचार एवं सफल प्रसार के लिए 1995 में गठित एक पंजीकृत, गैर–सरकारी समाज है।
- COAI अब भारत की दूरसंचार उद्योग की आधिकारिक आवाज है एवं इसका उद्देश्य भारतीय दूरसंचार उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को एक आम सहमति प्रस्तुत करना है।
- COAI के मुख्य सदस्य हैं – भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, रिलायंस जियो इंफोकॉम

लाल सागर में कछुए

समाचार –

- लाल सागर में कछुए की आबादी में मानव जाति के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन से हुई समुद्र के तापमान में वृद्धि के कारण मादाओं की संख्या अत्यधिक हो सकती है।
- सऊदी अरब किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने प्रति पंद्रह मिनट का पांच महीने के आँकड़े एकत्र किये।

जाँच – परिणाम –

- लाल सागर समुद्री कछुओं की सात प्रजातियों में से पांच का घर है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, पुरुषों एवं महिलाओं की आबादी के 50:50 अनुपात को बनाए रखने के लिए, 29.2 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। इस तापमान से ऊपर, मादा कछुए की हैचिंग मुख्य रूप से होगी।
- अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि चयनित पांच स्थलों में से चार पर रेत का तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक था।

कछुओं का संरक्षण –

- विभिन्न कछुओं को IUCN द्वारा अलग–अलग वर्गीकृत किया गया है। लॉगरहेड एवं ग्रीन सी कछुओं को 'लुप्तप्राय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेदरबैक टर्टल एवं ओलिवर रिडले कछुओं को 'वल्नरेबल' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- नॉर्थवेस्ट अटलांटिक में लेदरबैक कछुए को 'लुप्तप्राय (एनडेंज्रड)' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ग्रीन टर्टल, केम्प के रिडले कछुए एवं हॉक्सबिल कछुए को 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय(क्रिटीकली एंडेंज्रड)' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। IUCN के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में इनमें से 80% कछुए मारे गए हैं।

भारत में कछुओं का संरक्षण –

- भारत में, ग्रीन टर्टल एवं हॉक्सबिल कछुए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध हैं।
- कछुओं को जैव विविधता संरक्षण एवं गंगा कायाकल्प कार्यक्रम के तहत भी संरक्षित किया जाता है।
- भारत में कछुओं की पांच प्रजातियां हैं। वे ओलिव रिडले, लॉगरहेड, लेदरबैक, ग्रीन टर्टल, हॉक्सबिल हैं।
- प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है।

यूनेस्को की विश्व धरोहर शहर

समाचार –

- मध्य प्रदेश के ओरछा एवं ग्वालियर शहरों को यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO), संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी, जिसका उद्देश्य शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति एवं सुरक्षा, विज्ञान, एवं संस्कृति को बढ़ावा देना है।

ओरछा –

- यह शहर अपने महलों एवं मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं 16 वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी।
- शहर में प्रसिद्ध स्थान जहाँगीर महल, राज महल, राय प्रवीण महल, राम राजा मंदिर एवं लक्ष्मी नारायण मंदिर हैं।
- शहर को विश्व धरोहर शहर की सूची में शामिल किए जाने के बाद, गुजरी महल, मानसिंह महल एवं सहस्त्र बाहु मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थलों का रासायनिक उपचार किया जाएगा।
- यह इन स्थानों में कला को एवं अधिक दृश्यमान बनाने के लिए किया जाना है।
- साथ ही, भारतीय परंपराओं के अनुसार पर्यटकों का स्वागत करने के लिए इन स्थानों पर गार्ड तैनात किए जाने हैं।

ग्वालियर –

- ग्वालियर शहर अपने मंदिरों एवं महलों के लिए जाना जाता है।
- ग्वालियर किले को पवित्र जैन मूर्तियों के साथ घुमावदार सड़क के माध्यम से पहुँचा जाता है एवं एक बलुआ पत्थर के पठार पर स्थित है।
- यह अब एक पुरातात्विक संग्रहालय है जिसमें 15 वीं शताब्दी की ऊंची दीवारें हैं।
- ग्वालियर शहर 9 वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था एवं राजवंश, बघेल कछवाहो, तोमर एवं सिंधिया द्वारा शासित था।

विश्व विरासत स्थल –

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा प्रशासित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कानूनी संरक्षण के साथ एक विश्व विरासत स्थल या क्षेत्र है।
- विश्व धरोहर स्थलों को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या अन्य प्रकार के महत्व के लिए नामित किया गया है।

- स्थलों को 'मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य के रूप में मानी जाने वाली विष्व भर की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत' के रूप में शामिल किया गया है।
- चयनित होने के लिए, विश्व धरोहर स्थल का किसी भी तरह का अनूठा लैंडमार्क होना चाहिए जो भौगोलिक एवं ऐतिहासिक रूप से पहचान योग्य हो एवं जिसका विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व हो।
- उदाहरण के लिए, विश्व धरोहर स्थल प्राचीन खंडहर या ऐतिहासिक संरचनाएं, इमारतें, शहर, रेगिस्तान, जंगल, द्वीप, झील, स्मारक, पहाड़ या जंगल के क्षेत्र हो सकते हैं।

इको–ब्रिज

समाचार –

- उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर वन प्रभाग ने हाल ही में सरीसृप एवं छोटे स्तनधारियों के लिए अपना पहला इको–ब्रिज बनाया है।

इको–ब्रिज क्या मायने रखते हैं? –

इको–डक्ट या इको–ब्रिज का उद्देश्य वन्यजीव कनेक्टिविटी को बढ़ाना है जो राजमार्गों या लॉगिंग के कारण बाधित हो सकते हैं। इनमें चंदवा पुल (आमतौर पर बंदरों, गिलहरियों एवं अन्य जंगली प्रजातियों के लिए), कंक्रीट अंडरपास या सुरंगें या पुल (आमतौर पर बड़े जानवरों के लिए) शामिल हैं। आमतौर पर, इन पुलों को क्षेत्र में इस प्रकार लगाया जाता है ताकि यह परिदृश्य के साथ एक सन्निहित रूप दे सके।

भारत में पहले पाँच पशु पुल –

- रणथंभौर वाइल्डलाइफ कॉरिडोर में गड़बड़ी से बचने के लिए पुलों की योजना बनाई गई है। पहले पांच पशु पुलों की योजना दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनाई गई है।
- ये पशु पुल मनुष्यों एवं जानवरों के मध्य होने वाले संघर्ष से बचने में मदद करेंगे।
- रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था।

आवश्यकता –

- भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार, भारत में पाँच से छह वर्षों में लगभग 50,000 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। साथ ही, कई राजमार्गों को चार लेन में अपग्रेड किया गया है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा प्रमुख पशु गलियारे काटे जाते हैं।
- वे कर्नाटक में नागरहोल टाइगर रिजर्व के माध्यम से राज्य राजमार्ग 33, असम में काजीरंगा–कार्बी आंगलोंग परिदृश्य के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग 37 हैं।
- इसलिए, उनके प्राकृतिक सहवास को बाधित होने से रोकने के लिए इन पशु मार्गों का निर्माण करना आवश्यक है।

इको–ब्रिज के बारे में –

- इको पुलों के निर्माण में माना जाने वाले दो मुख्य पहलू आकार एवं स्थान हैं। इन पुलों को पशुओं के आने–जाने पैटर्न के आधार पर बनाया जाना चाहिए।
- प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन की वैज्ञानिक दिव्या मुदप्पा ने नीलगिरी लंगुर एवं लॉयन–टेल्ड मकाक के लिए चंदवा पुल का निर्माण किया है। IUCN रेड लिस्ट ऑफ डेंजरस स्पीशीज़ की सूची में लॉयन–टेल्ड मकाक एवं नीलगिरी लंगुर शामिल हैं। लगभग छह पुलों का निर्माण तीन किलो मीटर तक फैला हुआ है।

मानव अधिकार दिवस

समाचार –

- मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
- मानवाधिकार नैतिक सिद्धांत या मानदंड हैं जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों का वर्णन करते हैं एवं नियमित रूप से नगरपालिका एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून में संरक्षित हैं।
- संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रों को 'सभी के लिए समान अवसर बनाने' के लिए प्रोत्साहित करता है एवं असमानता, बहिष्करण एवं भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करता है।

विषय –

- 'रिकवर बैटर – स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राईट्स' इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का विषय है।
- इसका उद्देश्य सभी हितधारकों एवं भागीदारों के साथ जुड़ना है एवं परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए लोगों को शामिल करना है।

विवरण –

- मानव अधिकार दिवस 1948 में लागू हुआ जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया।
- दिसंबर 1948 में, यूनेस्को यूनिवर्सल घोषणा करने वाली पहली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी थी।

मानव अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है?

- यह विष्व भर में मानव के लिए वास्तविक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विष्व भर में लोगों के सामाजिक एवं शारीरिक कल्याण में सुधार करना है। दिन निम्नलिखित कारणों से मनाया जाता है।
- विश्व में लोगों के बीच मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रयासों में सुधार।
- मानव अधिकारों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत एवं चर्चा करना।
- अल्पसंख्यकों, महिलाओं, गरीबों एवं विकलांगों को आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित करना।

अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस

समाचार –

- भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता लाने एवं इसे रोकने एवं इसे रोकने में कन्वेंशन की भूमिका के लिए 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है।

भ्रष्टाचार –

- भ्रष्टाचार को स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति या व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करने के लिए रिश्वतखोरी या सार्वजनिक पद या शक्ति के दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

विषय –

- अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार–निरोधक दिवस 2020 का विषय 'यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन' है।
- विषय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक के रूप में भ्रष्टाचार पर केंद्रित है।
- 2020 की थीम 2030 एजेंडा का समर्थन करना जारी रखेगी, थीम अपने अभियान में अधिक युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखती है।

इतिहास –

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर, 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया।
- विधानसभा ने भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता लाने एवं इसे रोकने में कन्वेंशन की भूमिका के बारे में 9 दिसंबर को विश्व भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में भी नामित किया।
- कन्वेंशन दिसंबर 2005 में लागू हुआ।

एवेरेस्ट पर्वत

समाचार –

- नेपाल एवं चीन के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से समुद्र तल से 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को प्रमाणित किया। यह 1954 से मान्यता प्राप्त की तुलना में 86 सेमी अधिक है।

मुद्दा –

- पहाड़ की ऊंचाई के बारे में राय पर दो देशों के बीच लंबे समय से मतभेद है।
- पर्वत की ऊँचाई – चीन द्वारा दावा किया गया 29,017 फीट (8,844 मीटर) एवं नेपाल के लिए 29,028 फीट (8,848 मीटर) है।
- नई ऊंचाई लगभग 29,031 फीट है, या नेपाल के पिछले दावे से लगभग 3 फीट अधिक है।
- वर्षों से, इस मुद्दे पर बहस चल रही है कि क्या इसे 'चट्टान की ऊंचाई' होना चाहिए, या उसमें बर्फ की परत की मोटाई को शामिल किया जाना चाहिए।

पहले का माप –

- इसे जीपीएस के साथ थियोडोलाइट्स एवं जंजीरों जैसे उपकरणों का उपयोग करके, 1954 में सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया गया था।
- चीन को छोड़कर, विष्व भर के सभी संदर्भों में 8,848 मीटर की ऊंचाई को स्वीकार किया गया है। माउंट एवरेस्ट नेपाल एवं चीन की सीमा से लगता है।
- 1999 में, एक अमेरिकी टीम ने ऊंचाई 29,035 फीट (लगभग 8,850 मीटर) रखी। यह सर्वेक्षण नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, यूएस द्वारा प्रायोजित किया गया था।

नया माप –

- अप्रैल 2015 के विनाशकारी भूकंप से पहले, नेपाल के सर्वेक्षण विभाग ने कभी माउंट एवरेस्ट को मापने का विचार नहीं किया था।
- लेकिन भूकंप ने वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर बहस छेड़ दी कि क्या इससे पहाड़ की ऊंचाई प्रभावित हुई है।
- सरकार ने बाद में घोषणा की कि वह 1954 के सर्वेक्षण के अनुसरण को जारी रखने के बजाय पहाड़ को फिर से मापेगी।
- न्यूजीलैंड, जो पहाड़ पर नेपाल के साथ एक बंधन साझा करता है, तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- मई 2019 में, न्यूजीलैंड सरकार ने नेपाल के सर्वेक्षण विभाग (नापी विभाग) को एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट एवं प्रशिक्षित तकनीशियनों का साथ प्रदान किया।

'गो फॉर जीरो' नीति

समाचार –

- ऑस्ट्रेलिया की 'गो फॉर जीरो' नीति ने देश को अपने कोविड–19 मामलों को नीचे लाने में मदद की।

विवरण –

- ऑस्ट्रेलिया की शून्य नीति के लिए गो एक गैर–लाभकारी थिंक टैंक है जिसे ग्राटन इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तावित किया गया था जो सरकार को सलाह देता है।
- नीति के तहत कोविड–19 के परीक्षण का विस्तार करने के अलावा, ऑस्ट्रेलिया ने संपर्क अनुरेखण एवं अनिवार्य अलगाव को भी बढ़ाया।
- सरकार ने क्वारंटाइन तोड़ने वाले यात्रियों के मुद्दे से निपटने के लिए एक क्यूआर कोडेड प्रणाली की शुरुआत की थी। इस प्रणाली ने संबंधित व्यक्ति को ट्रैक करने में मदद की।
- ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्यों जैसे विक्टोरिया ने भी लोगों की स्पॉट जाँच करने के लिए पुलिस तैनात की एवं अलगाव में रहने का निर्देश दिया।
- हॉट होटल या स्वास्थ्य होटल स्थापित किए गए थे। ये होटल रोगग्रस्त यात्रियों के लिए स्थापित होते हैं। इसने बिमार व्यक्तियों के समूहों के उद्भव को रोका।
- नीति के तहत ऑस्ट्रेलिया ने श्रमिकों एवं व्यवसायों का भी समर्थन किया।
- लोगों को नियोजित रखने के लिए एवं बेरोजगारी लाभ में वृद्धि करने के लिए रूपों को सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- जैसे ही सितंबर के महीने में कोविड –19 के मामले कम होने लगे, ऑस्ट्रेलिया ने तीखे तरीके से लॉकडाउन हटा लिया।

लक्षद्वीप को 100% जैविक घोषित किया गया

समाचार –

- केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने के लिए सिक्किम के बाद केंद्र शासित प्रदेश दूसरे स्थान पर है।

विवरण –

- केंद्र के परम्परागत कृषि विकास योजना (जैविक खेती सुधार कार्यक्रम) के तहत आवश्यक प्रमाणपत्र एवं घोषणाएँ प्राप्त करने के बाद प्रस्ताव को 26 अक्टूबर, 2020 को मंजूरी दी गई।
- लक्षद्वीप शारीरिक रूप से मुख्य भूमि से कटा हुआ है, पिछले 15 वर्षों से, इस क्षेत्र में कोई भी रसायन नहीं भेजा गया है, सिवाय दवाओं एवं कुछ सौंदर्य प्रसाधन।
- इससे लक्षद्वीप 100 फीसदी जैविक हो गया है।
- लक्षद्वीप प्रशासन ने औपचारिक रूप से घोषित किया कि उसका पूरा कृषि समुदाय जैविक इनपुट जैसे खाद, पोल्ट्री खाद, हरी पत्ती खाद का उपयोग कर जैविक कृषि रहा है।
- पौधों की सुरक्षा के लिए जैविक या जैविक तरीकों का पालन कर रहा था।
- कृषि के लिए सिंथेटिक रसायनों को चरणबद्ध तरीके से कम किया गया एवं 2005 तक पूर्णतः रोक दिया गया।

जैविक खेती –

- जैविक खेती फसल एवं पशुधन उत्पादन की एक विधि है जिसमें कीटनाशकों, उर्वरकों, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों, एंटीबायोटिक्स एवं वृद्धि हार्मोन का उपयोग नहीं किया जाता है।
- जैविक खेती से फसल के सड़ने एवं आवरण फसलों के उपयोग को बढ़ावा मिलता है, एवं संतुलित शिकार/शिकारी संबंधों को बढ़ावा मिलता है।
- जैविक अवशेषों एवं पोषक तत्वों को खेत में उत्पादित करके वापस मिट्टी में पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। खाद का उपयोग करके मृदा के कार्बनिक पदार्थ एवं उर्वरता को बनाए रखा जाता है।
- कनाडा के जैविक मानकों (2006) से जैविक उत्पादन के सामान्य सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल हैं –
  – पर्यावरण की रक्षा, मिट्टी के क्षरण एवं क्षरण को कम करना, प्रदूषण में कमी, जैविक उत्पादकता को अनुकूलित करना एवं स्वास्थ्य की सुदृढ़ स्थिति को बढ़ावा देना
  – मिट्टी के भीतर जैविक गतिविधि के लिए परिस्थितियों का अनुकूलन करके दीर्घकालिक मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना
  – प्रणाली के भीतर जैविक विविधता को बनाए रखना
  – उद्यम के भीतर सामग्री एवं संसाधनों को सबसे बड़ी सीमा तक पुर्नचक्रित करना
  – चौकस देखभाल प्रदान करते हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है एवं पशुधन की व्यवहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
  – जैविक उत्पादों को तैयार करते हैं, जैविक अखंडता को बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक उत्पादन के सभी चरणों में उत्पादों के महत्वपूर्ण गुण प्रसंस्करण एवं हैंडलिंग विधियों पर जोर देते हैं।
  – स्थानीय स्तर पर संगठित कृषि प्रणालियों में नवीकरणीय संसाधनों पर भरोसा।

लक्षद्वीप –

- लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं एवं यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है।
- यह एक एकल–जिला केंद्र शासित प्रदेश है एवं इसमें 12 एटोल, तीन रीफ्स, पाँच डूबे हुए तल एवं 10 आबाद द्वीप शामिल हैं।
- सभी द्वीप कोच्चि से 220–440 किमी दूर हैं।

महत्वपूर्ण जानकारी –

- 2000 में जैविक खेती नीति शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य था।
- सिक्किम 100% जैविक बनने वाला पहला राज्य था।

1000 खेलो इंडिया केंद्र

समाचार –

- देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 1000 खेलो इंडिया छोटे केंद्र शुरू करने की घोषणा की। मंत्रालय ने सेवानिवृत्त होने के बाद भी खिलाड़ियों एवं खेल समुदाय को प्रोत्साहित करने एवं समर्थन देने के लिए कई पहल की हैं।

विवरण –

- फिक्की द्वारा आयोजित 10 वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट, TURF 2020 को संबोधित करते हुए, खेल मंत्री ने देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्रों की घोषणा की।
- ये केंद्र सेवानिवृत्त खेल व्यक्तियों को देश की खेल संस्कृति को आकार देने में रोजगार या कुछ भूमिका पाने में मदद करेंगे।
- खेलो भारत एवं फिट इंडिया मूवमेंट जोरदार तरीके से चल रहे हैं।
- इन केंद्रों को या तो पिछले चैंपियन द्वारा अपने दम पर चलाया जाएगा या उन्हें कोच के रूप में चुना जाएगा।
- चुनें गए पूर्व खिलाड़ियों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है –
  – जिन लोगों ने किसी मान्यता प्राप्त एनएसएफ या एसोसिएशन के तहत मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है,
  – मान्यता प्राप्त एनएसएफ के खेलो इंडिया गेम्स / नेशनल चौंपियनशिप में पदक विजेता
  – यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक विजेता
  – राष्ट्रीय स्तर/केआईजी के प्रतिभागी
- जम्मू–कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लद्दाख से एनआईएस–प्रमाणित कोच भी पात्र होंगे।
- वित्तीय अनुदान में पारिश्रमिक, उपकरण, खेल किट, उपभोग्य सामग्रियों की खरीद एवं तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, साइकिलिंग, तलवारबाजी, हॉकी, जूडो, रोइंग, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती, फुटबॉल एवं पारंपरिक खेलो की प्रतियोगिताओं में भाग लेना शामिल होगा।

खेलो इंडिया –

- खेलो भारत कार्यक्रम को हमारे देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा बनाकर एवं एक महान खेल राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए भारत में खेल संस्कृति को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने के लिए पेश किया गया है।
- शक्तिशाली समिती द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकता वाले खेल विषयों में पहचाने जाने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्ष तक प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन (SMDS)

समाचार –

- सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन (सस्टेनेबल माऊँटेन डेवलपमेंट समिट – एसएमडीएस) का नौवां संस्करण देहरादून में आयोजित किया गया था।
- शिखर सम्मेलन कोविड–19 परिदृश्य एवं जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक लचीला एवं स्थायी पर्वत अर्थव्यवस्था की ओर जाने के रास्ते के निर्माण के समग्र उद्देश्य पर केंद्रित है।

विषय –

- इस वर्ष का विषय 'एक लचीली कोविड–19 पश्चात् पर्वत अर्थव्यवस्था – अनुकूलन, नवाचार एवं त्वरण के निर्माण के उभरते मार्ग' था, एवं यह भारतीय हिमालय में एक लचीले एवं टिकाऊ अर्थव्यवस्था की दिशा में पथ निर्माण के समग्र उद्देश्य पर केंद्रित है।

विवरण –

- इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव (आईएमआई) द्वारा आयोजित, चार दिवसीय शिखर सम्मेलन में प्रवासन, जल सुरक्षा, जलवायु लचीलापन एवं कृषि क्षेत्र के लिए अभिनव समाधान एवं भारतीय हिमालय में आपदा जोखिम में कमी जैसे मुद्दों पर विचार–विमर्श शामिल है।
- पहाड़ों एवं पहाड़ियों के लिए तत्काल ध्यान देने एवं प्रासंगिक बनाने के लिए प्रतिवर्ष 3–5 मुख्य विषयों को चर्चा एवं बहस के लिए लिया जाता है।
- इस अभ्यास से निकलने वाले निष्कर्ष एवं सिफारिशें IMI द्वारा बाद में कार्रवाई योग्य आउटपुट के लिए अपनाई जाती हैं।
- पहला संस्करण 2011 में नैनीताल में आयोजित किया गया था।

फिटनेस का डोज़ आधा घंटा रोज अभियान

समाचार –

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिटनेस का डोज़ आधा घंटा रोज अभियान के लिए भारत की सराहना की है।

विवरण –

- यह अभियान 1 दिसंबर को केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू द्वारा राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट के भाग के रूप में शुरू किया गया था।
- इस अभियान ने विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों का समर्थन प्राप्त किया है – बॉलीवुड, खिलाड़ीयों, लेखकों, डॉक्टरों, फिटनेस प्रभावकारों, अन्य, जिन्होंने भारतीयों से हर दिन उत्साहपूर्वक 30 मिनट की फिटनेस का मूल–मंत्र अनुसरण करने का आग्रह किया है।

अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस

समाचार –

- पर्वतीय जैव विविधता इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का विषय है, जिसे 11 दिसंबर को मनाया गया।
- दिवस का उद्देश्य पहाड़ों में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है।
- 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन की घोषणा की गई थी।
- यह दिवस, जीवन में पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने, पर्वतों के विकास में अवसरों एवं बाधाओं को उजागर करने एवं गठबंधन बनाने के लिए मनाया जाता है जिससे विष्व भर में पहाड़ के लोगों एवं वातावरण में सकारात्मक बदलाव लाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2020 का विषय पर्वतीय जैव विविधता है। इसका उद्देश्य पहाड़ों की समृद्ध जैव विविधता का उत्सव मनाना है एवं उनके खतरों का भी पता लगाना है।

पर्वतों का महत्व –

- विश्व की लगभग 15 फीसदी आबादी पर्वतों पर रहती है।
- विश्व के आधे जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट पहाड़ों पर हैं।
- वे मानव जीवन की आधी आबादी के रोजमर्रा जीवन के लिए मीठे पानी का स्रोत हैं।
- उनका संरक्षण सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है एवं सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 15 का हिस्सा है।

क्वांटम की डिस्ट्रीब्युशन (QKD) प्रौद्योगिकी

समाचार –

- डीआरडीओ ने सुरक्षित संचार दिखाने के लिए दो डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, डीआरडीएल एवं आरसीआई के बीच हैदराबाद में क्वांटम की डिस्ट्रीब्युशन (क्यूकेडी) तकनीक का परीक्षण किया।
- रक्षा एवं सामरिक एजेंसियों के लिए सुरक्षित संचार विष्व भर में महत्वपूर्ण है एवं समय–समय पर एन्क्रिप्शन कुंजी का वितरण इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

QKD तकनीक का विवरण –

- प्रौद्योगिकी सीएआईआर, बेंगलुरु एवं डीवाईएसएल–क्यूटी, मुंबई द्वारा विकसित की गई है।
- क्वांटम कम्युनिकेशन, टाईम–बिन क्वांटम की डिस्ट्रीब्युशन (QKD) योजना का उपयोग करके यथार्थवादी परिस्थितियों में किया गया था।
- 12 किमी रेंज एवं फाइबर ऑप्टिक चैनल पर 10dB क्षीणन पर तैनात सिस्टम के लिए ईव्सड्रॉपिंग के खिलाफ क्वांटम आधारित सुरक्षा को मान्य किया गया था।
- विध्रुवण प्रभाव के बिना फोटोन उत्पन्न करने के लिए कंटीन्युस वेव लेजर स्रोत का उपयोग किया गया था।
- सेटअप में नियत समय सटीकता पिकोसेकंड के आदेश की थी।
- सिंगल फोटॉन हिमस्खलन डिटेक्टर (एसपीएडी) फोटॉनों के आगमन को दर्ज करता है एवं केपीएस की श्रेणी में कम क्वांटम बिट त्रुटि दर के साथ कुंजी दर प्राप्त की गई थी।
- सॉफ्टवेयर डाटा अधिग्रहण, समय सिंक्रनाइजेशन, पोस्ट–प्रोसेसिंग, क्वांटम बिट त्रुटि दर निर्धारित करने एवं अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों को निकालने के लिए विकसित किया गया था।

महत्व –

- क्वांटम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्ट–अप एवं एसएमई को सक्षम करने के लिए डीआरडीओ में किए जा रहे काम का उपयोग किया जाएगा।
- यह मानकों एवं क्रिप्टो नीतियों को परिभाषित करने का काम करेगा जो वर्तमान एवं भविष्य की सैन्य क्रिप्टोग्राफिक प्रणालियों के लिए अधिक सुरक्षित एवं व्यावहारिक कुंजी प्रबंधन के लिए एकीकृत सिफर नीति समिति (सीपीसी) ढांचे में क्यूकेडी प्रणाली का लाभ उठा सकती है।

एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर (ABTO) इंटरनेशनल कन्वेंशन

समाचार –

- केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स इंटरनेशनल कन्वेंशन का उद्घाटन किया।
- यह सम्मेलन पर्यटन मंत्रालय की साझेदारी में आयोजित किया जाना है।

भारत में पर्यटन –

- देश में पर्यटन उद्योग को विकसित करने के लिए स्वदेश दर्शन योजना एवं PRASAD योजना शुरू की गई।
- मध्य प्रदेश के सांची स्मारक में सिंहली भाषा में संकेत एवं सरवस्ती एवं सारनाथ में चीनी भाषा में संकेत भी लगाए गए हैं।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने स्मारकों से संबंधित एवं आने वाले दिनों में, स्मारकों की संख्या में काफी वृद्धि हो सकती है।
- पर्यटन मंत्रालय नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री (NIDHI) के तहत आवास इकाइयों को पंजीकृत करने की योजना बना रहा है, एक पोर्टल जो पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है। अब तक डाक के तहत 32000 से अधिक आवास इकाइयाँ पंजीकृत हैं।

अंतराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस

समाचार –

- 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया।
- वैश्विक महामारी को देखते हुए, इस वर्ष का विषय हेल्थ फॉर ऑल – प्रोटेक्ट एवरीवन है।
- यह दिवस मल्टीस्टेकहोल्डर भागीदारों के साथ मजबूत एवं लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों एवं सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए एक संकल्प आग्रह देशों का समर्थन किया – यह विचार कि हर किसी को अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक प्राथमिकता के रूप में, हर जगह गुणवत्तापूर्ण, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच होनी चाहिए।
- 12 दिसंबर 2017 को, संयुक्त राष्ट्र ने 72/138 संकल्प द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस (यूएचसी दिवस) के रूप में घोषित किया।

HD106906 b

समाचार –

- एक विचित्र एक्सोप्लैनेट, जिसने 333 प्रकाश वर्ष दूर एक दोहरे तारे की परिक्रमा की, ने खगोलविदों की रुचि को जगा दिया है। ग्रह का विषम व्यवहार हमारे अपने रहस्यमय ग्रह नौ के बारे में सुराग प्रदान करता है।

प्लैनेट नाइन क्या है?

- प्लैनेट नाइन हमारे अपने सौर मंडल में एक मायावी, दूर का ग्रह है।
- हालांकि इसे अभी तक देखा नहीं गया है, पिछले कुछ वर्षों में अध्ययनों की एक श्रृंखला द्वारा इसकी भविष्यवाणी की गई है, एवं खगोलविदों द्वारा 'पृष्ठ दृष्टि में छिपने' के रूप में वर्णित किया गया है।
- यदि यह मौजूद है, तो प्लैनेट नाइन पृथ्वी से 10 गुना बड़े पैमाने का होगा।
- प्लेनेट नाइन के साथ नए एक्सोप्लैनेट की तुलना क्यों की जा रही है?

- दोनों ग्रह (ग्रह नाइन वास्तविक है) अपने संबंधित तारकीय प्रणालियों में बहुत दूर रहते हैं। दोनों अपने–अपने सितारों को अत्यधिक झुकाव पर परिक्रमा करते हैं एवं दोनों बड़े पैमाने पर अपने क्षेत्रों में अन्य वस्तुओं के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त हैं।
- एक हालिया शोध पत्र के लेखकों ने जांच की कि HD106906 b अपने तारे से इतनी दूरी तक कैसे पहुंच सकता है, एवं सवाल उठाया कि क्या प्लेनेट नाईन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है।

हस्तशिल्प एवं जीआई खिलौने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर) से मुक्त

समाचार –

- केंद्र ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से हैंडीक्राफ्ट एवं जियोग्राफिकल इंडिकेशन खिलौनों को छूट दी है।
- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2020 में इस छूट का उल्लेख किया।
- स्वदेशी खिलौनों के उत्पादन एवं बिक्री तथा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है।
- खिलौनों के मानकीकरण एवं गुणवत्ता के पालन के लिए विभाग द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया गया है। यह आदेश अगले वर्ष पहली जनवरी से लागू होगा।
- इस आदेश का उद्देश्य केंद्र, राज्यों एवं हितधारकों के समन्वित प्रयासों को आगे लाना है ताकि स्वदेशी खिलौनों की गुणवत्ता मानकों को प्राथमिकता के रूप में रखते हुए खिलौनों की दृष्टि से टीम को बढ़ावा दिया जा सके।

जीआई –

- एक भौगोलिक संकेत (जीओग्राफिकल टैग – जीआई) एक संकेत है जो उन उत्पादों पर उपयोग किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है।
- जीआई किसी दिए गए स्थान पर उत्पन्न होने वाले उत्पाद की पहचान का चिन्ह है।

वल्लभभाई झावेरभाई पटेल

समाचार –

- 15 दिसंबर को उनकी 70 वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्र सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देता है।

वल्लभभाई पटेल –

- वल्लभभाई झावेरभाई पटेल (31 अक्टूबर 1875 – 15 दिसंबर 1950), सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे।
- उन्होंने भारत के पहले उप–प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।
- वह एक भारतीय बैरिस्टर थे, एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई थी।
- उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण एवं 1947 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया।
- पटेल का जन्म नडियाद जिला खेड़ा में हुआ था एवं उनका जन्म गुजरात राज्य के ग्रामीण इलाके में हुआ था। वे एक सफल वकील थे।
- उन्होंने बाद में ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा में गुजरात में खेड़ा, बोरसद एवं बारडोली से किसानों को संगठित किया, जो गुजरात के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए।
- उन्हें 1934 एवं 1937 में भारत छोड़ो आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए पार्टी का आयोजन करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49 वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
- नए स्वतंत्र देश में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उनकी प्रतिबद्धता कुल एवं समझौतावादी थी, जिससे उन्हें 'भारत का लौह पुरुष' नाम मिला।
- उन्हें आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना के लिए 'भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत' के रूप में भी याद किया जाता है।
- उन्हें 'भारत का एकीकरण करने वाला' भी कहा जाता है।
- उन्हें 31 अक्टूबर 2018 को, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विष्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, समर्पित की गई थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर (597 फीट) है।

मिरिस्टिका स्वेम्प ट्रीफ्रॉग

समाचार –

- मिरिस्टिका स्वेम्प ट्रीफ्रॉग का झुंड, पश्चिमी घाटों में पाई जाने वाली एक दुर्लभ एक दुर्लभ वानस्पतिक (एर्बोरियल) प्रजाति है, जो केरल के त्रिशूर में वाज़ाचल रिजर्व फॉरेस्ट के शेंकोटा गैप के उत्तर में पहली बार पाई गई थी।
- वैज्ञानिक नाम – मर्कुराना मिरिसिपालुस्ट्रिस

वानस्पतिक (एर्बोरियल) –

- जैविक संदर्भ में, एर्बोरियल एक वर्णनात्मक शब्द है जिसका उपयोग पेड़ों के लिए किया जाता है।
- वानस्पतिक पशुओं के उदाहरण गिलहरी, कोयल, प्राइमेट, स्लॉथ, मकड़ी बंदर, तेंदुए, गिरगिट, जेकॉस, चमगादड़, ट्री फ्रॉग, सांप, पक्षी, छिपकली, एवं पेड़ घोंघे हैं।

विवरण –

- मेंढक को पहली बार 2013 में कोल्लम जिले के अगस्त्यमलाई के पश्चिमी तलहटी में कुलथुपुझा रिजर्व फॉरेस्ट के पास अरिप्पा के मिरिस्टिका दलदल में देखा गया था।
- इन मेंढकों को देखा जाना दुर्लभ हैं क्योंकि वे अपने प्रजनन–काल के दौरान केवल कुछ सप्ताहों के लिए ही बाहर पेड़ों पर दिखाई देते हैं।
- इस मौसम के दौरान, दलदलों के निचले हिस्से से निकलकर पेड़ों के उपरी भागों पर नरों का एक बड़ा एकत्रीकरण होता है।
- वे अद्वितीय प्रजनन व्यवहार प्रर्दशित करते हैं।
- अन्य मेंढकों के विपरीत, प्रजनन का मौसम मानसून–पूर्व (मई) में शुरू होता है एवं जून में मानसून के पूर्णतः से सक्रिय होने से पहले समाप्त हो जाता है।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2020

समाचार –

- प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा संरक्षण दिवस को वर्तमान पीढ़ी के साथ–साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया।
- जलवायु परिवर्तन शमन की दिशा में काम करते हुए ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।

इतिहास –

- 1978 में, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA) नामक एक सरकारी निकाय बनाया गया जो ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
- PCRA ने प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो एवं डिजिटल माध्यमों जैसे मास मीडिया के माध्यम से कई अभियान चलाए हैं।
- 2001 में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, एक संवैधानिक निकाय, को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के ढांचे को विनियमित करने के लिए विकासशील रणनीतियों में सहायता के लिए बनाया गया था।
- संगठन का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा गहनता को कम करना है।
- यह ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के पक्ष में है।

दिवस का महत्व –

- कुशल तरीके से ऊर्जा का उपयोग भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे बचाने के लिए आवश्यक है। ऊर्जा के गैर–प्रतिपूर्ति योग्य स्रोतों की कम हो रही है जो विश्व भर में चिंता का एक प्रमुख कारण है।
- इसलिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को ऊर्जा संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके करने, ऊर्जा के अपव्यय को रोकने एवं ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- ऊर्जा विकास ब्यूरो (BEE) सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस दिशा में काम करता है। इसके कुछ प्रमुख कार्यों में शामिल हैं –
- ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना एवं सूचना का प्रसार करना।
- ऊर्जा उपयोग में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा कुशल प्रक्रियाओं, उपकरणों, उपकरणों एवं प्रणालियों को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा के कुशल उपयोग एवं इसके संरक्षण के महत्व पर शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करना।

नाजो एनिग्मा मशीन

समाचार –

- जर्मन गोताखोरों ने हाल ही में बाल्टिक सागर से एक एनिग्मा एन्क्रिप्शन मशीन डाली, जिसका उपयोग नाज़ियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोडित संदेश भेजने के लिए किया था।
- गोताखोरों ने सोनार उपकरणों की मदद से पुराने छुटे हुए मछली पकड़ने के जालों (जो समुद्री जीवों के हानिकारक हो सकते हैं) की खोज करते समय, मशीन की खोज की।

एनिग्मा –

- एनिग्मा एक एन्क्रिप्शन डिवाइस है जिसका इस्तेमाल जर्मन नाजियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गुप्त संदेशों को एनकोड करने के लिए किया था।
- इसे हाल ही में बाल्टिक सागर में गोताखोरों द्वारा खोजा गया।
- मशीन का आविष्कार आर्थर शेरेबियस ने प्रथम विश्व युद्ध के अंत के पास किया था।
- इन मशीनों के उपयोग ने मित्र देशों की सेनाओं के लिए जर्मन के कूट संदेशों को रोकना एवं डिकोड करना बहुत कठिन बना दिया।
- द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के पास, मित्र राष्ट्रों की शक्तियों को पहुँचने से रोकने के लिए जर्मनों ने इनमें से अधिकांश मशीनों को नष्ट कर दिया।

एनिग्मा कोड को कैसे हल किया गया –

- 1932 में, पोलिश क्रिप्टोएनालिस्टों ने एनिग्मा के पुराने संस्करण के कोड को डीकोड किया।
- उन्होंने समाधानों की खोज के लिए इलेक्ट्रो–मैकेनिकल मशीनों का निर्माण किया। पोलिश डिकोडिंग मशीन अंग्रेज गणितज्ञों के लिए 'बॉम्ब' मशीन विकसित करने का आधार थी।
- कोड को तोड़ने के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में बॉम्ब मशीन ने एनिग्मा द्वारा बनाए गए संदेश के ज्ञात हिस्सों का उपयोग किया।

प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (PMSSS)

समाचार –

- एआईसीटीई ने जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएस) के तहत रखरखाव भत्ते के रूप में 20,000 रुपये प्रति माह की किश्त जारी करने का फैसला किया है। ऑनलाइन पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्रों को समर्थन एवं सशक्त बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया।

पृष्ठभूमि –

- जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के युवाओं के बीच रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एवं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में कार्य के अवसर तैयार करने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था।
- इसके बाद से, प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (PMSSS) को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ATETE) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

PMSSS योजना –

- योजना के तहत, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के युवाओं को शैक्षणिक शुल्क एवं रखरखाव भत्ता छात्रवृत्ति के माध्यम से दो भागों में सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना का उद्देश्य जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख के युवाओं की क्षमता को विकसित करना, उन्हें सक्षम बनाना एवं उन्हें सामान्य पाठ्यक्रम में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सशक्त बनाना है।
- शैक्षणिक शुल्क का भुगतान उस संस्थान को किया जाता है जहां छात्र को एआईसीटीई द्वारा आयोजित ऑन–लाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद प्रवेश दिया जाता है।
- शैक्षणिक शुल्क में विभिन्न व्यावसायिक, चिकित्सा एवं अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए तय सीमा के अनुसार ट्यूशन शुल्क एवं अन्य घटक शामिल हैं।
- छात्रावास के आवास, मेस के खर्च, पुस्तकों एवं स्टेशनरी आदि के लिए व्यय को पूरा करने के लिए, लाभार्थी को एक लाख रुपये की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है एवं 10,000/– रुपये प्रतिमाह की किश्तों में सीधे छात्र के खाते में भुगतान किया जाता है।

एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (ABU)

समाचार –

- प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति को एशिया–पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया।

एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (ABU)

- 1964 में गठित ABU, एक गैर–लाभकारी, प्रसारण संगठनों का पेशेवर संघ है।
- ABU विश्व में सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है।
- ABU की भूमिका एशिया–प्रशांत क्षेत्र में प्रसारण के विकास एवं सदस्यों के सामूहिक हितों को बढ़ावा देने में मदद करना है।
- ABU की गतिविधियों में से एक एशियाविज़न कार्यक्रम है जो एशिया के 20 देशों में टेलीविजन स्टेशनों के बीच उपग्रह द्वारा समाचार फीड का आदान–प्रदान किया जाता है।
- ABU टेलीविजन एवं रेडियो प्रसारकों के सामूहिक हितों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है, एवं प्रसारकों के बीच क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- ABU का सचिवालय, अंगकासपुरी, कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित है।

इस्वातिनी साम्राज्य

समाचार –

- प्रधानमंत्री मोदी ने इस्वातिनी साम्राज्य के प्रधान मंत्री, एम्ब्रोस मंडवुलो देलमिनी के निधन पर दुख व्यक्त किया।

- दक्षिणी अफ्रीका में स्थित यह देश 2018 में अपने नाम बदले जाने से पूर्व स्वाजीलैंड द्वारा जाना जाता था।
- स्वाजी भाषा में 'इस्वातिनी' शब्द का अर्थ 'भूमि' से है।
- इस्वातिनी में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए एचआईवी/एड्स की सबसे अधिक व्यापकता दर सबसे कम जीवन प्रत्याशा के साथ है।

स्वाजीलैंड ने अपना नाम इस्वातिनी क्यों किया?

- अप्रैल 2018 में, स्वाजीलैंड के राजा मस्वाती III ने घोषणा की कि वे देश का नाम बदलकर 'किंगडम ऑफ इस्वातिनी' रख रहे हैं।
- नाम बदलने की घोषणा अंग्रेजी शासन से स्वाजी स्वतंत्रता के 50 वर्षों के पूर्ण होने जो उनके राजा का 50 वां जन्मदिवस भी था, पर की गई।
- इस नाम का सबसे प्रमुख उपयोग तब हुआ जब राजा ने 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान देश को इस नाम से पुकारा।

देशों के बदले हुए नाम –

- आधुनिक इतिहास में, अफ्रीका के विघटन के बाद, कई देशों ने खुद का नाम बदलने का फैसला किया। उदाहरण के लिए,
- मध्य अफ्रीका में न्यासालैंड का नाम बदलकर मलावी रखा गया
- बेचुआनालैंड 1966 में बोत्सवाना गणराज्य बना
- ऊपरी वोल्टा गणराज्य का नाम बदलकर बुर्किना फासो रखा गया
- गोल्ड कोस्ट घाना बन गया इत्यादि
- देश की सैन्य सत्ता द्वारा, 1989 में, बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया, एक कदम जिसमें देश को इसकी औपनिवेशिक विरासत से अलग होते हुए बर्मी भाषा के साथ संरेखित होते हुए देखा।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

समाचार –

- जल विज्ञान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (विश्व बैंक जल संसाधन मंत्रालय की समर्थित पहल) की समीक्षा की गई।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (NHP)

- एनएचपी को वर्ष 2016 में सुपूर्ण भारत आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों को 100% अनुदान के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू किया गया।
- परियोजना का उद्देश्य जल संसाधन सूचना की सीमा, विश्वसनीयता एवं पहुंच में सुधार करना एवं भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना है।
- एनएचपी कुशलतापूर्वक विश्वसनीय सूचना के अधिग्रहण की सुविधा प्रदान कर रहा है जो एक प्रभावी जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करेगी।
- परियोजना ने जल संसाधन निगरानी प्रणाली, जल संसाधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूआरआईएस), जल संसाधन संचालन एवं नियोजन प्रणालियों एवं संस्थागत क्षमता वृद्धि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- एनएचपी के तहत, जल संसाधन आँकड़ों का एक राष्ट्रव्यापी भंडार – एनडब्ल्यूआईसी स्थापित किया गया है। एनएचपी संपूर्ण भारत आधार पर रियल टाइम डेटा अधिग्रहण प्रणाली (आरटीडीएएस) की स्थापना पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- रियल टाइम डेटा अधिग्रहण प्रणाली, नियर रियल टाईम डेटा अधिग्रहण प्रणाली एवं मैनुअल डेटा अधिग्रहण स्टेशन एक दूसरे के पूरक होंगे एवं बेहतर जल संसाधन प्रबंधन की एक मजबूत नींव रखेंगे। ऐसे सभी डेटा वेब सक्षम इंडिया WRIS के माध्यम से उपलब्ध होंगे जो NHP के तहत अपस्केल किए जा रहे हैं।

रूसी एस–400 वायु रक्षा प्रणाली

समाचार –

- अंकारा द्वारा रूसी एस–400 वायु रक्षा प्रणालियों के अधिग्रहण पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाए हैं।

पृष्ठभूमि –

- अंकारा ने 2019 के मध्य में रूसी एस–400 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाईलों अधिग्रहण किया एवं कहा कि वे नाटो सहयोगियों के लिए कोई खतरा नहीं रखते हैं।
- वाशिंगटन लंबे समय से तुर्की पर प्रतिबंधों की धमकी दे रहा है एवं उसने पिछले वर्ष एक एफ–35 जेट कार्यक्रम से देश को हटा दिया।
- भारत ने अगले वर्ष की शुरुआत में एस–400 एयर डिफेंस सिस्टम की खेप लाने की तैयारी की।

एस–400

- एस–400 ट्रायम्फ, (नाटो इसे SA-21 ग्रोव्लर कहता हैं), एक मोबाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (SAM) है जिसे रूस द्वारा निर्मित किया गया है।
- यह विश्व में सबसे लंबी अवधि की आधुनिक रूप से लंबी दूरी के एसएएम (एमएलआर एसएएम) का सबसे खतरनाक रूप माना जाता है, जो यूएस–विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम (टीएचएएडी) से बहुत आगे का है।
- यह प्रणाली 30 किमी तक की ऊंचाई पर विमान, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी एवं बैलिस्टिक एवं क्रूज मिसाइलों सहित) 400 किमी की सीमा के भीतर, सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को गिरा सकती है।
- प्रणाली 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है एवं उनमें से छह को एक साथ निशाना बना सकती है।
- यह रूसी एसएएम की चौथी पीढ़ी एवं एस–200 एवं एस–300 के उत्तराधिकारी है।
- एस–400 का मिशन सेट एवं क्षमताएं प्रसिद्ध अमेरिकी पैट्रियट प्रणाली के लगभग बराबर हैं।
- एस–400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली एक बहुक्रिया राडार, स्वायत्त पहचान एवं लक्ष्यीकरण प्रणाली, विमान भेदी मिसाइल प्रणाली, लांचर एवं कमांड तथा नियंत्रण केंद्र को एकीकृत करता है।
- यह एक स्तरित रक्षा बनाने के लिए तीन प्रकार की मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है।
- एस–400 पिछले रूसी वायु रक्षा प्रणालियों की तुलना में दो गुना अधिक प्रभावी है एवं इसे पांच मिनट के भीतर तैनात किया जा सकता है।

- इसे वायु सेना, सेना एवं नौसेना की मौजूदा एवं भविष्य की वायु रक्षा इकाइयों में भी एकीकृत किया जा सकता है।
- पहला एस–400 सिस्टम 2007 में शुरू हुआ एवं मॉस्को की रक्षा के लिए तैनात है।
- इसे रूसी एवं सीरियाई नौसैनिकों एवं हवाई संपत्ति की सुरक्षा के लिए 2015 में सीरिया में तैनात किया गया था। रूस ने हाल ही में अनुमानित प्रायद्वीप पर रूस की स्थिति को मजबूत करने के लिए क्रीमिया में एस–400 इकाइयों को तैनात किया है।
- भारत के दृष्टिकोण से, चीन भी प्रणाली खरीद रहा है। 2015 में, बीजिंग ने प्रणाली की छह बटालियन खरीदने के लिए रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसकी डिलीवरी जनवरी 2018 में शुरू हुई थी।

हुनर हाट

समाचार –

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्वदेशी मास्टर कारीगरों के 23 वें हुनर हाट का उद्घाटन किया।

विवरण –

- राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, पंजाब, लद्दाख, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, जम्मू–कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल एवं अन्य स्थानों के मास्टर कारीगर एवं शिल्पकार लकड़ी, पीतल, बांस, कांच, कपड़े, कागज एवं मिट्टी से बने अपने स्वदेशी उत्पादों को लाए।
- हुनर हाट देश के प्रत्येक कोने से मास्टर कारीगरों एवं शिल्पकारों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक प्रभावी मंच साबित होता है।
- हुनर हाट विशेषज्ञता एवं प्रोत्साहन को आधार प्रदान करने के लिए सरकार का एक प्रभावी मिशन बन गया है।

हुनर हाट –

- हुनर हाट अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प एवं पारंपरिक उत्पादों की एक प्रदर्शनी है।
- इनका आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा USTTAD (पारंपरिक कला/शिल्प में विकास के लिए प्रशिक्षण एवं उन्नयन) योजना के तहत किया जाता है।
- USTTAD योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला एवं शिल्प की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देना एवं संरक्षित करना है।
- इन हाट का उद्देश्य कारीगरों, शिल्पकारों एवं पारंपरिक पाक विशेषज्ञों को बाजार में निवेश एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
- इसमें शिल्पकारों, बुनकरों एवं कारीगरों के कौशल को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है जो पहले से ही पारंपरिक पुश्तैनी काम में लगे हुए हैं।
- हुनर हाट कारीगरों, शिल्पकारों एवं मास्टरों के लिए सशक्तिकरण एक्सचेंज साबित हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस

समाचार –

- प्रति वर्ष, संयुक्त राष्ट्र एवं कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है।
- इस वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का दिवस, मानव गतिशीलता को फिर से संगठित करना, विषय के अंर्तगत मनाया गया है।
- 18 दिसंबर का दिवस चुना गया क्योंकि इस दिनाँक को, सभी प्रवासी कामगारों के अधिकारों एवं उनके परिवारों के सदस्यों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अपनाया गया था।

इतिहास –

- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाने का संकल्प 1990 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के दौरान सभी प्रवासी कामगारों के अधिकारों एवं उनके परिवारों के सदस्यों के संरक्षण के लिए अपनाया गया था।
- प्रवासियों द्वारा किए गए योगदान को उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस मनाया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व में लगभग 72 मिलियन प्रवासी हैं। इसमें 41 मिलियन आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति शामिल हैं।

गुरु तेग बहादुर

समाचार –

- प्रधानमंत्री ने शहीदी दिवस अर्थात 19 दिसंबर को गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर, 1621 में पैदा हुए थे एवं 1675 में दिल्ली में शहीद हुए थे।

गुरु तेग बहादुर –

- गुरु तेग बहादुर (1 अप्रैल 1621 – 19 दिसंबर 1675) सिख धर्म के दस गुरुओं में नौवें थे।
- वे गुरु हरगोबिंद साहिब के सबसे छोटे पुत्र थे।
- गुरु के रूप में उनका कार्यकाल 1665 से 1675 तक चला।
- उनके भजनों में से एक सौ पंद्रह गुरु ग्रंथ साहिब में हैं।
- औरंगजेब के आदेशों पर गुरु तेग बहादुर की हत्या के पीछे की मंशा को स्पष्ट करने वाले कई सबुत हैं।
- औरंगजेब द्वारा कश्मीरी पंडितों के धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ गुरु साहिब उठ खड़े हुए।
- औरंगजेब चाहता था कि पूरे विश्व में एक धर्म (इस्लाम) होना चाहिए ताकि धर्मों के बीच कोई टकराव न हो।
- मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर 1675 में सार्वजनिक रूप से मुगल शासकों की अवहेलना करने पर उन्हें सार्वजनिक रूप से मृत्यु–दंड दिया गया।
- दिल्ली में गुरुद्वारा सिस गंज साहिब एवं गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब उनके शरीर के निष्पादन एवं दाह संस्कार के स्थानों को चिह्नित करते हैं।

ई 20 ईंधन

समाचार –

- सरकार ने इथेनॉल जैसे हरित ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ई 20 ईंधन को अपनाने के लिए सार्वजनिक निविदाओं को आमंत्रित किया है। ई 20 ईंधन का अर्थ मोटर वाहन ईंधन के रूप में पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल का मिश्रण करना होता है।

महत्व –

- इथेनॉल जैसे हरित ईंधन को बढ़ावा देने से 8 लाख करोड़ रूपये के कच्चे आयात निर्भरता को कम करने में मदद मिलती है।
- इस कदम से तेल आयात बिल को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी एवं ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी।
- यह कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करेगा।

विवरण –

- इथेनॉल एवं गैसोलीन के मिश्रण में इथेनॉल के प्रतिशत के लिए वाहन की संगतता को वाहन निर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा एवं वही वाहन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला स्टिकर लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा।

आगे को राह –

- सरकार अगले पांच वर्षों में इथेनॉल अर्थव्यवस्था को वर्तमान में 22,000 करोड़ रुपये से 2 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने की इच्छा रखती है।

हरित ईंधन –

- जिसे जैव ईंधन के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का ईंधन है जो पौधे एवं पशु प्रदार्थो से आसवित करके पाया है, जिसका व्यापक रूप से उपयोग जीवाश्म ईंधन की तुलना में पर्यावरण के अधिक अनुकूल है जो वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा स्त्रोत हैं।
- जैव ईंधन के मूल रूपों को बनाने की फसलों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है – चीनी उत्पादन एवं तेल उत्पादन।
- चीनी एवं स्टार्च उत्पादक फसलें, जैसे कि गन्ना या मकई, इथेनॉल बनाने के लिए किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से उपयोग की जाती हैं। तेल उत्पादक पौधे, तेल के जीवाश्म स्रोतों की तरह बहुत अधिक उपयोग किए जा सकते हैं, उनसे डीजल बनता हैं जिन्हें कारों में उपयोग किया जा सकता है या उन्हें आगे बायोडीजल बनने के लिए संसाधित किया जा सकता है।
- तकनीकी नवाचारों ने उन्नत जैव ईंधन के क्षेत्रों का निर्माण किया है, जो गैर–खाद्य स्रोतों एवं ऊर्जा के रूप में तेजी से नवीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लैंडफिल सामग्री, साथ ही लकड़ी एवं अखाद्य पौधों के हिस्सों को हरित ईंधन में परिवर्तित करके, हम न केवल जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कटौती कर सकते हैं, बल्कि प्रभावी रूप से भारी मात्रा में कचरे का भी पुर्नचक्रण करते हैं।
- ईंधन के इस नए रूप को हरित ईंधन कहते है, क्योंकि यह हरे शैवाल से निकलता है। शैवाल, जिसे अक्सर पानी में देखा जाता है, एक छोटा पौधा है जिसकी विकास दर तेज होती है। ईंधन के रूप में इसकी उपयोगिता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि इसमें एक उच्च तेलीय सामग्री होती है जिसे अन्य तेल उत्पादक फसलों की तरह संसाधित किया जा सकता है।

चांग 5

समाचार –

- 44 वर्षों में पहली बार, चीन का चांग 5 चंद्र अभियान बाद चंद्रमा से पहले ताजा चट्टानों के नमूनों का लगभग 2 किलोग्राम भार लेकर पृथ्वी पर लौटा।
- अंतरिक्ष यान उत्तरी चीन के भीतरी मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र के सिजिवांग बैनर में उतरा।
- चांग 5 एक तीन सप्ताह का अभियान था जिसने चीन की अंतरिक्ष में बढ़ती प्रगति एवं महत्वाकांक्षा को रेखांकित किया। यह चीन का अब तक का सबसे सफल मिशन था।

झलकियाँ –

- चांग–5 के पुनः प्राप्त कैप्सूल को बीजिंग में प्रसारित किया जाएगा, जहां कैप्सूल खोला जाएगा एवं नमूने विश्लेषण एवं अध्ययन के लिए तैयार किये जाएंगे।
- चंद्रमा की प्राचीन चीनी देवी के नाम पर प्रोब को पहली बार 24 नवंबर को हैनान में वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से छोड़ा गया था।
- चांग 5 के चार में से दो मॉड्यूल 1 दिसंबर को चंद्रमा पर उतरे। सतह से स्कूपिंग करके एवं चंद्रमा की पपड़ी में 2 मीटर ड्रिलिंग करके नमूनों के लगभग 2 किलोग्राम (4.4 पाउंड) एकत्र किए।
- नमूने एक सील कंटेनर में जमा किए गए जिसे एक चढ़ाई वाहन द्वारा रिटर्न मॉड्यूल में वापस ले जाया गया।
- नमूनों को चंद्रमा के एक स्पष्ट रूप से निर्विवाद क्षेत्र से प्राप्त किया गया एवं 1976 में रूस के बाद किसी भी देश द्वारा एकत्र किए जाने वाले यह पहले नमूने भी हैं।
- नवीनतम नमूने चंद्रमा के एक हिस्से से आते हैं जिसे ओशन्स प्रोसेलरम, या स्टॉर्म के महासागर के रूप में जाना जाता है, जो कि मॉन्स रुम्कर नामक स्थान के समीप है जिसका प्राचीन काल में ज्वालामुखी होना माना जाता है।
- मॉन्स रुम्कर, जहाँ से पहले कभी नमूना नहीं लिया गया था, अमेरिकी एवं सोवियत मिशनों के नमूने क्षेत्रों की तुलना में भूगार्भिक रूप से बाद का है।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नमूने एक महत्वपूर्ण अंतर को भरने में मदद कर सकते हैं एवं चंद्रमा की ज्वालामुखी गतिविधि एवं उसके विकास को समझने के विश्लेषण के स्पेक्ट्रम को बढ़ा सकते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य –

- चीन संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ के बाद तीसरा देश बन गया, जिसने चंद्र नमूने एकत्र किए।
- अपोलो कार्यक्रम में, जिसने पहली बार पुरुषों को चंद्रमा पर पहुँचाया, द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1969 से 1972 तक छह उड़ानों में 12 अंतरिक्ष यात्रियों को उतारा, 382 किलोग्राम (842 पाउंड) चट्टानों एवं मिट्टी को लाया।
- चीन भी मंगल ग्रह का पता लगाने के प्रयास में शामिल हो गया है। जुलाई 2020 में, उसने तियानवेन 1 प्रोब शुरू की, जो पानी की खोज करने के लिए एक लैंडर एवं एक रोबोट रोवर ले जा रहा है। इसके 2021 के मध्य फरवरी के आसपास मंगल की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है।

- भारत के अलावा अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ ने अब तक मंगल पर मिशन भेजने में कामयाबी हासिल की है जिसे सबसे जटिल अंतरिक्ष मिशन माना जाता है।
- भारत ऐसा पहला एशियाई देश बन गया है जिसने अपने मंगलयान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसने 2014 में अपने पहले ही प्रयास में लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया।

कुथम्बलम का गुरुवयुर मंदिर

समाचार –

- केरल के त्रिशूर जिले में श्रीकृष्ण मंदिर, गुरुवायुर के पुनर्निर्मित कुथम्बलम ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया–प्रशांत पुरस्कार जीता है। कुथम्बलम एक मंदिर क्षेत्र है जहाँ अनुष्ठानों के कला रूपों का मंचन किया जाता है।

गुरुवयूर मंदिर –

- यह एक हिंदू मंदिर है, जो हिंदू भगवान, गुरुवायुरप्पन (भगवान विष्णु का एक चार–सशस्त्र रूप) को समर्पित है, जो केरल के गुरुवायूर शहर में स्थित है।
- यह केरल में हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक है एवं इसे अक्सर भुलोक वैकुंठ (पृथ्वी पर विष्णु का पवित्र निवास) के रूप में जाना जाता है।

विवरण –

- गुरुवयुर मंदिर में कुथम्बलम को सबसे आधुनिक निर्माण तकनीकों का उपयोग करके पुनर्निर्मित किया गया था, लेकिन पारंपरिक वास्तुकला को बरकरार रखा गया है।
- छत पर तांबे के पत्तों एवं अंदरूनी हिस्सों में लकड़ी के काम को पहले इनेमल पेंट से लेपित किया गया था, इसे हटा कर अब इसे पर्यावरण के अनुकूल पेंट से लेपा गया है।
- इसके अलावा, मंदिर के ग्रेनाइट खंडों एवं फर्श पर भी कार्य किया गया।
- संरचना में लकड़ी की मरम्मत भी की गई थी। एक ओर सुधार वैज्ञानिक रूप से नवीनीकृत प्रकाश व्यवस्था से संबंधित था।

निर्माण –

- इस मंदिर का निर्माण मंदिर के पंचप्रकार के भीतर किया गया है। प्रोजेक्ट की जगह बाह्यारा एवं मर्यादा के प्रकार के बीच है।
- केरल परंपरा में, इसे मंदिर परिसर के पंचप्रसादों में से एक माना जाता है।
- इसकी विमाएँ मदिर दर मंदिर अलग होती हैं।
- एक बड़े हॉल कुठामपलम के भीतर एक वर्गाकार प्लेटफॉर्म के ऊपर स्तंभों पर आधारित एक पिरामीडनुमा छत अलग से बनाई जाती है।
- हॉल के फर्श को दो बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है, एक हिस्सा प्रदर्शन (मंच, उपकरण, ग्रीन रूम आदि के लिए) एवं बाकि दर्शकों के लिए होता है।

क्रिसमस स्टार

समाचार –

- लगभग 400 वर्षों के बाद, 21 दिसंबर को, शनि एवं बृहस्पति – हमारे सौर मंडल के दो सबसे बड़े ग्रह – के आकाश में एक दुसरे के समीप दिखने की खगोलीय घटना का 'महान संयोजन' बना जिसे 'क्रिसमस स्टार' कहा जाता है।
- यह घटना उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति (वर्ष के सबसे छोटे दिन) एवं दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति पर आएगी।

महान संयोग –

- जब ग्रह या क्षुद्रग्रह पृथ्वी से देखे जाने पर आकाश में एक साथ बहुत करीब दिखाई देते हैं तो इस घटना को संयोजन कहते हैं।
- जून 2005 में, 'शानदार' संयोजन के परिणामस्वरूप, बुध, शुक्र एवं शनि आकाश में एक साथ इतने करीब दिखाई दिए कि आकाश के उस हिस्से को जहां तीनों ग्रह दिखाई दे रहे थे को एक अंगूठे से कवर किया जा सकता था।
- ग्रहों के आकार के कारण खगोलविद बृहस्पति एवं शनि के संयोजन के लिए 'महान' शब्द का उपयोग करते हैं।
- 'महान संयोजन' लगभग 20 वर्षों में एक बार होता है क्योंकि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए समय लेता है।
- बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं एवं शनि को 30 वर्ष (शनि की कक्षा बड़ी है एवं वह धीरे–धीरे आगे बढ़ता है क्योंकि यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से उतना प्रभावित नहीं है जितना कि सूर्य के करीब वाले ग्रह)।
- जैसे ही दो ग्रह अपनी कक्षाओं में आगे बढ़ते हैं, हर दो दशकों में, बृहस्पति एवं शनि पृथ्वी से समीप दिखाई देते हैं जिसे महान संयोग कहते हैं।

इस वर्ष संयोग दुर्लभ क्यों है?

- इस वर्ष, यह घटना दुर्लभ है क्योंकि ग्रह लगभग चार शताब्दियों में एक दूसरे के सबसे करीब आएंगे। परिणामस्वरूप खगोलविद हेनरी थ्रुप इसे 'दुर्लभ संरेखण' कहते है।

- बृहस्पति एवं शनि दिसंबर की शुरुआत से करीब जा रहे है एवं 21 दिसंबर को, यह शनि के ऊपर आ जाएगा।
- बृहस्पति एवं शनि चमकीले ग्रह हैं एवं इन्हें आमतौर पर शहरों से भी नग्न आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन एक संयोजन के दौरान, वे एक दूसरे के करीब दिखाई देते हैं, जो कि एक उल्लेखनीय घटना है।

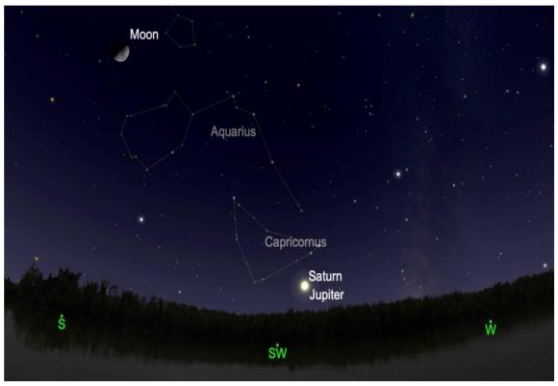

वानर सुरक्षा, पुनर्वास एवं बंध्याकरण केंद्र

समाचार –

- वन एवं पर्यावरण मंत्री ने तेलंगाना के निर्मल जिले के चिंचोली गांव के पास एक वानर सुरक्षा, पुनर्वास एवं बंध्याकरण केंद्र का उद्घाटन किया।

लक्ष्य –

- परियोजना का उद्देश्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए उन्हें एक नए निवास स्थान में प्रजनन करने एवं फिर उन्हें वन क्षेत्रों में छोड़ना है।

मुद्दा –

- वानर मानव बस्तियों में प्रवेश कर एवं फसलों को नुकसान पहुंचा कर समस्या का कारण बन रहे थे।

झलकियाँ –

- यह केंद्र दक्षिण भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है।
- ग्राम पंचायत अधिकारियों की सहायता से, वानरों को चरणबद्ध तरीके से केंद्र में पहुंचाया गया।
- डॉक्टरों ने वानरों की नसबंदी की जिसके बाद उन्हें अवलोकन के लिए पिंजरे में रखा गया, एवं ठीक होने के बाद उन्हें एक वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया।

मूषक हिरण (माऊस डियर)

- तेलुगु में मुशिका जिंका कहे जाने वाले मूषक हिरण छोटे आकार के हिरण हैं एवं उन्हें हरितावनम में फिर से लाया जा रहा है, जहां वर्तमान में ऐसा कोई हिरण नहीं है।
- हरितवनम लाए गए मूषक हिरण हैदराबाद के नेहरू प्राणि उद्यान से ले लाए गए हैं एवं उन्हे एक बाड़े में रखा गया है।

गैस्ट्रोडिया एगनिकेलस

समाचार –

- गैस्ट्रोडिया एगनिकेलस, एक नए खोजे गए आर्किड को 'विश्व का सबसे पुराना आर्किड' नाम दिया गया है।

विवरण –

- यह मेडागास्कर के जंगल में पाया जाता है।
- ऑर्किड पोषण के लिए कवक पर निर्भर करते है एवं इसमें कोई पत्तियां या कोई अन्य प्रकाश संश्लेषक ऊतक नहीं होता है।
- हालांकि एक खतरे वाली प्रजाति के रूप में मूल्यांकित किया गया है, पौधे राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित हैं।
- मेडागास्कर, पूर्वी अफ्रीका के तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में एक द्वीप देश है।
- मेडागास्कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है।

वेबकेप टोडस्टुल मशरूम

- इस वर्ष नामित अन्य आधिकारिक खोजों में यूनाइटेड किंगडम में प्राप्त वेबकैप टॉडस्टूल मशरूम की छह नई प्रजातियां एवं 2010 में दक्षिणी नामीबिया में मिली एक अजीब झाड़ी शामिल है।

टिगोनोफाइटन

- झाड़ी में विचित्र प्रकार की पत्तियां होती हैं एवं यह अत्यंत गर्म प्राकृतिक नमक के ढेरों में बढ़ती है, इसलिए इसका नाम टिंगोनोफाइटन है, जो ग्रीक 'टिंगोनो' या 'फ्राइंग पैन', एवं 'फाइटन' अर्थात पौधे से लिया गया है।

भारतीय बंदरगाह (प्रारूप) अधिनियम 2020

समाचार –

- बंदरगाहों, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए भारतीय बंदरगाह बिल 2020 के मसौदे को परिचालित किया है जो भारतीय बंदरगाहों अधिनियम, 1908 को निरस्त एवं प्रतिस्थापित करेगा।

बिल की विशेषताएं –

- अधिनियम बंदरगाहों के प्रभावी प्रबंधन द्वारा भारतीय तटरेखा के इष्टतम उपयोग के लिए बंदरगाहों के संरचित विकास एवं सतत विकास को सक्षम करने में मदद करेगा।
- यह बंदरगाहों के संरक्षण की सुविधा के लिए उपाय प्रदान करेगा। गैर–परिचालन बंदरगाहों की उच्च संख्या के संबंध में प्रचलित स्थिति को ध्यान में रखते हुए।
- भारतीय बंदरगाहों के क्षेत्र में सुधार, नए बंदरगाहों के निर्माण एवं मौजूदा बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए व्यापक नियामक ढांचे का निर्माण करेगा।
- विधेयक निम्नलिखित व्यापक तरीकों से भारत में बंदरगाहों क्षेत्र के विकास एवं सतत विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना चाहता है – समुद्री बंदरगाह नियामक प्राधिकरण का गठन, तटीय राज्य सरकारों, राज्य समुद्री के परामर्श से राष्ट्रीय बंदरगाह नीति एवं राष्ट्रीय बंदरगाह योजना का गठन बोर्ड एवं अन्य हितधारक, विशेष क्षेत्र न्यायाधिकरणों का गठन अर्थात् समुद्री बंदरगाह न्यायाधिकरण एवं समुद्री बंदरगाह विशेष न्यायाधिकरण, बंदरगाह क्षेत्र में किसी भी विरोधी प्रथाओं पर रोक लगाने एवं तेजी से कार्य करने के लिए किफायती शिकायत निवारण तंत्र बनाने।

श्रीनिवास रामानुजन

समाचार –

- उपराष्ट्रपति ने प्रख्यात गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
- यह दिन राष्ट्रीय गणित दिवस (22 दिसंबर) के रूप में भी मनाया जाता है।

श्रीनिवास रामानुजन का विवरण –

- श्रीनिवास रामानुजन का जन्म श्रीनिवास रामानुजन अयंगर (22 दिसंबर 1887 – 26 अप्रैल 1920) एक भारतीय गणितज्ञ थे जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए।
- उन्होंने गणितीय विश्लेषण, संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला, एवं निरंतर अंशों में पर्याप्त योगदान दिया, जिसमें गणितीय समस्याओं का समाधान भी शामिल था, फिर उन्हें अस्वीकार्य माना गया।
- अपने छोटे जीवन के दौरान, रामानुजन ने स्वतंत्र रूप से लगभग 3,900 परिणाम (ज्यादातर पहचान एवं समीकरण) संकलित किए।

राष्ट्रीय गणित दिवस 2020 –

- भारत के गणितीय प्रतिभा श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है।
- यह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 26 फरवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में भारतीय गणितीय प्रतिभा श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की 125 वीं वर्षगांठ के अवसर पर घोषित किया गया था।

भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020

समाचार –

- प्रधान मंत्री ने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल (IISF) 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से उद्घाटन भाषण दिया।
- इसका उद्देश्य जनता को विज्ञान से जोड़ना है।
- IISF 2020 का लक्ष्य युवाओं को वैज्ञानिक ज्ञान, रचनात्मकता, महत्वपूर्ण सोच, समस्या को सुलझाने एवं टीम वर्क पर ध्यान केंद्रित करने के साथ 21 वीं सदी के कौशल विकसित करने में मदद करना है।

पृष्ठभूमि –

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विज्ञान भारती (VIBHA) के साथ मिलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का एक अनूठा मंच बनाया है।
- 2015 में शुरू हुआ, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव देश के कई शहरों में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है।
- पहला एवं दूसरा IISF नई दिल्ली में, तीसरा चेन्नई में, चौथा लखनऊ में एवं पांचवा IISF कोलकाता में आयोजित किया गया।
- इन सभी IISFs ने भारत के भीतर एवं विदेशों से लोगों की अपार प्रतिक्रिया उत्पन्न की है।

उद्देश्य –

- IISF 2020 भारत एवं विदेशों में वैज्ञानिक स्वभाव के स्पेक्ट्रम को विकसित करने में भारत की दीर्घकालिक दृष्टि का एक अभिन्न अंग है।
- विज्ञान के साथ सार्वजनिक जुड़ाव एवं विज्ञान का उत्सव मनाने के लिए।
- दीर्घकालिक उद्देश्य छात्रों को वैज्ञानिक क्षेत्रों में अध्ययन एवं काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- इसके अलावा, यह बताता है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित (एसटीईएम) किस प्रकार हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपाय प्रदान करते हैं।

महोत्सव को मदद करने वाले संस्थान–

- विज्ञान प्रसार
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)
- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) एवं
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)।

राष्ट्रीय किसान दिवस

समाचार –

- किसानों एवं अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है।
- यह दिन 23 दिसंबर को मनाया जाता है, भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर।
- चरण सिंह ने छोटे एवं सीमांत किसान मुद्दों को सबसे आगे लाने का काम किया।
- देश में किसान के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, चरण सिंह ने 23 दिसंबर 1978 को किसान ट्रस्ट की स्थापना की।

चौधरी चरण सिंह –

- उनका जन्म 1902 में मेरठ में हुआ था। वह एक किसान परिवार से थे।
- उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिए गए नारे 'जय जवान, जय किसान' को जीवन में उतारा।
- उन्होंने 1979 एवं 1980 के बीच बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
- देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई किसान हितैषी पहलें की।
- वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आर्य समाज एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय भागीदार थे। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्हें दो बार कारावास हुआ।
- 1939 में, उन्होंने ऋण मोचन विधेयक पेश किया। इससे किसानों को मुनीमों से पैसा उधार लेने से राहत मिली।
- 1952 में, एक कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने भारत में जमींदारी प्रणाली को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत की।
- 1953 में, उन्हें होल्डिंग्स एक्ट का समेकन मिला। अधिनियम के तहत, किसानों की खंडित भूमि जोतने एवं पूल करने के लिए किसानों को इस तरह से आवंटित किया गया था कि प्रत्येक किसान को एक ही खेत मिले।
- किसानों के कल्याण के लिए उनके योगदान के लिए, नई दिल्ली में उनके स्मारक को किसान घाट नाम दिया गया।

ब्रेकडांसिंग

समाचार –

- ब्रेकडांसिंग एक आधिकारिक ओलंपिक खेल बन गया।
- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने युवा दर्शकों को लुभाने के लिए शहरी खेलों को शामिल करने की कोशीश में 2024 के पेरिस खेलों में सड़क पर किए जाने वाली ब्रेकडांसिंग प्रतियोगिताएं अब पदक प्राप्त करने का जरिया बन सकेंगी।
- इसके अलावा आईओसी कार्यकारी बोर्ड ने पेरिस खेलों के लिए स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइम्बिंग एवं सर्फिंग खेलों के शामिल होने की पुष्टि की।
- ब्यूनस आयर्स में 2018 युवा ओलंपिक में सकारात्मक परीक्षणों के बाद पेरिस आयोजकों द्वारा लगभग दो वर्ष पहले ब्रेकडांसिंग का प्रस्ताव दिया गया था।

एफ/ए –18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट

समाचार –

- बोइंग ने नौसेना के लड़ाकू खरीद के लिए अपने पिच के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना के विमान वाहक के साथ अपने एफ/ए –18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू जेट की संगतता के सफल प्रदर्शन की घोषणा की।

विवरण –

- प्रदर्शनों को अमेरिकी नौसेना के साथ समन्वय में मेरीलैंड अमेरिका में पेट्युज़ेन्ट नदी के किनारे आयोजित किया गया।
- प्रदर्शनों से पता चलता है कि एफ–18 सुपर हॉर्नेट भारतीय नौसेना के शॉर्ट टेक–ऑफ अरेस्ट लैंडिंग (STOBAR) प्रणाली के साथ अच्छा काम करेगा एवं पिछले दो वर्षों में किए गए अन्य सिमुलेशन अध्ययनों को मान्य करता है।
- बोइंग के प्रस्तावित 'बाय इंडिया, फॉर इंडिया' स्थिरता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, ब्लॉक III सुपर हॉरनेट को भारतीय नौसेना के साथ–साथ भारत एवं अमेरिका स्थित साझीदारों द्वारा जहाजों के संपूर्ण जीवन चक्र में सर्विस किया जा सकता है।

महत्व –

- एफ/ए –18 ब्लॉक III सुपर हॉर्नेट न केवल भारतीय नौसेना को बेहतर युद्ध–लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा, बल्कि अमेरिकी एवं भारत के बीच नौसैनिक विमानन में सहयोग के अवसर भी पैदा करेगा।
- F/A–18 नौसेना के P-8I के साथ 'बल गुणक' के रूप में एवं प्रेरण के अन्य प्लेटफार्मों के साथ भी इंटरफेस कर सकता है।

STOBAR -

- STOBAR ('शॉर्ट टेक–ऑफ बट अरेस्ड रिकवरी' या 'शॉर्ट टेक–ऑफ, बैरियर एररेटेड रिकवरी') एक विमान वाहक के डेक से विमान के प्रक्षेपण एवं पुनर्प्राप्ति के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली है।
- नौसेना का एकमात्र कार्यरत वाहक INS विक्रमादित्य में एवं निर्माणाधीन स्वदेशी विमान वाहक (IAC) –I विक्रांत दोनों में STOBAR तंत्र के साथ एक स्की–जंप है।

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय

समाचार –

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम (जीवीएमसी) को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना है।
- GVMC को 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए चुना गया है।

विवरण –

- यह पुरस्कार 1 जनवरी 2021 को आवास एवं शहरी मामलों के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
- आंध्र प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह, राज्य ने परियोजना निगरानी उपकरण एवं नवीन निर्माण प्रौद्योगिकी में विशेष श्रेणी का पुरस्कार भी प्राप्त किया है।
- मिर्जापुर नगर पंचायत ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नगर निकाय जीता जबकि मलीहाबाद लखनऊ को पहले स्थान के लिए एवं हरिहरपुर को दूसरे स्थान के लिए चुना गया।
- मंत्रालय ने 'शहरी क्षेत्रों में आवास लाभार्थियों के चयन में प्रौद्योगिकी एवं पारदर्शिता के उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन' के लिए पुरस्कारों को शामिल करने का निर्णय लिया है। कुल पांच पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वे इस प्रकार हैं –
  –सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य
  – सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम
  – सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पालिका
  – सर्वश्रेष्ठ हाउस कंस्ट्रक्शन
  – सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को पहचानने के लिए विशेष पुरस्कार

थौबल बहुउद्देशीय परियोजना

समाचार –

- मणिपुर में गृह मंत्री द्वारा थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया गया। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान थौबल बहुउद्देशीय परियोजना योजना शुरू की गई थी। 35,104 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने वाली यह परियोजना पूर्ण होने की स्थिती में है।
- उन्होंने ऑनलाईन माध्यम से इम्फाल में ई–ऑफिस एवं थौबल मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट (थौबल डैम) का उद्घाटन किया।

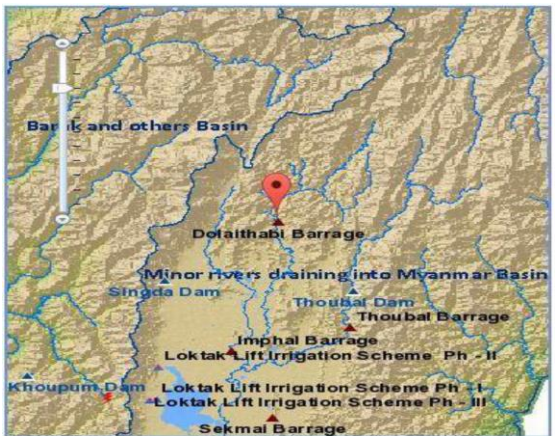

- उन्होंने परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिसमें चुराचंदपुर मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में मंटिपुखरी में आईटी–एसईजेड, मणिपुर भवन एवं इंफाल में एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र शामिल हैं।
- इम्फाल में राज्य पुलिस मुख्यालय एवं स्मार्ट सिटी इंटीग्रेटेड सेंटर स्मार्ट गवर्नेंस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
- आईटी–एसईजेड के निर्माण के बाद, मणिपुर की जीडीपी में सालाना 600 करोड़ की वृद्धि होगी एवं 44,000 लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा।

'ग्रीन प्रोपल्शन' तकनीक

समाचार –

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 'ग्रीन प्रोपल्सन' तकनीक विकसित कर रहा है, माना जाता है कि यह पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है।
- प्रोपल्शन (प्रणोदन) का अर्थ है आगे बढ़ना या किसी वस्तु को आगे बढ़ाना।
- यह शब्द दो लैटिन शब्दों से लिया गया है – प्रो, जिसका अर्थ पहले या आगे एवं पेलेरे, जिसका अर्थ है चलना। एक प्रणोदन प्रणाली में यांत्रिक शक्ति का एक स्रोत होता है, एवं एक प्रणोदक होता है।
- रॉकेट एवं हवाई जहाज में, प्रोपल्सन न्यूटन के तीसरे नियम 'प्रत्येक क्रिया के लिए, एक समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है', के अनुप्रयोग के माध्यम से उत्पन्न होता है।

ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी –

- इसरो ने 2018 में ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी विकसित करने की यात्रा शुरू की। इसरो ने ईंधन के रूप में एक ईको–फ्रेंडली सॉलिड प्रोपेलेंट ग्लाइसीडाइल एलाइड पॉलीमर जीएपी विकसित किया एवं ऑक्सीमाइजर के रूप में अमोनियम डी–नाइट्रामाइड।
- इसरो प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाओं को चला रहा था जिसमें केरोसिन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तरल ऑक्सीजन, ANDGlycerol-water एवं मेथनॉल–पानी जैसे हरे प्रणोदक संयोजनों को शामिल किया गया था।
- इसरो ने लॉन्च वाहनों के लिए तरल ऑक्सीजन, तरल हाइड्रोजन आधारित प्रणोदन प्रणाली का परीक्षण शुरू कर दिया है।
- इसरो ने पहले ही अपने मिशन में ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। हालाँकि, तकनीकों का उपयोग केवल मिशन के एक हिस्से में किया जाता है। उदाहरण के लिए, लिक्विड ऑक्सीजन, प्रोपल्सन के लिक्विड हाइड्रोजन संयोजन का उपयोग जीएसएलवी एमके– III वाहन के ऊपरी क्रायोजेनिक स्थितीयों में किया जाता है।
- ISRO ने ISORENE विकसित किया है। ISORENE केरोसिन का रॉकेट ग्रेड संस्करण है। यह पारंपरिक हाइड्रेंजाइन रॉकेट ईंधन का एक विकल्प है।
- इसरो ने अपने दक्षिण एशिया उपग्रह में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जो मई 2017 में लॉन्च किया गया था।

लद्दाख में उमबा गांव

समाचार –

- उमबा गांव के पांच मोहल्लों को बिजली कनेक्शन मिला।
- जिला मुख्यालय कारगिल से 60 किलोमीटर दूर यह 13,000 हजार फीट की ऊंचाई पर सबसे कठिन इलाके में स्थित है एवं सर्दियों के दौरान पांच महीने तक कट जाता है।
- उमबा गाँव में आज तक बिजली नहीं थी।

- कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी (KREDA) के मार्गदर्शन में, Royal Enfield के CSR प्रोजेक्ट के साथ साझेदारी में ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन (GHE) ने उम्बा में 17.5kW की सोलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम लगाई है।
- ठंड के शून्य से 25 डिग्री तापमान में काम करते हुए एक टीम ने 103 सौर ग्रिड स्थापित किये है ।
- समुदाय के लिए स्ट्रीट लाइटिंग के साथ–साथ कुल 97 घरों 7 मस्जिदें में 500 से अधिक एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं।
- प्रत्येक सौर ग्रिड को बैटरी बैक–अप प्रदान किया गया है जो 4 दिनों की निरंतर बादलों की स्थिति में भी ग्रिड को चलने में सक्षम करेगा।
- जीएचई ऊर्जा कुशल एलईडी रोशनी एवं डीसी उपकरणों का उपयोग करके एक अभिनव सौर माइक्रो ग्रिड समाधान के साथ आया है जिसने क्षेत्र में विद्युतीकरण परिदृश्य को बदल दिया है।
- जीएचई द्वारा पिछले 5 वर्षों में लेह, कारगिल एवं जांस्कर के 100 से अधिक दूरदराज के गांवों, मठों एवं आवासों को बिजली प्रदान की गई है।

थेरिमिन

समाचार –

- थेरेमिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 2020 में सौ वर्ष पुराना हो गया है। इसे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण माना जाता है।
- यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के मॉड्यूलेशन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करता है एवं यह बजाने वाले व्यक्ति के इंस्ट्रूमेंट को छुए बिना होता है। इसमें टोन को नियंत्रित करने के लिए एक ऊर्ध्वाधर एंटीना एवं वॉल्यूम को नियंत्रित करने के लिए एक लूप एंटीना होता है।

इतिहास –

- जब प्रौद्योगिकी में रेडियो तरंगें अभी भी एक नई घटना थी, तो एक वैज्ञानिक ने कहा कि अगर वह एप्रेटस के चारों ओर हाथ बढ़ाता है तो एप्रेटस अजीब आवाज निकालता है।
- लेव सर्गेयेविच टर्मेन– जो बाद में लियोन थेरेमिन के नाम से प्रसिद्ध हुए– एक शास्त्रीय संगीतकार भी थे, जो सेलो बजाते थे, एवं अजीब आवाजों ने उनकी रुचि को बढ़ाया।
- उन्होंने थोड़ी देर के लिए इसे ध्वनियों के साथ 'बजाया' एवं निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने नए संगीत उपकरण बनाए हैं, जो बिना छुए बजाया जा सकता है।
- यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था, जिसे थेरेमिन कहा जाता था।

थेरेमिन –

- थेरेमिन में एक ऊर्ध्वाधर एंटीना एवं एक लूप एंटीना होता है, एवं बजाने वाला व्यक्ति हवा में अपने हाथों एवं उंगलियों को इधर–उधर घुमाकर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों को बजाते हैं।
- यदि आप ऊर्ध्वाधर एंटीना के चारों ओर हाथ घूमाते हैं, तो आप टोन बढ़ा या घटा सकते हैं। लूप्ड एंटीना वॉल्यूम को नियंत्रित करता है।

मुख्य परीक्षा आधारित समसामयिकी

सामान्य अध्ययन – I

भारतीय विरासत एवं संस्कृति,
इतिहास एवं विश्व एवं समाज का भूगोल

पहली डाऊनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना –

समाचार –

- चीनी अधिकारियों ने एक चीनी पनबिजली कंपनी को ब्रह्मपुत्र नदी की निचली पहुंच (तिब्बत में यारलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है) पर पहली डाउनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना का निर्माण करने की अनुमति दी है।
- परियोजना को देश की 14 वीं पंचवर्षीय योजना (2021–25) तैयार करने के प्रस्तावों में आगे रखा गया था।
- 14 वीं पंचवर्षीय योजना (2021–2025) एवं राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं दीर्घकालीन उद्देश्य वर्ष 2035 को प्लेनम द्वारा अपनाया गया था – जो सीपीसी का एक प्रमुख नीति निकाय है।
- यह पहली बार होगा जब नदी के बहाव क्षेत्र का दोहन किया जाएगा।
- हालांकि, नियोजित परियोजना के स्थान का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।

ब्रह्मपुत्र नदी –

- यह सियांग या दिहांग के नाम से मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है।
- यह अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है।
- सहायक नदियाँ– दिबांग, लोहित, सियांग, बुरही दिहिंग, तिस्ता एवं धनसारी।
- यह एक बारहमासी नदी है एवं इसकी भूगोल एवं प्रचलित जलवायु परिस्थितियों के कारण कई विशिष्ट विशेषताएं हैं।
- इसमें सालाना दो बार बाढ़ आती है। एक बाढ़ गर्मियों में हिमालय की बर्फ के पिघलने के कारण एवं दूसरी मानसून के प्रवाह के कारण होती है।

भारत की चिंता –

- भारत 2015 से ब्रह्मपुत्र पर चिंता व्यक्त कर रहा है जब चीन ने जंगमू में अपनी परियोजना का संचालन किया।
- ग्रेट बेंड बांध को यदि मंजूरी दे दी जाती है, तो यहाँ नई चिंताओं जैसे इसके स्थान, अरूणाचल प्रदेश की सीमा के बिल्कुल नजदीक होने का जन्म होगा।
- भारत पानी की गुणवत्ता, पारिस्थितिक संतुलन एवं बाढ़ प्रबंधन को प्रभावित करने वाली चीनी गतिविधियों से चिंतित है।
- भारत एवं चीन के बीच जल बंटवारा समझौता नहीं है। दोनों देश जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों को साझा करते हैं इसलिए सही आँकड़े साझा करना एवं सूखे, बाढ़ एवं उच्च–पानी के निर्वहन की चेतावनी जैसे मुद्दों पर निरंतर संवाद महत्वपूर्ण हो जाता है।

चक्रवाती तूफान बुरेवी

समाचार –

- चक्रवात 'बुरेवी' ने 4 दिसंबर को तमिलनाडु को हिला दिया। इससे पहले, एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान, निवार, ने दक्षिणी राज्य में विनाश किया था।
- इसने पहले 2 दिसंबर को श्रीलंका एवं फिर 4 दिसंबर को तमिलनाडु में प्रवेश किया।

चक्रवात –

- चक्रवात, हवाओं की कोई भी बड़ी प्रणाली जो भूमध्य रेखा के उत्तर में भूमध्य रेखा के निम्न वायुमंडलीय दबाव के केंद्र में एवं दक्षिण की ओर दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है।
- चक्रवाती हवाएं भूमध्यरेखीय पेटी को छोड़कर पृथ्वी के लगभग सभी क्षेत्रों में चलती हैं एवं आमतौर पर बारिश या बर्फ से जुड़ी होती हैं।

चक्रवात के प्रकार –

- प्रचलित निम्न–दबाव प्रणाली के प्रकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के चक्रवात हैं।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात
- उष्णकटिबंधीयेत्तर चक्रवात
- टॉरनेडो

- मंगल, बृहस्पति एवं नेपच्यून जैसे अन्य ग्रहों पर भी चक्रवात देखे जाते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति पर तूफान है जो 340 वर्षों से चल रहा है। ग्रेट ब्लैक स्पॉट को नेपच्यून के दक्षिणी गोलार्ध में देखा गया था।

विभिन्न नाम –

- हरिकेन – अटलांटिक एवं पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में
- टाइफून – दक्षिण पूर्व एशिया में
- साईक्लोन (चक्रवात) – ऑस्ट्रेलिया के आसपास हिंद महासागर एवं पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की एक अंतरराष्ट्रीय समिति द्वारा चक्रवातों की सूचियों एवं नामों को बनाए रखा एवं अद्यतन किया जाता है।

चक्रवात का निर्माण –

- भूमध्य रेखा के पास गर्म महासागरीय जल के ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। समुद्र की सतह के पास गर्म नम हवा ऊपर की ओर उठती है।
- इससे सतह के पास एक कम दबाव का क्षेत्र बनाता है। इससे आसपास के क्षेत्रों से कम दबाव वाले क्षेत्र में ठंडी हवा की आवाजाही होती है। अब तो यह ठंडी हवा भी गर्म एवं नम हो जाती है एवं ऊपर उठ जाती है।
- उपरोक्त चक्र निरंतर चलता रहता है। गर्म नम हवा जो ऊपर उठती है, हवा में पानी को ठंडा करती है, जिसके परिणामस्वरूप बादल बनते हैं। बादलों एवं हवाओं का यह पूरा सिस्टम घूमता एवं बढ़ता है।
- यह पूरा चक्र एक चक्रवात कहलाता है। जब हवाएं 63 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंचती हैं, तो इसे उष्णकटिबंधीय तूफान कहा जाता है, जब हवाएं 119

किमी प्रति घंटे की गति तक पहुंचती हैं तो इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है।

अन्नपूर्णा की मूर्ति

समाचार –

- वाराणसी अन्नपूर्णा की मूर्ति को कनाडा से शताब्दी के बाद भारत लाया जा रहा है। यह लगभग एक सदी पहले वाराणसी के एक मंदिर से चोरी हुई थी। देवी को खीर का कटोरा एवं एक चम्मच धारण करते हुए दर्शाया गया है।

अन्नपूर्णा –

- अन्नपूर्णा, को भोजन एवं पोषण की देवी के रूप में जाना जाता है। उन्हें देवी पार्वती के रूप में भी जाना जाता है, जो भगवान शिव की साझीदार हैं।
- कनाडा में चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति का पता कैसे लगाया गया?
- बनारस शैली की कला के बाद बनी 18 शताब्दी की मूर्ति लंबे समय से मैकेंजी आर्ट गैलरी, कनाडा के एक कला संग्रहालय में एक प्रदर्शनी थी जो रेजिना विश्वविद्यालय के निजी संग्रह को प्रदर्शित करती है।
- एक विन्निपेग कलाकार दिव्या मेहरा को मैकेंजी आर्ट गैलरी में एक प्रदर्शनी के लिए आमंत्रित किया गया था। जब वह संग्रह पर शोध कर रही थी, तो उसने पाया कि अन्नपूर्णा मूर्ति 1913 में वाराणसी के तट पर एक निष्क्रिय मंदिर से चुराई गई थी। इसे मैकेंजी ने अधिग्रहित किया था।

भारत कब पहुंचेगा मूर्ति?

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सूत्रों, जो सभी प्रत्यावर्तित कलाकृतियों के संरक्षक हैं, ने बताया कि मूर्ति मध्य दिसंबर तक वापस आ जाएगी।
- मूर्ति काशी में अपने मूल घर वापस चली जाएगी।

अन्य प्रत्यावर्तित वस्तुएं –

- केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने हाल ही में ब्रिटेन की फर्म से वापस लाने के बाद भगवान राम, लक्ष्मण एवं देवी सीता की एक कांस्य मूर्ति को तमिलनाडु सरकार को सौंप दिया।
- पिछले छह वर्षों में, सरकार विभिन्न देशों से 40 पुरावशेषों का पता लगाने में सक्षम रही जो 1977 से 2014 के बीच चोरी हो गए थे।
- एएसआई के रिकॉर्ड के अनुसार, उनमें से 13 को भारत वापस लाया गया था।

महापरिनिर्वाण दिवस –

समाचार –

- राष्ट्र ने 64 वें महापरिनिर्वाण दिवस या 6 दिसंबर को भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. बी आर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉ. बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विचारक, राजनीतिज्ञ एवं स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे।

महापरिनिर्वाण दिवस –

- 'परिनिर्वाण' शब्द का बौद्ध परंपराओं में गहरा अर्थ है एवं यह किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसने अपने जीवनकाल में या मृत्यु के बाद निर्वाण प्राप्त किया हो।

- 6 दिसंबर को समाज एवं उनकी उपलब्धियों के लिए उनके अथाह योगदान की स्मृति में मनाया जाता है। लाखों लोग एवं अनुयायी इस दिन चैत्य भूमि में इकट्ठा होते हैं।
- निर्देशक सिद्धांतों को आकार देने में उनका अथक प्रयास, समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण प्रणाली का सूत्रपात, दलितों के बौद्धों के समान अधिकार की आवाज ने उन्हें भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक अपूरणीय स्थान दिलवाया है।
- 1932 के ऐतिहासिक पूना पैक्ट पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने दलितों को सामान्य चुनावी सूची में जगह दी थी।

डॉ बी आर अम्बेडकर –

- 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश में जन्मे अंबेडकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय के तहत एल्फिंस्टन कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी की थी एवं फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपना पाठ्यक्रम पूरा किया।

- एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू एवं गांधी के साथ मोर्चे का नेतृत्व किया था एवं समाज के गरीब एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- अंबेडकर ने दलित बौद्ध अभियान को आगे से आगे बढ़ाया एवं उनके समान मानव अधिकारों एवं बेहतरी के लिए अथक प्रयास किया।
- इस प्रकार, यह अपरिहार्य हो जाता है कि इस तरह के गूढ़ व्यक्तित्व को उनकी पुण्यतिथि पर सर्वोच्च श्रद्धांजलि दी जाए।
- 1956 में उन्होंने अपनी पुस्तक एनीहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित की जिसमें तत्कालीन प्रथा एवं अछूत एवं दलित कानूनों के बारे में आलोचना की गई थी।
- डॉ बी आर अम्बेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

थारू आदिवासी

समाचार –

- उत्तर प्रदेश सरकार ने थारू जनजाति की अनूठी संस्कृति को विश्व भर में ले जाने की योजना शुरू की है।
- योजना का उद्धेश्य थारू गाँवों को पर्यटन के नक्शे पर लाना एवं रोजगार सृजन करना एवं आदिवासी आबादी को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाना है।

थारुस –

- यह समुदाय निचले हिमालय के शिवालिकों के बीच तराई क्षेत्रों में रहता आया है। उनमें से अधिकांश वनवासी हैं एवं कुछ कृषि करते हैं।
- थारू शब्द का अर्थ थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं।
- थारू भारत एवं नेपाल दोनों में रहते हैं। भारतीय में, वे ज्यादातर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में रहते हैं।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 11 लाख से अधिक थी, वर्तमान अनुमानित संख्या 20 लाख के उपर है।
- जनजाति के सदस्य गेहूं पर जीवित रहते हैं, मकई एवं सब्जियां अपने घरों के करीब उगाई जाती हैं। अधिकांश अभी भी जंगल से दूर रहते है।
- थारुस महादेव के रूप में भगवान शिव की पूजा करते हैं, एवं उनके परम 'नारायण' कहते हैं, एवं उन्हें धूप, बारिश एवं फसल के प्रदाता मानते हैं।
- थारू महिलाओं के पास उत्तर भारतीय हिंदू रीति–रिवाज की मुख्यधारा में महिलाओं की तुलना में अधिक संपत्ति के अधिकार हैं।

योजना का विवरण –

- राज्य सरकार उत्तर प्रदेश वन विभाग की होम स्टे योजना के साथ बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर एवं पीलीभीत नेपाल के जिलों में थारू गांवों को जोड़ने के लिए काम कर रही है।
- मुख्य रूप से जंगलों से एकत्रित घास से बने पारंपरिक झोपड़ियों में पर्यटकों को प्राकृतिक थारू निवास स्थान में रहने का अनुभव प्रदान करना है।
- थारू गृहस्वामी पर्यटकों को आवास एवं घर के भोजन के लिए सीधे शुल्क ले सकेंगे।
- सरकार को उम्मीद है कि घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटक अपने जीवन शैली, खान–पान एवं पहनावे को देखते हुए अपने साथ रहकर विशेष थारू संस्कृति का स्वाद लेने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (CEEW)

समाचार –

- काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईवी) द्वारा जारी 'एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स – मैपिंग हॉटस्पॉट्स एंड रिस्पांस मैकेनिज्म' की रिपोर्ट पर किए गए एक हालिया अध्ययन के अनुसार, भारत में 75% से अधिक जिलों में चरमपंथी घटनाओं जैसे चक्रवात, बाढ़, सूखा, गर्मी एवं शीत के हॉटस्पॉट हैं।
- भारत में, 97 मिलियन से अधिक लोग वर्तमान में अत्यधिक बाढ़ के संपर्क में हैं, 258 जिले पिछले एक दशक के दौरान चक्रवातों से प्रभावित हुए हैं एवं 2005 के बाद से सूखा प्रभावित जिलों का वार्षिक औसत 13 गुना बढ़ गई है।

जलवायु जल्दी क्यों बदल रही है?

- भू–उपयोग के प्रतिमानों को बदलना, अस्थिर शहरीकरण, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अतिक्रमण ने भारत में जलवायु पैटर्न में एक मोड़ ला दिया है, जो चरम मौसम एवं पर्यावरणीय घटनाओं का कारण बन रहा है।

रिपोर्ट की खोज –

- रिपोर्ट में बताया गया है कि 1970 एवं 2019 के बीच 20 से अधिक बार भूस्खलन, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, गरज एवं बादलों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है।
- बिहार पिछले कुछ वर्षों में बाढ़ की लहर की शुरुआत से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से एक है।
- कटक, गुंटूर, कुरनूल, महबूबनगर, नलगोंडा, पश्चिम के क्षेत्र चंपारण, एवं श्रीकाकुलम हाल के वर्षों में सूखाग्रस्त हो गए हैं।
- तटीय दक्षिणी भारतीय राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक भी स्थानीय जलवायु परिवर्तन से प्रेरित अधिक सूखे की ओर बढ़ रहे हैं।
- पिछले 50 वर्षों के दौरान, बाढ़ की आवृत्ति लगभग आठ गुना बढ़ गई।
- 2019 में, भारत में 16 अति बाढ़ की घटनाएं हुईं, जिसने 151 जिलों को प्रभावित किया।

बाढ़ एवं चक्रवात के बीच सहसंबंध –

- बढ़ती निर्माण गतिविधि एवं वनों की कटाई के साथ भूमि–उपयोग के पैटर्न में बदलाव ने देश के कई हिस्सों में एक गर्म माइक्रोकलाइमेट को प्रेरित किया है।
- इस माइक्रॉक्लाइमैटिक परिवर्तन से तापमान में वृद्धि होती है एवं गर्म हवा वातावरण में फंस जाती है, जिससे कई गैर–तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक बादल छा जाते हैं एवं फ्लैश फ्लड शुरू हो जाता है।
- जब उसी गर्म हवा को ठंडे क्षेत्रों की ओर खींचा जाता है, तो यह तूफानों एवं चक्रवातों को ट्रिगर करती है।

जलवायु लचीलापन –

- वर्तमान में मुख्य आवश्यकताएं इन चरम घटनाओं के प्रभावों का मुकाबला करने एवं उन्हें कम करने के लिए एक नए सिरे से रणनीति विकसित करने की हैं। भारत के लिए जलवायु जोखिम एटलस तैयार करने के लिए स्थानीयकृत जोखिम मूल्यांकन रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है।
- आपात स्थिति के लिए एक व्यवस्थित एवं निरंतर प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए एक एकीकृत आपातकालीन निगरानी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।
- एक अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता जिला एवं राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिकारियों को बेहतर बुनियादी ढांचे एवं रणनीति के साथ तैयार करने के लिए बजटीय आधार प्रदान करना है।
- स्वाभाविक रूप से होने वाले चक्रवातों से निपटने के लिए साथ आने एवं एक अनुकूली रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है।

ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल पर परिषद

- सीईईवीई, दिल्ली स्थित एक गैर–लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान है।
- सीईईवी के कुछ अनुसंधान क्षेत्रों में जल संसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्थिरता वित्त, ऊर्जा–व्यापार–जलवायु संबंध, एकीकृत ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल की योजना, एवं जलवायु भू–नियोजन शासन दक्षता एवं सुरक्षा शामिल है।
- CEEW की स्थापना 2010 में हुई थी।

माइक्रोकलाइमिक जोन शिफ्टिंग –

- माइक्रॉक्लाइमैटिक जोन ऐसे क्षेत्र जहाँ का मौसम आसपास के क्षेत्रों से भिन्न होता है।
- माइक्रॉक्लाइमेट जोन में बदलाव से पूरे सेक्टर में भयंकर व्यवधान हो सकता है।
- वार्षिक औसत तापमान में हर 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से कृषि उत्पादकता में 15–20% की कमी आएगी।
- माइक्रोकलाइमिक जोन में इस बदलाव के पीछे पहचाने जाने वाले कुछ कारणों में लैंड–यूज पैटर्न, वनों की कटाई, मैंग्रोव पर अतिक्रमण, वेटलैंड्स एवं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों को अतिक्रमण से गायब करना, एवं शहरी ऊष्मातापी क्षेत्रों को बदलना है।

भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन (इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट)

समाचार –

- नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) एवं गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज (cGanga) केंद्र ने 10–15 दिसंबर 2020 के दौरान 5 वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया।
- इस वर्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन, अर्थ गंगा पर ध्यान देने के साथ नदियों एवं जल निकायों का व्यापक विश्लेषण एवं समग्र प्रबंधन पर केंद्रित है।

नमामि गंगे –

- इसे स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन भी कहा जाता है।
- इसे 2014 में गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प में प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू किया गया था।
- इसे राष्ट्रीय गंगा परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जिसने 2016 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया।
- कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ जैव विविधता एवं वनीकरण, जन जागरूकता, सीवेज उपचार के बुनियादी ढांचे एवं औद्योगिक प्रवाह की निगरानी एवं रिवरफ्रंट विकास एवं नदी के सतह की सफाई हैं।

अर्थ गंगा –

- नमामि गंगे "अर्थ गंगा" के आसपास विकसित होता है।
- साधारण शब्दों में यह एक विकास मॉडल का अर्थ है जो गंगा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित है।
- इस प्रक्रिया के तहत, किसानों को गंगा नदी के तट पर स्थायी कृषि प्रथाओं, बिल्डिंग प्लांट नर्सरी में शामिल होने, शून्य बजट खेती एवं फलदार पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- अर्थ गंगा में पानी के खेल, पैदल ट्रैक, शिविर स्थलों का विकास, साइकिल चालन आदि के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण भी शामिल होगा।
- अंततः इसका लक्ष्य हाइब्रिड टूरिज्म संभावनाओं का दोहन करना है, जिसमें धार्मिक एवं एडवेंचर टूरिज्म दोनों हो।

सम्मेलन का विवरण –

- शिखर सम्मेलन गंगा जल क्षेत्र में निवेशकों एवं हितधारकों के लिए एक सामान्य मंच के रूप में कार्य करेगा। शिखर सम्मेलन नदी प्रबंधन के लिए भारत एवं कई अन्य विदेशी देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा।

मोनपा हस्तनिर्मित कागज

समाचार –

- 1000 वर्ष पुरानी धरोहर कला– अरुणाचल प्रदेश के मोनपा हस्तनिर्मित कागज, जिसे विलुप्त होने के लिए छोड़ दिया गया था, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के प्रतिबद्ध प्रयासों से एक बार फिर से जीवंत हो गई है।

विवरण –

- तवांग के हर घर में निर्मित होने के बाद, यह हस्तनिर्मित कागज स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत था।
- धीरे–धीरे यह कला अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थानीय प्रथा एवं संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गई।
- महीन बनावट वाला हस्तनिर्मित कागज, जिसे स्थानीय बोली में सोम शुग कहा जाता है, तवांग में स्थानीय जनजातियों की जीवंत संस्कृति का अभिन्न अंग है।
- कागज का बड़ा ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व है क्योंकि यह बौद्ध धर्मग्रंथों एवं मठों में भजन लिखने के लिए उपयोग किया जाने वाला पेपर है।
- मोनपा हस्तनिर्मित कागज, शुग शेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाएगा, जिसमें औषधीय गुण भी हैं।
- इसके बाद, मोनपा इन कागजों को तिब्बत, भूटान, थिलानंद एवं जापान जैसे देशों में बेचता था क्योंकि उस समय इन देशों में कोई कागज बनाने का उद्योग मौजूद नहीं था।

- हालांकि, धीरे–धीरे स्थानीय उद्योग में गिरावट आने लगी एवं चीनीयों द्वारा स्वदेशी हस्तनिर्मित कागज उद्योग पर कब्जा कर लिया गया।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

- KVIC भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में संसद के अधिनियम, 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956' के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- यह भारत के भीतर खादी एवं ग्रामोद्योग के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक सर्वोच्च संगठन है, जो – ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी उद्योग आवश्यक हो, ग्रामीण विकास में लगी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में खादी एवं गाँव की स्थापना एवं विकास में योजना को बढ़ावा, सुविधा, आयोजन एवं सहायता करना चाहता है।

खादी –

- खादी का तात्पर्य हाथ से बुने कपड़े से है। कच्चा माल कपास, रेशम या ऊन हो सकता है, जो चरखे पर धागे में पिरोया जाता है।
- खादी को 1920 में महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन में एक राजनीतिक हथियार के रूप में लॉन्च किया गया था।
- खादी भारत के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त की जाती है, जो इसके कच्चे माल पर निर्भर करती है – जबकि रेशम की किस्म पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा एवं उत्तर पूर्वी राज्यों से प्राप्त होती है, कपास की किस्में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल से आती हैं।
- खादी पाली गुजरात एवं राजस्थान में काटी जाती है, जबकि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू एवं कश्मीर में, कर्नाटक को ऊनी किस्म के लिए जाना जाता है।
- उत्तराखंड खादी उत्पादों – हस्तनिर्मित एवं प्राकृतिक में निर्मित खादी व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला है।

आइसबर्ग A68

समाचार –

- विशाल हिमखंड A68, 2017 से अटलांटिक महासागर में बह रहा है। इस वर्ष, एक महासागरीय प्रवाह के कारण, हिमखंड को दक्षिण अटलांटिक महासागर डाल दिया गया था एवं तब से यह दक्षिण जॉर्जिया के दूरस्थ उप–अंटार्कटिक द्वीप की ओर बह रहा है। जो एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र (बीओटी) है। द्वीप के प्रचुर वन्य जीवन पर हिमखंड का प्रभाव हो सकता है।

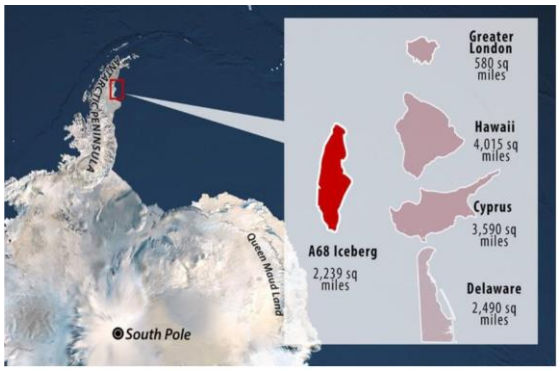

दक्षिण जॉर्जिया –

- दक्षिण जॉर्जिया दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है जो दक्षिण जॉर्जिया के ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र एवं दक्षिण सैंडविच द्वीप (SGSSI) का हिस्सा है। मुख्य बस्ती Grytviken है।

विवरण –

- आइसबर्ग ए 68 अंटार्कटिका से लगभग 5,800 वर्ग किमी के क्षेत्र के साथ फ्री–फ्लोटिंग बर्फ का सबसे बड़ा ब्लॉक है।
- हिमशैल समुद्र की धाराओं के साथ यात्रा करते हैं एवं या तो उथले पानी में फंस जाते हैं या खुद जमीन पर गिर जाते हैं।
- यूएस नेशनल आइस सेंटर (USNIC) ने पुष्टि की कि A68 से दो नए हिमखंडों को जन्म दिया था उन्हें A68E एवं A68F कहा जाता हैं एवं वे ट्रैक किए जाने के लिए पर्याप्त बड़े थे।
- यूएस नेशनल आइस सेंटर (USNIC) आइसबर्ग का नामकरण के लिए जिम्मेदार है, जिसे अंटार्कटिक क्वाड्रेंट जिसमें उन्हें स्पॉट किया था, के नाम पर रखा गया है।
- पारिस्थितिकीविदों के अनुसार, यदि हिमखंड द्वीप के पास फंस जाता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि पेंगुइन एवं सील को भोजन की तलाश में दूर की यात्रा करनी होगी, एवं कुछ के लिए इसका अर्थ यह हो सकता है कि वे अपने बच्चों के भुखों मरने से पहले उन तक भोजन ना पहुँचा पाए।
- दूसरी ओर, वहीं खुले समुद्र में फंसे हुए हिमशैलों के कुछ सकारात्मक परिणाम भी क्योंकि हिमशैल धूल ले जाते हैं जो महासागर प्लवक निषेचित करते हैं, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है।

सामान्य अध्ययन– II
शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

उत्तर प्रदेश धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश

समाचार –

- उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह द्वारा धार्मिक रूपांतरण का अपराधीकरण का अध्यादेश जारी किया।

अध्यादेश के अनुसार –

- यदि किसी महिला का धर्म परिवर्तन केवल विवाह के उद्देश्य से किया गया है तो विवाह का कानूनी नही माना जाएगा एवं जो लोग विवाह के बाद अपने धर्म को बदलना चाहते हैं, उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने की आवश्यकता होगी।
- इसमें एक प्रावधान यह भी जिसके तहत यदि कोई अपने मूल धर्म में वापस लौटता है, तो उसे रूपांतरण नहीं माना जाएगा।
- जबकि यह साबित करने कि 'धर्मांतरण जबरन नहीं किया गया है', की जिम्मेदारी आरोपी व्यक्ति एवं धर्मांतरण करने वाले पर होगी।
- कानून के उल्लंघन के मामले में, अध्यादेश में कहा गया है कि अदालत धर्मांतरण के शिकार व्यक्ति को आरोपी द्वारा देय उचित मुआवजा प्रदान करेगी जो जुर्माना के अलावा अधिकतम 5 लाख रुपये तक हो सकता है, का प्रावधान है।

- कोई भी व्यक्ति किसी धर्म से दुराचार, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, खरीद–फरोख्त या किसी धोखेबाजी के माध्यम से या विवाह करके या तो किसी धर्म से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धर्म परिवर्तन नहीं करेगा एवं न ही किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित करेगा।
- एक व्यथित व्यक्ति, उसके माता–पिता, भाई, बहन, या कोई अन्य व्यक्ति जो उससे संबंधित है / उसके द्वारा रक्त, विवाह या गोद लिये जाने का संबंध है द्वारा इस तरह के धर्मांतरण की प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।
- सामूहिक धार्मिक परिवर्तन के मामलों में, सामाजिक संगठनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, एवं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
- यदि पूर्व में अध्यादेश के तहत दोषी ठहराए गए लोग फिर से उसी अपराध के लिए पकड़े जाते हैं, तो उन्हें दोहरी सजा दी जाएगी।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित कुछ भी नहीं, इस अध्यादेश के तहत सभी अपराध सेशन कोर्ट द्वारा संज्ञेय एवं गैर–जमानती होंगे।

विवाह एवं धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट –

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि, राज्य एवं अदालतों के धार्मिक विश्वास का वयस्क के जीवन साथी चुनने में कोई दखल नही हैं एवं व्यस्कों का इसका पूर्ण अधिकार नहीं है।
- भारत एक 'स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक देश' है एवं प्यार तथा शादी करने के लिए एक वयस्क के अधिकार में राज्य द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का स्वतंत्रता पर 'द्रुतशीतन प्रभाव' है।
- विवाह की अंतरंगता गोपनीयता के एक प्रमुख क्षेत्र के अंर्तगत है, जो कि अनुल्लंघनीय एवं जीवन साथी की पसंद है, चाहे वह विवाह में हो या इसके बाहर, यह एक व्यक्ति की 'व्यक्तित्व एवं पहचान' का हिस्सा है।

स्वतंत्रता पर 'द्रुतशीतन प्रभाव' –

- प्रेम एवं शादी करने के एक वयस्क के अधिकार में राज्य द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का स्वतंत्रता पर 'द्रुतशीतन प्रभाव' कहलाता है।
- जीवन साथी चुनने के लिए किसी व्यक्ति का पूर्ण अधिकार कम से कम धार्मिक विश्वास के मामलों से प्रभावित नहीं होता है।

हादिया केस का फैसला, 2017

- न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने लिखा, पोशाक एवं भोजन के मामले, विचारों एवं विचारधाराओं के, प्यार एवं साझेदारी के पहचान के केंद्रीय पहलुओं के भीतर आते हैं। न तो राज्य एवं न ही कानून भागीदारों की पसंद तय कर सकते हैं या इन मामलों पर निर्णय लेने की प्रत्येक व्यक्ति की मुक्त क्षमता को सीमित कर सकते हैं।

के. एस. पुट्टुस्वामी या 'गोपनीयता' निर्णय, 2017

- संविधान पीठ ने कहा, व्यक्ति की स्वायत्तता जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने की क्षमता है।

लता सिंह केस, 1994

- शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत एक 'महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी अवधि' से गुजर रहा है एवं 'संविधान तभी मजबूत रहेगा जब हम अपनी संस्कृति की बहुलता एवं विविधता को स्वीकार करेंगे'।
- किसी प्रियजन के अंर्तधार्मिक विवाह से असंतुष्ट रिश्तेदार हिंसा या उत्पीड़न का सहारा लेने के बजाय 'सामाजिक संबंधों को काटने' का विकल्प चुन सकते हैं।

सोनी गेरी मामला, 2018

- उच्चतम न्यायालय ने 'माँ की किसी भी तरह की भावना या पिता की अहंता' के आगे झुकने के संबंध में न्यायाधीशों को 'सुपरगार्जियन' ना होने की चेतावनी दी।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 2020 के सलामत अंसारी–प्रियंका खरवार का मामला
- पसंद का साथी चुनने या रहने का अधिकार नागरिक के जीवन एवं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है (अनुच्छेद 21)।
- यह भी आयोजित किया गया कि शादी से पहले शादी के लिए धार्मिक रूपांतरण के विचार को बरकरार रखने के लिए अदालत के पहले के फैसले नियमानुसार अच्छे नहीं हैं।

क्या ऐसे कानून की आवश्यकता है?

1. नहीं – क्योंकि कई अन्य हालिया 'कानून' – मवेशियों के वध, विवाह एवं धार्मिक रूपांतरणों से संबंधित – मुसलमानों को लक्षित करते हैं, सामाजिक स्थान को साझा करने एवं समान नागरिक होने के अधिकार का हनन करते हैं।
   हाँ – हालाँकि, यह अभी भी राज्य द्वारा अतिक्रमण की अनुमति देता है, व्यक्तिगत कानूनों के विपरीत, अग्रिम में नोटिस जारी करने की मांग करने के बजाए, उप्र में धोखाधड़ी से धर्मांतरण की घटनाएँ बढ़ी हैं। तथा कथित तौर पर हनी ट्रेप के मामलों के लिए यह आवश्यक है।

निष्कर्ष –

1. उप्र के धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश युवा महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा कठिनाई से अर्जित स्वतंत्रता के लिए हानिकारक हैं।
2. अंर्तधार्मिक विवाह, कुल विवाहों के 2.5% से भी कम होते हैं, जो राज्य शक्ति एवं कानून को प्रमुख सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों के पीछे रखते हैं, जो विवाह को नियंत्रित करने वाले प्रतिगामी सामाजिक टुकड़ों को सशक्त बनाते हैं।
3. सभी महिलाओं के साथ एक ही तरह से दुर्व्यवहार करना एवं किसी व्यक्ति के पिछले धर्म को पुनः अपनाना गैरकानूनी नहीं है। इससे सांप्रदायिक हिंसा बढ़ सकती है।

कृषि विधेयक

समाचार –

- वर्तमान में तीन अधिनियमों – मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा अधिनियम, एवं आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम पर किसान उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, किसान (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) समझौता, के खिलाफ व्यापक किसान आंदोलन हो रहा है।

पृष्ठभूमि –

- राष्ट्रपति ने 27 सितंबर को तीन विवादास्पद कृषि विधेयकों पर अपनी सहमति दी जो पहले संसद द्वारा पारित किए गए थे।

अधिनियमों का विवरण –

- इन सुधारों से बुनियादी ढांचे के निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेश एवं राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों में कृषि उपज के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी।
- वे उन छोटे किसानों की मदद करने के लिए हैं, जिनके पास अपनी उपज के लिए या तो सौदेबाजी करने का कोई साधन नहीं है, ताकि खेतों की उत्पादकता में सुधार के लिए उन्हें बेहतर कीमत मिल सके या प्रौद्योगिकी में निवेश किया जा सके।
- कृषि बाजार अधिनियम किसानों को एपीएमसी 'मंडियों' के बाहर अपनी उपज बेचने की अनुमति देना चाहता है।
- किसानों को परिवहन पर प्रतिस्पर्धा एवं लागत में कटौती के माध्यम से बेहतर मूल्य मिलेंगे।
- अनुबंध खेती पर कानून किसानों को कृषि–व्यवसाय फर्मों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने की अनुमति देगा।
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज एवं आलू जैसी वस्तुओं को हटाने का प्रयास करता है। यह असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर स्टॉक–होल्डिंग की सीमा को समाप्त कर देगा।

कश्मीर पर इस्लामिक सहयोग का संगठन

समाचार –

- भारत ने जम्मू एवं कश्मीर पर तथ्यात्मक रूप से गलत एवं गैरवाजिब संदर्भ जोड़ने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) को 'दृढ़ता' से खारिज किया है।
- नियामे (नाइजर) में आयोजित ओआईसी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के 47 वें सत्र ने जम्मू–कश्मीर पर अपनी नीतियों को लेकर भारत का एक संदर्भ बनाया था।

इस्लामिक सहयोग संगठन

- चार महाद्वीपों में फैले 57 राज्यों की सदस्यता के साथ संयुक्त राष्ट्र के बाद इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) दूसरा सबसे बड़ा संगठन है।
- संगठन मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज है। यह विश्व के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना में मुस्लिम विश्व के हितों की रक्षा एवं संरक्षण का प्रयास करता है।
- संगठन की स्थापना 12 वीं रजब 1389 हिजरा (25 सितंबर 1969) को मोरक्को के रबात में हुई ऐतिहासिक समिट के एक फैसले के बाद की गई थी, जिसमें यरूशलेम पर कब्जे वाले अल–अक्सा मस्जिद की आपराधिक आगजनी हुई थी।
- 1970 में इसकी पहली बैठक जेद्दा में हुई, जिसमें जेद्दा में एक स्थायी सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
- ओआईसी के पास संयुक्त राष्ट्र एवं यूरोपीय संघ के स्थायी प्रतिनिधिमंडल हैं।
- ओआईसी की आधिकारिक भाषाएं अरबी, अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं।
- OIC ने मुस्लिमसमाज देशों के लिए सदस्यता आरक्षित की है। रूस, थाईलैंड एवं अन्य छोटे देशों के एक जोड़े को ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है।

भारत एवं ओ.आई.सी.

- बांग्लादेश में विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन 2018 के 45 वें सत्र में सुझाव दिया गया कि भारत को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया जाना चाहिए।
- 1969 में, भारत को रबात, मोरक्को में इस्लामिक देशों के सम्मेलन से आमंत्रित किया गया था।
- 2019 में, भारत ने ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में 'अतिथि सम्मान' के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की।

कश्मीर पर OIC का रुख –

- इसने कहा कि भारत सरकार के विशेष स्तर (2019 में) को निरस्त करने के निर्णय का उद्देश्य क्षेत्र की जनसांख्यिकीय एवं भौगोलिक संरचना को बदलना था।
- निरंतर नाकेबंदी एवं प्रतिबंधों के कारण मानव अधिकारों का हनन हुआ है।
- बयान ने उस समर्थन को स्वीकार किया जो पाकिस्तान संगठन के एजेंडे में कश्मीर मुद्दे को रखने के लिए प्रदान करता रहा है।
- 2018 में, ओआईसी सचिवालय ने भारतीय कब्जे वाले कश्मीर में भारत की सेनाओं द्वारा निर्दोष कश्मीरियों की हत्या की कड़ी निंदा की थी, प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलीबारी को एक आतंकवादी कार्य बताया।
- 2017 में OIC के सत्र में विदेश मंत्रियों ने कश्मीरी लोगों के लिए अटूट समर्थन की पुष्टि करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया था।

भारत की प्रतिक्रिया –

- भारत ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि OIC के पास भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर भी शामिल है जो भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य हिस्सा है।

भारत के नवीनतम कथन का महत्व –

- भारत ओआईसी के दोहरे मानक को तोड़ने का विश्वास करता है, जहां वह मानवाधिकारों के नाम पर पाकिस्तान के एजेंडे का समर्थन करता है। भारत के OIC के कई सदस्य देशों से अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं वे भारत को OIC के बयानों को नजरअंदाज करने के लिए मनाते हैं, लेकिन संयुक्त बयानों पर हस्ताक्षर करते हैं जो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान द्वारा तैयार किए जाते हैं।
- भारत इस मुद्दे को चुनौती भी देना चाहता है क्योंकि अमेरिका में जो बिदेन प्रशासन है जो कश्मीर में मानवाधिकारों के बारे में एक मजबूत दृष्टिकोण रख सकता है एवं ऐसे बयान जारी कर सकता है जो वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को जटिल बना सकते हैं।
- भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक गैर–सदस्यीय सदस्य की सीट लेने की तैयारी के साथ, वह अगले दो वर्षों में वैश्विक निकाय में इस मुद्दे को दफनाने एवं पाकिस्तान–सीमा पार आतंकवाद को सामने लाने के लिए अपने राजनयिक दबदबे एवं सद्भावना का उपयोग करना चाहता है।

महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल)

समाचार –

- अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अर्नब गोस्वामी द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने ट्वीट के लिए कलाकार रचिता तनेजा के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की सहमति दी है।

मुद्दा –

- कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा (ट्विटर पर) ने शीर्ष अदालत के खिलाफ कई चित्रण पोस्ट किए थे जिसे 'संस्था के अपमान' के रूप में देखा गया।
- तनेजा के चित्रण में अर्नब गोस्वामी को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी एवं सुप्रीम कोर्ट के साथ, गोस्वामी के साथ उक्ति 'तु जानता नहीं मेरा बाप कौन है' के रूप में चित्रित किया गया है, मानो कि सुप्रीम कोर्ट सत्तारूढ़ पार्टी के पक्षपाती है एवं भाजप किसी तरह अर्नब गोस्वामी की रक्षा करने में दिलचस्पी रखती है।

भारत के महान्यायवादी –

- भारत के अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं एवं भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक वकील हैं।
- वे केंद्रीय कार्यकारी का एक हिस्सा है।
- उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 (1) के तहत नियुक्त किया जाता है।
  – उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए।
  – उन्हें भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  –उन्होंने या तो किसी भारतीय राज्य के हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में या 10 वर्ष हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में पूर्ण किए होना चाहिए।
  – राष्ट्रपति की नजर में वे एक प्रख्यात न्यायविद भी हो सकते है।

शक्तियाँ एवं कार्य –

- अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को उसके द्वारा निर्दिष्ट कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए आवश्यक होते है। वे राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सौंपे गए अन्य कानूनी कर्तव्यों का पालन भी करते है।
- अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में दर्शकों के अधिकार के साथ–साथ संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, हालांकि वोट देने के लिए नहीं।
- भारत सरकार की ओर से सभी मामलों में अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों (मुकदमों, अपीलों एवं अन्य कार्यवाही सहित) में पेश होता है।
- वे संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
- अटॉर्नी जनरल ब्रीफ स्वीकार कर सकते हैं लेकिन सरकार के खिलाफ पेश नहीं हो सकते।
- वह आपराधिक कार्यवाही में किसी अभियुक्त का बचाव नहीं कर सकते है एवं सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी के निर्देशन को स्वीकार नहीं कर सकते है।
- अटॉर्नी जनरल को दो सॉलिसिटर जनरल एवं चार अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

अवमानना मामलों में पूर्व अनुमोदन का मामला क्या है –

- सर्वोच्च न्यायालय के लिए अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के अंतर्गत आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल की लिखित पूर्व सहमति आवश्यक है।

अदालती मामले की आपराधिक अवमानना लाने की प्रक्रिया?

- अदालतों की अवमानना अधिनियम, 1971 अदालत की अवमानना पर कानून को खारिज करता है। कानून की धारा 15 प्रक्रिया का वर्णन करती है कि अदालत की अवमानना के लिए मामला कैसे शुरू किया जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के मामले में, अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल, एवं उच्च न्यायालयों के मामले में, एडवोकेट जनरल, आपराधिक अवमानना का मामला शुरू करने के लिए अदालत के समक्ष एक प्रस्ताव ला सकते हैं।

अटॉर्नी जनरल को सहमति क्यों देनी पड़ती है?

- न्यायालय की आपराधिक अवमानना के मामलों में प्रक्रिया, जिसका अर्थ है कि ऐसी सामग्री का प्रकाशन जो न्यायालय की गरिमा या पक्षपात को कम करती है या न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप करती है, कानून के तहत एजी की सहमति आवश्यक है। शिकायत का संज्ञान लेने से पहले एजी की सहमति की आवश्यकता के पीछे उद्देश्य अदालत के समय को बचाना है।
- एजी की सहमति का अर्थ है कि तुच्छ याचिकाओं के खिलाफ सुरक्षा करना, क्योंकि यह माना जाता है कि एजी, अदालत के एक अधिकारी के रूप में, स्वतंत्र रूप से पता लगाएगा कि क्या शिकायत वास्तव में वैध है।

पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग

समाचार –

- केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 तक भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों की घोषणा की।
- सरकार अधिक प्रभावी कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित करने एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाने के लिए पुलिस स्टेशनों का चयन करती है।

चयन प्रक्रिया –

- चयन प्रधानमंत्री के निर्देशों के साथ–साथ पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।
- कच्छ, गुजरात में 2015 के सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री ने निर्देश दिया था कि थानों की ग्रेडिंग के लिए पैरामीटर निर्धारित किए जाएं एवं फीडबैक के आधार पर उनके प्रदर्शन का आकलन किया जाए।
- रैंकिंग में पुलिस स्टेशनों का निम्न पेरामीटरों पर परखा जाता है –
  – संपत्ति के अपराध
  – महिलाओं के खिलाफ अपराध
  – कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध
  – गुम व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति एवं लाशें
  – अंतिम पैरामीटर को इस वर्ष जोड़ा गया है।
- शीर्ष 10 पुलिस स्टेशन

1. मणिपुर, थौबल, नोंगपोकसेमई
2. तमिलनाडु, सलेम सिटी, AWPS Suramangalam
3. अरुणाचल प्रदेश, चांगलांग, खरसांग
4. छत्तीसगढ़, सूरजपुर, झिलमिल (भैया थाना)
5. गोवा, दक्षिण गोवा, सुंगम
6. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उत्तर एवं मध्य अंडमान, कालीघाट
7. सिक्किम, पूर्वी जिला, प्योंग
8. उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद, कंठ
9. दादरा एवं नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली, खानवेल
10. तेलंगाना, करीमनगर, जम्मीकुंटा टाउन पी.एस.

पुलिस की कार्यप्रणाली के मुद्दे –

- स्वीकृत पुलिस बल प्रति लाख व्यक्तियों पर 181 पुलिस है। हालांकि, 2016 में यह 137 था। इसने पुलिस बल पर काफी कार्यभार डाला है।
- वर्तमान में भारत में 5.5 लाख पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि स्वीकृत पुलिस बल का लगभग 24% खाली है।
- दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र ने प्रति व्यक्ति 222 पुलिस मानक की सिफारिश की है। यह स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत में एक औसत पुलिस आदमी के पास काम का बोझ है जो उसकी दक्षता एवं प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- कैग की रिपोर्टों के अनुसार राज्य पुलिस बलों के पास हथियारों की कमी है। रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान में क्रमशः 71% एवं 75% हथियारों की कमी थी।
- इसके अलावा, पुलिस थानों में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित धन का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया जाता है।

स्वास्थ्य बीमा योजना

समाचार –

- पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर, 2020 से राज्य की संपूर्ण जनसंख्या को कवर करने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार किया।
- यह योजना 2016 में शुरू की गई थी एवं यह राज्य की आबादी के ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बीच काफी लोकप्रिय है।
- यह माध्यमिक एवं तृतीयक देखभाल के लिए एक बुनियादी स्वास्थ्य कवर है जो प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक है।

स्वास्थ सथी योजना के मुख्य अंश –

- प्रत्येक परिवार, आयु वर्ग के बावजूद हर नागरिक को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
- यह माध्यमिक एवं तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक प्रति परिवार के लिए एक बुनियादी स्वास्थ्य कवर है।
- यह योजना राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है।
- राज्य की पूरी आबादी को कवर करने के लिए, प्रत्येक एवं प्रत्येक परिवार को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जहां उन्हें कैशलेस उपचार मिलेगा।
- सभी सरकारी एवं निजी अस्पताल स्वास्थ सथ्य के तहत आने वाले हैं।
- परिवारों के महिला अभिभावकों को कार्ड जारी किया जाएगा।
- राज्य सरकार के प्रतिनिधि हर घर जाकर ड्यूरे ड्यूरी पश्चिंबो सरकार की पहल यानी पश्चिम बंगाल सरकार के हर दरवाजे पर जाकर नामांकन प्रक्रिया शुरू करेंगे।
- इस योजना के लिए राज्य का वार्षिक खर्च लगभग 2,000 करोड़ रुपये होगा। वर्तमान में, यह 925 करोड़ रुपये है
- जो व्यक्ति किसी अन्य स्वास्थ्य योजना के तहत नामांकित नहीं हैं, वे स्वास्थ साठी योजना के तहत आने के लिए पात्र होंगे।

पृष्ठभूमि –

- पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को लागू नहीं किया है। पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव है। राज्य सरकार हाल ही में कई योजनाओं को शुरू कर रही है एवं विधानसभा चुनावों के समय में मौजूदा योजनाओं का विस्तार कर रही है।

विज्ञापनों पर सलाहपत्र

समाचार –

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स एवं अन्य पर विज्ञापनों पर एक एडवाइजरी जारी की है। दिशानिर्देश 15 दिसंबर से प्रभावी हो गए।

दिशा–निर्देशों के अनुसार

- कोई भी गेमिंग विज्ञापन 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्तिया जो 18 वर्ष से कम आयु का प्रतीत होता है को ऑनलाइन गेम खेलते हुए वास्तविक धन जीतते हुए या ऐसा करने का सुझाव देते हुए नही दिखा सकता है।
- इस तरह के हर गेमिंग विज्ञापन में यह खंडन होना चाहिए कि इस गेम में वित्तीय जोखिम का एक तत्व शामिल है एवं नशे की लत हो सकती है, इसलिए कृपया जिम्मेदारी से एवं अपने जोखिम पर खेलें।
- इस तरह के खंडन की विज्ञापन में 20 फीसदी से कम जगह नहीं होनी चाहिए।
- विज्ञापन को आय के अवसर या वैकल्पिक रोजगार विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
- विज्ञापन में यह भी सुझाव नहीं दिया जाना चाहिए कि गेमिंग गतिविधि में लगे व्यक्ति किसी भी तरह से दूसरों की तुलना में अधिक सफल है।

विज्ञापन मानक परिषद भारत –

- 1985 में स्थापित विज्ञापन मानक परिषद, भारत में विज्ञापन उद्योग का एक स्व–नियामक स्वैच्छिक संगठन है।
- यह एक गैर–सरकारी निकाय है।
- एएससीआई उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन में स्वप्रयोजन के कारण के लिए प्रतिबद्ध है।
- एएससीआई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि विज्ञापन स्व–नियमन के लिए अपने कोड के अनुरूप हों, जिसे देखने के दौरान विज्ञापनों को कानूनी, सभ्य, ईमानदार एवं सच्चा होना चाहिए एवं खतरनाक या हानिकारक नहीं होना चाहिए।

- ASCI प्रिंट, टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स, एसएमएस, ईमेल, इंटरनेट/वेब–साइट, उत्पाद पैकेजिंग, ब्रोशर, प्रचार सामग्री एवं बिक्री सामग्री के बिंदु आदि जैसे सभी मीडिया में शिकायतों को देखता है।

छठां भारत–सीएलएमवी बिजनेस कॉन्क्लेव 2020

समाचार –

- केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय एवं भारत उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित छठें भारत–सीएलएमवी बिजनेस कॉन्क्लेव 2020 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।
- कॉन्क्लेव का आयोजन 'रचनात्मक विकास के लिए निर्माण पुल' के तहत किया गया था।

सीएलएमवी देश –

- सीएलएमवी देश कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एवं वियतनाम हैं।
- यह संस्थान एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के भीतर अपनी नवीनतम, सबसे कम आय एवं पूर्व में बंद–अर्थव्यवस्था सदस्यों को शामिल करता है।
- सीएलएमवी आर्थिक मंत्रियों की बैठक के माध्यम से संघ के संचालन का एक तरीका है।
- देश विभिन्न व्यापारिक समझौतों के कारण यूरोपीय संघ एवं चीन एवं अन्य बाजारों के लिए बाजार पहुंच के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता हैं।
- चार देश तांबा, तेल, प्राकृतिक गैस, रत्न एवं सागौन जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधन रखते हैं।
- वे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं।
- पिछले दशक में, इन देशों के साथ भारत का व्यापार 1.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 10 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

मुख्य विचार –

- कॉन्क्लेव के दौरान, भारत ने सीएलएमवी देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखला पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
- कॉन्क्लेव के दौरान, भारत ने उल्लेख किया कि वह सीएलएमवी देशों के साथ कोविड–19 वैक्सीन साझा करने के लिए तैयार है।
- भारत एवं सीएलएमवी देशों के उद्यमों के साथ अपने उत्पादों एवं सेवाओं के प्रदर्शन के साथ 15 दिनों के लिए एक आभासी प्रदर्शनी होगी। निम्न उत्पाद एवं सेवाएँ शामिल होंगी –
  – कृषि (कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आदान, एवं संबद्ध सेवाएं)
  – विनिर्माण
  – प्रकाश उद्योग (ऑटोमोबाइल, कपड़ा, एवं मशीन टूल्स)
  – ऊर्जा एवं स्वच्छ ऊर्जा
  – इन्फ्रास्ट्रक्चर, परिवहन एवं रसद
  – हेल्थकेयर एवं फार्मास्यूटिकल्स
  – आईटी, कौशल एवं शिक्षा

अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA)

समाचार –

- बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA) पर हस्ताक्षर किए एवं दोनों देशों के बीच माल की एक सीमा तक शुल्क–मुक्त पहुंच की अनुमति दी। यह बांग्लादेश का पहला पहला पीटीए है जिसने विश्व के किसी भी देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं।

विवरण –

- दोनों देशों के बीच 50 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिह्नित करते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- पीटीए के तहत 100 बांग्लादेशी उत्पादों को भूटान में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा।
- भूटान से 34 वस्तुओं को बांग्लादेश में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा।
- जूट एवं जूट उत्पादों, बच्चे के कपड़े एवं सामान, पुरुषों की पतलून, जैकेट एवं ब्लेजर जैसे सामान बांग्लादेश से 100 वस्तुओं में से हैं, जिन्हें भूटान में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा।
- दूसरी ओर, भूटान से फलों का रस, प्राकृतिक शहद, गेहूं के आट, जेली एवं चूना पत्थर, क्वार्टजाइट आदि की बांग्लादेश में ड्यूटी फ्री पहुंच होगी।
- निर्यात में 7.56 मिलियन एवं बांग्लादेश में 42.09 मिलियन आयात के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा लगभग 50 मिलियन डॉलर है।
- बांग्लादेश को इंडोनेशिया एवं नेपाल जैसे देशों के साथ अगले वर्ष जून तक 11 एवं पीटीए एवं मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है।

अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA)

- अधिमान्य व्यापार क्षेत्र या अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA) को देशों के बीच आर्थिक एकीकरण का पहला चरण कहा जाता है।
- पीटीए में, भाग लेने वाले देश आपस में कुछ उत्पादों को तरजीह देते हैं। इसलिए, टैरिफ बाधाओं को कम कर दिया जाता है एवं गैर–ट्राफिक बाधाओं को कम कठोर बना दिया जाता है।

मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)

- जब भी कुछ देश एक साथ बैठते हैं एवं टैरिफ को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं, तो कोटा एवं आयात को प्राथमिकता दें (यदि सभी के बीच नहीं हैं) तो उनके बीच व्यापार किया जाने वाला सामान एवं सेवाएं एफटीए बना रही हैं।
- एक मुक्त–व्यापार क्षेत्र का उद्देश्य विनिमय के लिए बाधाओं को कम करना है ताकि व्यापार विशेषज्ञता, श्रम के विभाजन एवं तुलनात्मक लाभ के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण रूप से विकसित हो सके।
- एक मुक्त व्यापार समझौता दो देशों (द्विपक्षीय) या कई देशों (बहुपक्षीय) के बीच एक समझौता हो सकता है।
- एफटीए का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ मुफ्त है।

भारत में तस्करी रिपोर्ट 2019–20

समाचार –

- वित्त मंत्री ने 4 दिसंबर को राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के 63 वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया।
- इस अवसर पर, वित्त मंत्रालय ने स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019–20 जारी की जिसमें गोल्ड एवं विदेशी मुद्रा, नारकोटिक ड्रग्स, सुरक्षा, पर्यावरण एवं वाणिज्यिक धोखाधड़ी पर संगठित तस्करी के रुझान का विश्लेषण किया गया है।

विवरण –

- राजस्व खुफिया निदेशालय ने अब तक तस्करी के 412 मामलों का पता लगाया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019–20 में 1,949 करोड़ रुपये जब्त किए गए।
- राजस्व खुफिया निदेशालय ने 837 आर्थिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
- इसने सीमा शुल्क चोरी के 761 जटिल मामलों का खुलासा किया है। इससे 2,183 करोड़ रुपये की आय हुई।

सोना –

- रिपोर्ट के अनुसार, 2019–20 में भारत में लगभग 120 टन सोने की तस्करी की गई थी। यह विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार देश की वार्षिक मांग का 15% से 17% है।
- भूमि सीमाओं के माध्यम से सोने की तस्करी हाल के वर्षों में कई गुना बढ़ गई है।
- म्यांमार, नेपाल एवं बांग्लादेश जैसे अन्य देशों के साथ भारत की झरझरी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ सोने के तस्करों की मदद करती हैं।
- भारत एवं म्यांमार के बीच एक 16 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा जिसमें लोग बिना वीजा प्रतिबंध के यात्रा कर सकते हैं। यह क्षेत्र यदि सोने के तस्करों द्वारा उपयोग किया जाता है एवं यह चीन म्यांमार तस्करी नेटवर्क का एक हिस्सा भी है।

नारकोटिक्स ड्रग –

- अप्रैल 2019 में, असम राइफल्स की मदद से राजस्व खुफिया निदेशालय ने मणिपुर में एक गुप्त ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान लगभग 1 लाख मेथामफेटामाइन की गोलियां जब्त की गईं। इन गोलियों को आमतौर पर YaBa गोलियों के रूप में जाना जाता है।
- खुफिया निदेशालय ने वर्ष 2019–20 में नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट के तहत कुल 72 बरामदगी की। महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बरामदगी दर्ज की गई।

सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद –

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा अवैध सिगरेट बाजार बन गया है।
- 2019–20 में, राजस्व खुफिया निदेशालय ने 76.95 करोड़ रुपये की सिगरेट जब्त की है।

इस अवसर पर, डीआरआई उत्कर्ष सेवा सम्मान, 2020 को भारतीय राजस्व सेवा के 1961 बैच के अधिकारी शंकरन को प्रदान किया गया।

भारत–उजबेकिस्तान ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए

समाचार –

- भारत एवं उज्बेकिस्तान ने कई क्षेत्रों में सहयोग को अधिक व्यापक बनाने के लिए नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए एवं आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकाने, नेटवर्क एवं फंडिंग चैनलों को 'नष्ट' करके आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने की शपथ ली।
- दोनों राष्ट्रों ने द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर विचार–विमर्श किया एवं द्विपक्षीय निवेश संधि के जल्द समापन के लिए प्रयास करने पर सहमत हुए।
- जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनका उद्देश्य नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा एवं सूचनाओं के आदान–प्रदान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना है।

भारत–उज्बेकिस्तान –

- भारत एवं उज्बेकिस्तान ने 1 बिलियन अमरीकी डालर का वार्षिक व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत उन देशों के साथ भी अपने संबंधों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जहां चीन पहले ही अपनी भौगोलिक संदर्भता का लाभ उठाते हुए अतिक्रमण कर चुका है।
- भारत ने भारत से उजबेकिस्तान द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए 40 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की पेशकश की है।
- भारत एवं उज्बेकिस्तान ने सैन्य चिकित्सा एवं सैन्य शिक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए 2019 में रक्षा के क्षेत्र में तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
- जनवरी 2019 में, भारत एवं उज्बेकिस्तान ने भारत को यूरेनियम की आपूर्ति की लंबी अवधि के लिए एक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। उजबेकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सातवां सबसे बड़ा निर्यातक है।
- कजाकिस्तान के बाद, उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम निर्यात करने वाला दूसरा मध्य एशियाई देश है।

डस्टलिक 2019 –

- यह भारत एवं उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। पहला डस्टलिक सैन्य अभ्यास 2019 में आयोजित किया गया था।

आसियान प्लस रक्षा मंत्रियों की बैठक

समाचार –

- भारत के रक्षा मंत्री ने 14 वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (ADMM) प्लस हनोई, वियतनाम में ऑनलाइन आयोजित की। इसने ADMM प्लस की 10 वीं वर्षगांठ को चिह्नित किया।

एडीएमएम–प्लस के बारे में

- एडीएमएम–प्लस आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ) के लिए एक मंच है एवं यह क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं विकास के लिए सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए आठ संवाद सहयोगी है।
- ADMM– प्लस देशों में दस आसियान सदस्य राज्य एवं आठ प्लस देश, अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- इस वर्ष एडीएमएम–प्लस की अध्यक्षता वियतनाम ने की।
- इसका उद्देश्य अधिक संवाद एवं पारदर्शिता के माध्यम से रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ावा देना है।
- सिंगापुर में 2007 में द्वितीय आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (ADMM) ने ADMM–Plus की स्थापना के लिए एक संकल्प को अपनाया।
- पहला एडीएमएम–प्लस 2010 में हनोई, वियतनाम में बुलाया गया था।

बैठक के मुख्य आकर्षण –

- यह बैठक उस समय हुई जब भारत एवं चीन लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ एक सैन्य गतिरोध में लगे हुए हैं, एवं दक्षिण चीन सागर में तनाव जारी है।
- भारत ने बैठक में कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के भविष्य को स्वतंत्रता, समावेशिता एवं खुलेपन के मूल सिद्धांतों के आधार पर क्षेत्र में चुनौतियों का सामूहिक रूप से जवाब देने की उनकी क्षमता से परिभाषित किया जाएगा।

चुनौतियाँ –

- नियम आधारित आदेश, समुद्री सुरक्षा, साइबर से संबंधित अपराध एवं आतंकवाद के लिए खतरा।
- चरित्र में चुनौतियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं जिसके लिए ADMM– प्लस देशों के बीच सैन्य–से–सैन्य बातचीत एवं सहयोग की आवश्यकता है।

आसियान –

- क्षेत्रीय संगठन जो एशिया–प्रशांत के बाद के औपनिवेशिक राज्यों के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।
- अंतर–सरकारी संगठन, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के दस देश शामिल हैं, जो अंतर–सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है एवं एशिया में इसके सदस्यों एवं अन्य देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक एकीकरण प्रदान करता है।
- आसियान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास में तेजी लाना एवं उस सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास के माध्यम से है।

इस्लामवाद के खिलाफ फ्रांस का कानून

समाचार –

- फ्रांसीसी मंत्रिमंडल ने एक प्रारूप कानून पेश किया जो 'कट्टरपंथी इस्लामवाद' को लक्षित करता है। हालांकि शब्द 'इस्लामवादी' पाठ का हिस्सा नहीं है।
- यह विधेयक हाल के वर्षों में कई आतंकी हमलों के बाद आया है।
- इसे स्कूल के शिक्षक सैमुअल पैटी की अक्टूबर की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। इसने चिंता जताई है कि इससे फ्रांस का मुस्लिम समुदाय, यूरोप में सबसे बड़ा है, कलंकित हो सकता है।

बिल की विशेषताएं –

- कानून में कई उपायों की परिकल्पना की गई है जिसमें स्कूली शिक्षा सुधार शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुस्लिम बच्चे स्कूल बीच में ना छोड़े।
- इसका उद्देश्य उपदेशकों एवं मस्जिदों पर सख्त नियंत्रण प्रदान करना है।
- कानून ऑनलाइन घृणा अभियान के खिलाफ नियम प्रदान करेगा।
- जब कानून लागू होता है, तो फ्रांसीसी मस्जिदें अपनी गतिविधियों, विशेष रूप से वित्तपोषण पर निगरानी बढ़ाएंगी।
- कानून के तहत फ्रांसीसी सरकार पूजा स्थलों को बंद करने के लिए अधिक से अधिक शक्तियों के साथ सशक्त होगी। पूजा के ये स्थान वे हैं जो सार्वजनिक सब्सिडी प्राप्त करते हैं। यदि वे लैंगिक समानता जैसे गणतंत्रीय सिद्धांतों के खिलाफ जाते हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा।
- चरमपंथी PUTSCH द्वारा लक्षित किए जा रहे सामुदायिक नेताओं को कानून के तहत संरक्षण प्राप्त होगा। PUTSCH किसी सरकार को उखाड़ फेंकने का एक हिंसक प्रयास है।
- कानून तीन वर्ष से अधिक के बच्चों के होमस्कूलिंग को पूर्णतः समाप्त कर देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से, माता–पिता उन्हें भूमिगत इस्लामी संरचनाओं में भर्ती करते हैं।
- कानून कौमार्य प्रमाण पत्र जारी करने वाले डॉक्टरों को दंडित करेगा।
- कानून अधिकारियों को बहुविवाह आवेदकों को निवास परमिट देने से प्रतिबंधित करेगा।

- कानून अपनी शादी से पहले जोड़ों को अलग से साक्षात्कार करने की अनुमति देता है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या वे शादी के लिए मजबूर हैं।

एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी (APVAX)

समाचार –

- एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में विकासशील देशों को वैक्सीन की खरीद एवं वितरित करने के लिए समान समर्थन प्रदान करने के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस सुविधा शुरू की है।

सुविधा का विवरण –

- यह एशिया में विकासशील देशों का समर्थन करेगा एवं घातक वायरस के खिलाफ टीकों की खरीद के प्रयासों में लगाएगा। यदि किसी देश को APVAX के तहत वित्त प्राप्त करना है, तो उसे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए –
- – इसे COVAX के माध्यम से खरीदा जाना चाहिए।
- – इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पूर्व निर्धारित किया जाना चाहिए
- – इसे कड़े नियामक प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए।

वित्तीय सहायता –

- बैंक ने APVAX योजना के लिए 9 बिलियन USD आवंटित किए हैं।
- इससे पहले, एशियाई विकास बैंक ने पहले बैंक के व्यापार एवं आपूर्ति श्रृंखला वित्त कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 500 मिलियन यूएसडी वैक्सीन आयात सुविधा को मंजूरी दी थी।
- बैंक ने कोविड–19 टीकों के आयात में निजी क्षेत्रों के साथ 1 बिलियन अमरीकी डालर के कोफिनेंस को आवंटित किया।
- अप्रैल 2020 में, ADB ने कोविड–19 महामारी के प्रभावों को दूर करने एवं त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए विकासशील देशों को समर्थन देने के लिए 20 बिलियन अमरीकी डालर का अनुमोदन किया।
- बैंक कोविड–19 महामारी प्रतिक्रिया विकल्प का समर्थन करने के लिए 14.9 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए प्रतिबद्ध है।
- नवंबर 2020 में, ADB ने सिस्टम स्थापित करने के लिए 20.3 मिलियन USD तकनीकी सहायता की घोषणा की, जो टीकों के कुशल एवं न्यायसंगत वितरण को सक्षम करेगा।

COVAX -

- COVAX विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू किए गए अधिनियम त्वरक के तीन स्तंभों में से एक है।
- COVAX सुविधा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विश्व के सभी लोगों को कोविड–19 वैक्सीन के बराबर पहुंच मिलेगी।
- सुविधा का प्रारंभिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2021 के अंत तक दो बिलियन खुराक उपलब्ध हों।
- यह जीएवीआई (ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन) एवं गठबंधन फॉर एपिडेमिक प्रिपरेशननेस इनोवेशन (सीईपीआई) द्वारा सह–नेतृत्व किया गया है।

एसीटी एक्सीलरेटर –

- यह सहयोग का एक ढांचा है जिसका उद्देश्य कोविड–19 वैक्सीन के उत्पादन, विकास एवं न्यायसंगत पहुंच में तेजी लाना है। अधिनियम एसीटी एक्सीलरेटर, फ्रांस एवं यूरोपीय आयोग द्वारा शुरू किया गया था। इसे तीन मुख्य स्तंभों पर बनाया गया है, जिनका नाम थेरैपटिक्स, वैक्सीन (COVAX) एवं डायग्नोस्टिक्स है।

मोटर वार्षिक रिपोर्ट

समाचार –

- बीमा सूचना ब्यूरो ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2019 तक सड़क पर कुल वाहनों का लगभग 57 प्रतिशत बिना लाइसेंस के थे। बीमा नियामक IRDAI द्वारा स्थापित बीमा सूचना ब्यूरो (IIB) को अपनी मार्च 2020 की रिपोर्ट को अंतिम रूप देना बाकी है।

विवरण –

- भारत विश्व में सबसे बड़े ऑटो बाजारों में से एक है, जहाँ सालाना 20 मिलियन से अधिक गाड़ियाँ बिकती हैं।
- भारत उन देशों में भी शामिल है, जहां सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं एवं मौतें होती हैं।
- IIB के अनुसार, 31 मार्च, 2019 तक भारत में सड़क पर 23.12 करोड़ से अधिक वाहन, लगभग 57 प्रतिशत बिना लाइसेंस के थे, 2017–18 में, सड़क पर लगभग 21.11 करोड़ वाहनों में से 54 प्रतिशत वाहन बिना लाइसेंस के थे।
- बिना लाइसेंस के वाहनों में बड़े पैमाने पर दोपहिया वाहन शामिल हैं।
- कारों का बीमा काफी हद तक किया जाता है, जिसमें बिना लाइसेंस के वाहनों संख्या लगभग 10 प्रतिशत कम होती है।
- पहले वर्ष के बाद लगभग 52 प्रतिशत वाहन अपने बीमा को नवीनीकृत नहीं करते हैं – बीमा पॉलिसी के पहले नवीनीकरण के समय ज्यादातर दोपहिया वाहन बीमा के दायरे से बाहर हो जाते हैं।
- रिपोर्ट किए गए तीसरे पक्ष के दावों की कुल संख्या चालू वित्त वर्ष के लिए लगभग 3.25 लाख थी।
- कुल मिलाकर, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश ने मिलकर वित्त वर्ष 2018–19 में कुल तीसरे पक्ष के दावों का दो–तिहाई योगदान दिया।
- केरल में, कुल तीसरे पक्ष के दावों का लगभग 86 प्रतिशत चोटों के लिए था, जबकि बिहार में लगभग 80 प्रतिशत मौतों के लिए था।
- मृत्यु दावों के लिए उच्चतम औसत केरल में था, एवं बिहार में सबसे कम था।
- केंद्रशासित प्रदेशों एवं दक्षिणी राज्यों में दूसरों की तुलना में एक उच्च औसत है।

मोटर वाहन अधिनियम, 2019 –

- मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के अनुसार, सभी वाहनों का तीसरे पक्ष के वाहन बीमा पॉलिसी के साथ बीमा होना अनिवार्य है।
- थर्ड–पार्टी या लायबिलिटी इंश्योरेंस तीसरे पक्ष के नुकसान या उनकी संपत्ति को नुकसान या मृत्यु की विकलांगता के कारण उत्पन्न होने वाले कानूनी दायित्व को कवर करता है।

- जब एक अनजाने वाहन की दुर्घटना होती है, तो मृत या घायल व्यक्तियों के परिजनों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। क्षतिग्रस्त वाहनों का कोई मुआवजा नहीं है।

भारत में मोटर बीमा –

- मोटर सामान्य बीमा उद्योग में व्यापार की सबसे बड़ी लाइन है, जिसमें सकल अंडरराइट प्रीमियम का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है।
- छह राज्यों – महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात एवं दिल्ली ने कुल नीतियों एवं दावों का लगभग 50 प्रतिशत योगदान दिया।

IRDAI -

- भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) एक स्वायत्त, वैधानिक निकाय है जो भारत में बीमा एवं पुर्न बीमा उद्योगों को विनियमित करने एवं बढ़ावा देने के साथ काम करता है।
- यह बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा गठित किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा पारित संसद का एक अधिनियम है।
- एजेंसी का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है, जहां यह 2001 में दिल्ली से स्थानांतरित हुआ।
- IRDAI एक 10–सदस्यीय निकाय है, जिसमें भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक एवं चार अंशकालिक सदस्य शामिल हैं।

सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा –

- ब्रासीलिया घोषणा डब्ल्यूएचओ एवं भागीदारों को सड़क यातायात दुर्घटनाओं एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए लक्ष्यों के विकास की सुविधा के लिए प्रोत्साहित करती है, एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित एसडीजी लक्ष्यों से जुड़े संकेतकों की परिभाषा एवं उपयोग का समर्थन करती है।

पहला त्रिपक्षीय कार्य समूह

समाचार –

- चाबहार पोर्ट के संयुक्त उपयोग पर भारत, ईरान एवं उजबेकिस्तान के बीच पहली त्रिपक्षीय कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई।

विवरण –

- बैठक के दौरान, प्रतिभागियों ने व्यापार एवं पारगमन उद्देश्यों के लिए चाबहार पोर्ट के संयुक्त उपयोग एवं क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर चर्चा की।
- सभी पक्षों ने कोविड महामारी के दौरान मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए चाबहार बंदरगाह द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया।
- सभी पक्षों ने जनवरी 2021 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शिखर सम्मेलन के अवसर पर 'चाबहार दिवस' आयोजित करने के भारत के प्रस्ताव का स्वागत किया।

चाबहार बंदरगाह –

- चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर दक्षिण–पूर्वी ईरान में स्थित है।
- दिसंबर 2018 में, भारत ने पोर्ट के संचालन को संभाला।
- भारत ने चाबहार बंदरगाह एवं जाहेदान के बीच उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे के हिस्से के रूप में एक रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किया।
- चाबहार बंदरगाह चीन द्वारा पाकिस्तान में बनाए गए ग्वादर पोर्ट से लगभग 170 किमी दूर है।

चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- ईरान के साथ व्यापार संबंधों, राजनयिक संबंधों एवं सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना।
- पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे का प्रवेश द्वार होगा जो रूस, यूरोप, मध्य एशिया, ईरान एवं भारत को जोड़ने वाली सड़क, रेल एवं समुद्री मार्गों का एक संयोजन है।
- यदि आवश्यकता पड़ी तो भारत इस बंदरगाह से मानवीय कार्रवाई कर सकता है।
- यह बंदरगाह पाकिस्तान में चीन द्वारा संचालित ग्वादर बंदरगाह से सिर्फ 170 किमी दूर है, इसलिए यह बंदरगाह भारतीय नौसेना एवं रक्षा प्रतिष्ठान के लिए रणनीतिक महत्व का होगा।

सैन इसिड्रो मूवमेंट

समाचार –

- सैन इसिड्रो मूवमेंट (MSI) क्यूबा में सत्तावादी शासन के खिलाफ चल रहा विरोध है।

क्यूबा का सैन इसिड्रो मूवमेंट (MSI) –

- डिक्री 349 के माध्यम से राज्य की कलात्मक कार्यों पर सेंसरशिप के जवाब में 2018 में सैन इसिड्रो आंदोलन शुरू हुआ।
- डिक्री संस्कृति मंत्रालय को किसी भी सांस्कृतिक गतिविधि को बंद करने में सक्षम बनाती है जिसे वह अनुमोदित नहीं करता है।
- डिक्री का विरोध करने के लिए, कलाकार, कवि, पत्रकार और कार्यकर्ता सैन इसिड्रो में एकत्रित हुए, जो एक अश्वेत–बहुमत वाला इलाका है, जो हवाना के सबसे गरीब एवं सांस्कृतिक रूप से सक्रिय वार्डों में सबसे गरीब है, और जो ओल्ड हवाना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है।

आंदोलन कैसे बढ़ा?

- 2015 में, क्यूबा ने यूएसए के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसने एमएसआई प्रदर्शनकारियों को अधिक इंटरनेट स्वतंत्रता दी।
- प्रदर्शनकारी इंटरनेट पर अपने संदेशों को बढ़ाने और जोड़ने में कामयाब रहे।
- क्यूबा में सरकार संचार के सभी तरीकों को नियंत्रित करती है और किसी भी राजनीतिक विरोध की अनुमति नहीं है।
- इस प्रकार, इंटरनेट स्वतंत्रता ने विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचने में आंदोलन की मदद की।

वर्तमान परिदृश्य–

- क्यूबा सरकार ने दुनिया भर में आंदोलन की लोकप्रियता के बावजूद एमएसआई को 'यांकी साम्राज्यवाद' कहने की आलोचना जारी रखी।

हवाना –

- यह क्यूबा की राजधानी है। इसके अलावा, यह देश का सबसे बड़ा प्रांत, प्रमुख बंदरगाह तथा एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र है। यह चौथा सबसे बड़ा कैरेबियन महानगरीय शहर क्षेत्र है।

ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स (मानव विकास सूचकांक) –

समाचार –

- भारत इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में दो रैंक पिछे चला गया तथा 189 देशों की सूची में 131 वें स्थान पर रहा।

मुख्य विचार –

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने पहली बार, प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और उसके भौतिक पदचिह्न के कारण होने वाले प्रभाव को प्रतिबिंबित करने के लिए एक नए माप की शुरुआत की, जो माल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन, धातु और अन्य संसाधनों और सेवाओं की खपत की मात्रा को मापता है।

Miles to go

Though India improved its absolute value of the Human Development Index (0.645 in 2019 from 0.642 the previous year), it dropped a place in the overall ranking

Country	HDI rank (2019)	Change from 2018
Russia	52	-3
Sri Lanka	72	1
Brazil	84	0
China	85	2
South Africa	114	1
India	**131**	**-2**
Bangladesh	133	1
Nepal	142	1
Pakistan	154	0

HDI की प्रमुख खोजें –

- नॉर्वे सूचकांक में सबसे ऊपर है, इसके बाद आयरलैंड तथा स्विट्जरलैंड हैं। हांगकांग एवं आइसलैंड शीर्ष पांच को पूर्ण करते हैं।
- भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, कंबोडिया, केन्या तथा पाकिस्तान 189 देशों के बीच 120 और 156 की रैंक के साथ मध्यम मानव विकास वाले देशों के अंतर्गत आते हैं।
- ब्रिक्स समूह में, रूस मानव विकास सूचकांक में 52, ब्राजील 84 और चीन 85 वें स्थान पर था।
- क्रय शक्ति अनुपात (PPP) के आधार पर भारत की सकल राष्ट्रीय आय (GNI) प्रति व्यक्ति, 2018 में $ 6,829 से गिर कर 2019 में $ 6,681 हो गई।
- 2019 के लिए भारत का एचडीआई मूल्य 0.645 है, जिसने देश को मध्यम मानव विकास श्रेणी में डाल दिया है, जो इसे 131 वे स्थान पर रखता है।
- 1990 एवं 2019 के बीच, भारत का HDI मूल्य 0.429 से बढ़कर 0.645, अर्थात 50.3% बढ़ गया।
- 1990 तथा 2019 के बीच, जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा में 11.8 वर्ष की वृद्धि हुई, स्कूली शिक्षा के वर्ष में 3.5 वर्ष की वृद्धि हुई, तथा अपेक्षित विद्यालयिन वर्षों में 4.5 वर्षों की वृद्धि हुई। 1990 तथा 2019 के बीच भारत की जीएनआई प्रति कैपिटा में लगभग 273.9% की वृद्धि हुई।
- पेरिस समझौते के तहत, भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33–35% कम करने एवं 40% विद्युत शक्ति 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का संकल्प लिया।

क्रय शक्ति समता (या अनुपात)

- क्रय शक्ति समता (पीपीपी) विभिन्न देशों में कीमतों का एक माप है जो देशों की मुद्राओं की निरपेक्ष क्रय शक्ति की तुलना करने के लिए विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों का उपयोग करता है।

मानव विकास सूचकांक –

- मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) जीवन प्रत्याशा, शिक्षा (साक्षरता दर, विभिन्न स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात) एवं शुद्ध उपस्थिति अनुपात, एवं प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र समग्र सूचकांक है, जो देशों को चार स्तरों में बांटने के लिए उपयोग किया जाता है।
- एचडीआई की उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा उत्पादित वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट में पाई जाती है।
- ये 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा तैयार किए गए एवं लॉन्च किए गए थे, एवं राष्ट्रीय आय लेखांकन से विकास अर्थशास्त्र का ध्यान लोगों की नीतियों पर केंद्रित करने का स्पष्ट उद्देश्य था।

यूनेस्को की भारत में 2020 की शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट

समाचार –

- भारत के लिए यूनेस्को स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2020 – तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी), वस्तुतः यूनेस्को नई दिल्ली द्वारा शुरू किया गई पहल है।
- रणनीति सतत विकास लक्ष्य एवं शिक्षा के लिए 2030 कार्ययोजनाओं के साथ संरेखण में है।
- शिक्षा स्थिती रिपोर्ट का दूसरा संस्करण तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (TVET) पर केंद्रित है।

लक्ष्य –

- रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में कौशल विकास से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों को बढ़ाने एवं प्रभावित करने के लिए एक संदर्भ उपकरण के रूप में सेवा करना है।

सिफारिशें –

- शिक्षार्थियों एवं उनकी आकांक्षाओं को व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के केंद्र में रखें।
- शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र बनाएं।
- अपस्किलिंग, री–स्किलिंग एवं आजीवन सीखने पर ध्यान दें।
- विकलांग एवं वंचित शिक्षार्थियों, महिलाओं के लिए टीवीईटी की समावेशी पहुंच सुनिश्चित करना।
- व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के डिजिटलकरण का व्यापक विस्तार।
- मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में संलग्न होकर आजीविका उत्पन्न करने के लिए स्थानीय समुदायों का समर्थन करें।
- सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के साथ बेहतर संरेखित करें।
- टीवीईटी के वित्तपोषण के नवीन मॉडल तैनात करें
- बेहतर योजना एवं निगरानी के लिए साक्ष्य–आधारित अनुसंधान का विस्तार करें।
- अंतर–मंत्रालयी सहयोग के लिए एक मजबूत समन्वय तंत्र स्थापित करे।

रिपोर्ट का विवरण –

- रिपोर्ट को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई के शोधकर्ताओं की एक अनुभवी टीम द्वारा यूनेस्को नई दिल्ली के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है।
- तकनीकी एवं वित्तीय साझेदार–अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन (एआईएफ), महिलाओं, बच्चों एवं युवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ, भारत के वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

यूनेस्को –

- यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है।
- यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना चाहता है।
- यूनेस्को के कार्यक्रम एजेंडा, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाये गये, 2030 में परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान करते हैं।
- इस भावना में, यूनेस्को लोगों को घृणा एवं असहिष्णुता से मुक्त वैश्विक नागरिक के रूप में जीने में मदद करने के लिए शैक्षिक उपकरण विकसित करता है। यूनेस्को प्रत्येक बच्चे एवं नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए कार्य करता है।

आंध्र प्रदेश में संवैधानिक त्रूटि

समाचार –

- शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी कि क्या राज्य मशीनरी में संवैधानिक त्रूटि है या नहीं, एवं क्या राष्ट्रपति शासन की घोषणा की आवश्यकता है, इसकी न्यायिक जांच शुरू हो जाएगी।
- उच्च न्यायालय का 'अभूतपूर्व' आदेश, न्यायिक हिरासत में या जमानत पर रिहा किए गए व्यक्तियों के रिश्तेदारों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं का फैसला करते हुए आया।
- उच्च न्यायालय ने राज्य के वकील से कहा था कि वह 'आंध्र प्रदेश राज्य में मौजूद परिस्थितियों में निर्णय लेने में सहायता करने के लिए राज्य के वकील को बुलाए, अदालत यह पता लगा सकती है कि राज्य में संवैधानिक त्रूटि है या नहीं'।
- शीर्ष अदालत ने जांच को अत्यधिक परेशान करने वाला पाया। इसलिए इसने आदेश को जारी रखने का फैसला किया।
- सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय के अवलोकन ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है।

सू मोटो संज्ञान एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है किसी सरकारी एजेंसी, अदालत या अन्य केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा अपने दम पर की गई कार्रवाई।

आंध्र सरकार की प्रतिक्रिया

- सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय के अवलोकन ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन किया है।
- संवैधानिक ढांचे के तहत, किसी राज्य में संवैधानिक त्रूटि है या नही यह तय करना अदालतों का कार्य नहीं है।
- उक्त शक्ति को विशेष रूप से एक अलग संवैधानिक प्राधिकरण को सौंपा गया है जो कि ठीक भी है।
- यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि संवैधानिक अदालतों के पास यह निर्धारित करने के लिए कोई न्यायिक रूप से खोजे जाने योग्य एवं प्रबंधनीय मानक नहीं हैं कि क्या कोई संवैधानिक त्रूति हुई है," याचिका ने कहा।

अनुच्छेद 356 –

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को संघ के किसी भी राज्य की कार्यकारी एवं विधायी शक्तियों को वापस लेने का अधिकार देता है "यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है।

- संवैधानिक मशीनरी में त्रूटि का निर्धारण किसी भी समय राष्ट्रपति या राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, या स्वप्रेरणा से, किया जा सकता है।
- दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित, राष्ट्रपति शासन, 6 महीने तक जारी रह सकता है। इसे संसद की मंजूरी के साथ अधिकतम 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

मूल संरचना सिद्धांत –

- संविधान में सिद्धांतों एवं मूल्यों की एक बुनियादी संरचना है, जिसे कार्यपालिका के किसी भी अधिनियम द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
- संविधान की मूल विशेषताओं को न्यायपालिका द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
- इस प्रकार सिद्धांत संवैधानिक संशोधनों एवं कृत्यों की समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का आधार बनाते है।
- संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन इसकी 'मूल संरचना' को नष्ट नहीं कर सकती है।

इन 'बुनियादी सुविधाओं' में से प्रमुख निम्नलिखित हैं –

- मौलिक अधिकार
- प्रस्तावना
- संविधान की सर्वोच्चता
- सरकार का एक गणतंत्रात्मक एवं लोकतांत्रिक रूप
- संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र
- शक्तियों के पृथक्करण का अनुरक्षण
- संविधान का संघीय चरित्र
- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में निहित एक कल्याणकारी राज्य बनाने का जनादेश
- भारत की एकता एवं अखंडता का रखरखाव
- देश की संप्रभुता
- भारत की संप्रभुता
- राजनीति का लोकतांत्रिक चरित्र
- देश की एकता
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यक विशेषताएं
- कल्याणकारी राज्य बनाने का जनादेश
- एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य
- सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का प्रावधान
- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास एवं पूजा की स्वतंत्रता
- स्थिति एवं अवसर की समानता

स्टॉपगैप फंडिंग बिल

समाचार –

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टॉपगैप फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर किए। यह बिल कानून निर्माताओं को 900 बिलियन अमरीकी डालर के सहायता पैकेज के बारे में चल रही बातचीत में कुछ मुद्दों को सुलझाने के लिए दो और दिन प्रदान करता है।

विवरण –

- एक स्टॉपगैप फंडिंग बिल का उपयोग अमेरिकी सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि यह विनियोग अधिनियम की समय सीमा के बाद संघीय कार्यक्रम को चलाने के लिए धन से बाहर न चला जाए।
- एक वित्तीय वर्ष में, अमेरिकी कांग्रेस 12 विनियोग अधिनियम पारित करती है जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अमेरिकी ट्रेजरी से खर्च करने के लिए बजटीय अधिकार देता है।
- इन अधिनियमों की एक समय सीमा है एवं धन का उपयोग इसके बाद नए दायित्वों को संबोधित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। जब कांग्रेस सरकार को वित्त पोषित करने में विफल रहती है, तो एक सरकारी शटडाउन घोषित किया जाता है एवं सभी गैर–जरूरी सेवाओं को रोक दिया जाता है।

फेडरल फंडिंग की समय सीमा कैसे समाप्त होती है?

- अमेरिका में वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान, कांग्रेस बारह वार्षिक विनियोग अधिनियम पारित करती है जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए यूएस ट्रेजरी से धन खर्च करने के लिए बजट प्राधिकरण प्रदान करती है।
- नए दायित्वों को पूर्ण करने के लिए धन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, फंड निर्दिष्ट समय सीमा के बाद समाप्त हो जाते हैं।

सरकारी शटडाउन क्या है?

- गवर्नमेंट शटडाउन तब होता है जब कांग्रेस सरकार को फंड देने में विफल रहती है।
- ऐसे परिदृश्य में, अमेरिकी सरकार सभी गैर–जरूरी सेवाओं को रोक देती है। दूसरी ओर, आवश्यक सेवाएं जैसे पुलिस
- विभाग, सशस्त्र बल आदि कार्य जारी हैं।

जनता पर प्रभाव –

- संयुक्त राज्य में सरकारी शटडाउन के परिणामस्वरूप कई सौ सरकारी कर्मचारियों के लिए मुसीबत खड़ी होती है। सरकारी गतिविधियों में कमी ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है।

बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020

समाचार –

- केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने एवं चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति जैसे सेवा के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है।
- नियमों में बिजली वितरण फर्मों के लिए सेवाओं के अनिवार्य मानकों को बनाए नहीं रखने पर दंड का प्रावधान है।

पृष्ठभूमि –

- मंत्रालय ने सितंबर में विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बिजली उपभोक्ताओं के लिए मसौदा अधिकारों का एक सेट प्रकाशित किया, जिसमें एक उपभोक्ता चार्टर है। नवीनतम नियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाते हैं एवं उनके लिए नए आपूर्ति अधिकार पेश करते हैं।

विवरण –

- नियमों का कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करेगा कि नए बिजली कनेक्शन, रिफंड एवं अन्य सेवाएं समय–सीमा में दी जाएं।

- नियमों का लक्ष्य लगभग 300 मिलियन मौजूदा एवं भावी उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना है।
- नीति में पर्याप्त बिजली आपूर्ति की व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में लाइसेंस निलंबित करने का प्रस्ताव है।
- उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति में व्यवधान के मामले में दंड का प्रावधान है।

बिल की मुख्य विशेषताएं –

- विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020, कनेक्शन के लिए समयबद्ध एवं सरलीकृत प्रक्रिया लाते हैं, 60 दिनों या अधिक की देरी के साथ सेवारत बिलों पर 2% से 5% छूट।
- यह 1,000 रुपये या अधिक के सभी बिलों के भुगतान की ऑनलाईन कर सकने की अनुमति देता है।

प्रोज़्युमर –

- नए नियम के तहत प्रोज़्युमर नामक की एक नई श्रेणी की पहचान की गई है।
- प्रोज़्युमर वे उपभोक्ता हैं जिन्हें स्व–उपयोग के लिए बिजली का उत्पादन करने एवं ग्रिड से अधिक इंजेक्शन लगाने का अधिकार है।
- वे उपभोक्ता भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने छत पर इकाइयों लगवाई है या सौर सिंचाई पंपों की स्थापना की है।
- कनेक्शन के समान बिंदु का उपयोग करके अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में लाया जाता है।
- ग्रिड में इंजेक्ट करने की सीमा SERC द्वारा निर्धारित की गई है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

- एक उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की स्थापना की जानी है। फोरम में विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि होंगे। इसमें उपभोक्ता शिकायत निवारण में आसानी के लिए उपखंड शामिल है।

धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020

समाचार –

- मध्य प्रदेश कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी।

पृष्ठभूमि –

- यह अनुमोदन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा उप्र धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश, 2020 के तहत जबरन या धोखेबाजी से धार्मिक धर्मांतरण की स्वीकृति के बाद आया है।

अधिनियम की विशेशताएँ –

- यदि अधिनियम पारित हो जाता है, तो कोई भी किसी को एक धर्म से दूसरे में शादी या किसी अन्य धोखाधड़ी या डराने–धमकाने के माध्यम से परिवर्तित नहीं करवा पाएगा।
- नए विधेयक के तहत, किसी पर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने पर 1–5 वर्ष की कैद एवं न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- अपने धर्म को छिपाने की कोशिश करने पर तीन से 10 वर्ष की कैद एवं कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना होगा।
- यदि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति श्रेणियों की एक नाबालिग या महिला को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है, तो अपराधी को दो से 10 वर्ष की कैद एवं 50,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। ऐसे धर्मांतरण के पीड़ितों के रक्त रिश्तेदार शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- सामूहिक धार्मिक रूपांतरण (दो या अधिक व्यक्तियों में से) के लिए पाँच से 10 वर्ष की कैद एवं कम से कम 1,00,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है।

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता –

- भारत में धार्मिक स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 25–28 द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है।
- भारत के प्रत्येक नागरिक को शांति से अपने धर्म का अभ्यास करने एवं बढ़ाने का अधिकार है।
- भारत धर्म के मामले में सबसे विविध देशों में से एक है, यह चार प्रमुख विश्व धर्मों का जन्मस्थान है – जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एवं सिख धर्म।
- भले ही हिंदुओं की आबादी 80 प्रतिशत के करीब है, भारत में भी क्षेत्र विशेष की धार्मिक प्रथाएं हैं– जम्मू एवं कश्मीर में मुस्लिम बहुमत है, पंजाब में सिख बहुमत है, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम में ईसाई प्रमुखताएँ हैं एवं भारतीय हिमालयी राज्य जैसे सिक्किम एवं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य एवं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में बौद्ध आबादी की बड़ी संख्या है।
- देश में महत्वपूर्ण मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी आबादी है।
- इस्लाम भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म है, एवं भारतीय मुसलमान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी बनाते हैं, जिसका देश की आबादी का 14 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

सामान्य अध्ययन– III
प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव–विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन

शहद एफपीओ कार्यक्रम

समाचार –

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) के शहद किसान निर्माता संगठन (FPO) कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
- एक निर्माता संगठन (पीओ) प्राथमिक उत्पादकों जैसे किसान, दूध उत्पादक, मछुआरे, बुनकर, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार आदि द्वारा गठित एक कानूनी इकाई है।
- एफपीओ एक प्रकार का पीओ है जहां सदस्य किसान होते हैं।

विवरण –

- भारत में मधुमक्खी पालन ग्रामीण एवं आदिवासी आबादी के बीच असंगठित क्षेत्र में अत्यधिक प्रबल है। देश में शहद उत्पादन की बड़ी संभावना होने के बावजूद, मधुमक्खी पालन उद्योग अभी भी अविकसित है।

- NAFED एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करके एवं मधुमक्खी पालन आपूर्ति श्रृंखला के तत्वों के बीच अंतराल को भरने के द्वारा इन मुद्दों को हल करेगा एवं मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों को मूल्य पारिश्रमिक भी सुनिश्चित करेगा।
- इन शहद एफपीओ के माध्यम से, NAFED बेरोजगार महिलाओं एवं आदिवासी आबादी के लिए एक व्यवसाय के रूप में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने एवं उनकी आजीविका के उत्थान के लिए भी काम करेगा।

मुख्य विचार –

- कार्यक्रम एफपीओ के गठन एवं संवर्धन के तहत शुरू किया गया है।
- यह 10,000 नए एफपीओ के प्रचार के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- इसके तहत, नेशनल लेवल प्रोजेक्ट मेनेजमेंट एडवाईसरी एंड फंड सेंक्शनींग कमेटी (N–PMAFSC) ने सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को 2020–21 के लिए क्लस्टर आवंटित किए थे। कार्यान्वयन एजेंसियों ने ब्लॉक वार समूहों की पहचान की थी।
- एफपीओ को कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लगे विशेषज्ञ 'क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ)' द्वारा विकसित किया जाएगा।

नाफेड –

- नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण (DAC–FW) विभाग द्वारा 10,000 एफपीओ के निर्माण के लिए SFAC, NABARD एवं NCDC के अलावा चौथे राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- NAFED ने हाल ही में सामूहिक क्षमता बढ़ाने के लिए स्थायी छोटे पैमाने एवं सहज कृषि व्यापार धारक संस्थान बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर के फेडरेशन ऑफ इंडियन एफपीओ एंड एग्रीगेटर्स (फीफा) का अधिग्रहण किया है।
- एनएएफईडी ने अपने एमपेनल्ड क्लस्टर बेस्ड बिज़नेस ऑर्गेनाईज़ेशन (सीबीबीओ) इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेशनल्स (आईएसएपी) के माध्यम से भारत के पाँच राज्यों में मधुमक्खी पालकों एवं शहद संग्राहकों के एफपीओ के गठन एवं संवर्धन की पहल की है।
- कार्यक्रम के तहत आने वाले क्षेत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, बिहार में पूर्वी चंपारण, उत्तर प्रदेश में मथुरा, मध्य प्रदेश में मुरैना एवं राजस्थान में भरतपुर हैं।

भारत के राष्टोय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (लिमीटेड) –

- यह भारत में कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों का एक सर्वोच्च संगठन है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी।
- यह बहु–राज्य सहकारी समितियों अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत है।
- नाफेड अब भारत में कृषि उत्पादों के लिए सबसे बड़ी खरीद के साथ–साथ विपणन एजेंसियों में से एक है।
- इसका उद्देश्य कृषि, बागवानी एवं वन के विपणन, प्रसंस्करण एवं भंडारण को व्यवस्थित करना, बढ़ावा देना एवं विकसित करना है।
- एक अन्य उद्देश्य में कृषि मशीनरी, उपकरणों एवं अन्य आदानों का वितरण, अंतर–राज्य का कार्य, आयात एवं निर्यात व्यापार, थोक या खुदरा शामिल हैं जैसा कि मामला हो सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

समाचार –

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के संविधान में आरक्षण नीति को बरकरार रखती है।

आरक्षण नीति –

- भारत में आरक्षण नीति एक निश्चित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, आदि के लिए सरकारी शिक्षण संस्थान, सरकारी नौकरी इत्यादि कुछ प्रतिशत सीटों (अधिकतम 50%) को आरक्षित करने की एक प्रक्रिया है।
- आरक्षण नीति भारत में प्रचलित एक पुरानी नीति है।
- इसकी उत्पत्ति की जड़ें प्राचीन काल में बिखरी हुई हैं जब समाज में अस्पृश्यता, जातिएवं वर्ण व्यवस्था का प्रचलन प्रमुख था।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 में निहित आरक्षण, भारत सरकार को किसी भी 'नागरिकों के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों' को सुनिश्चित करने के लिए कोटा निर्धारित करने की अनुमति देता है जिसका सार्वजनिक जीवन में उचित प्रतिनिधित्व है।
- आरक्षण मुख्य रूप से सभी 4 समूहों को दिया जाता है – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग।
- मूल रूप से आरक्षण केवल एससी एवं एसटी को दिया गया था, लेकिन बाद में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद 1987 से अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) को भी दिया जाता है।

मंडल आयोग –

- संविधान के अनुच्छेद 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राष्ट्रपति ने बी। पी। मंडल की अध्यक्षता में दिसंबर 1978 में एक पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया।
- आयोग का गठन भारत के 'सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों' को परिभाषित करने के लिए मापदंड निर्धारित करने एवं उन वर्गों की उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए किया गया था।
- मंडल आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि भारत की जनसंख्या में लगभग 52 प्रतिशत अपिव शामिल हैं, इसलिए 27% सरकारी नौकरियों को उनके लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।
- आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के ग्यारह संकेतक विकसित किए हैं।
- हिंदुओं के बीच पिछड़े वर्गों की पहचान करने के अलावा, आयोग ने गैर–हिंदूओं (जैसे, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं बौद्ध) इत्यादि में भी पिछड़े वर्गों की पहचान की है।
- इसने 3,743 जातियों की एक अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची एवं 2,108 जातियों की एक 'अधिक वंचित पिछड़े वर्ग' सूची बनाई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 –

- विद्यालय जाने शुरूआत 3 वर्ष से। स्कूली शिक्षा पॉलिसी में अनिवार्य स्कूली शिक्षा के आयु वर्ग को 6–14 वर्ष से बदलकर 3–18 वर्ष तक किया गया है। इस नई प्रणाली में तीन वर्ष की आंगनवाड़ी/प्री–स्कूलिंग के साथ 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा शामिल होगी। स्कूल के पाठ्यक्रम की मौजूदा 10+2 संरचना को क्रमशः 3–8, 8–11, 11–14 एवं 14–18 वर्ष की आयु के अनुरूप 5+3. 3+4 पाठयक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने छात्रों की मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है, भले ही यह तीन भाषा सूत्र से जुड़ा हो, लेकिन यह भी अनिवार्य है कि किसी भी भाषा को किसी पर भी लागू नहीं किया जाएगा। नीति यह बताती है कि जहां भी संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 एवं उसके बाद तक, मातृभाषा/स्थानीय भाष/क्षेत्रीय भाषा, दोनों सार्वजनिक एवं निजी स्कूल में, मानदंड होगा।
- उच्च शिक्षा का एकल अधिभार निकाय भारत का उच्च शिक्षा आयोग (HECI) अब चिकित्सा, कानूनी शिक्षा को छोड़कर, संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अतिव्यापी छत्र निकाय स्थापित करेगा। विनियमन के लिए समान मानदंड, मान्यता और शैक्षणिक मानक, दोनों सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू किया जाना है। सरकार का लक्ष्य 15 वर्षों में कॉलेजों की संबद्धता को समाप्त करना है और कॉलेजों को ग्रेडेड ऑटोनॉमी देने के लिए स्टेज–वार तंत्र स्थापित किया जाना है।
- विषय धाराओं के बीच अलगाव धुंधला करना। NEP 2020 के अनुसार, विषयों की धारा के बीच का कठोर अलगाव दूर किया जाएगा। छात्रों को उन विषयों को चुनने की स्वतंत्रता होगी, जिन्हें वे धाराओं के बीच अध्ययन करना चाहते हैं। व्यावसायिक शिक्षा, कक्षा 6 से स्कूलों में पेश की जाएगी एवं साथ ही इंटर्नशिप भी शामिल होगी।
- एफवाईयूपी कार्यक्रम की वापसी और नो मोर ड्रॉपआउट्स। स्नातक की डिग्री की अवधि 3 या 4 साल होगी। छात्रों को इस अवधि के भीतर कई निकास विकल्प भी दिए जाएंगे। कॉलेजों को एक छात्र को एक प्रमाण पत्र देना होगा यदि वे व्यावसायिक और व्यावसायिक क्षेत्रों सहित एक अनुशासन या क्षेत्र में 1 वर्ष पूरा करने के बाद छोड़ना चाहते हैं, 2 साल के अध्ययन के बाद डिप्लोमा, या तीन साल के कार्यक्रम को पूरा करने के बाद स्नातक की डिग्री। अलग–अलग उच्च शैक्षणिक संस्थानों से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने के लिए सरकार द्वारा एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी ताकि इन्हें स्थानांतरित किया जा सके और अर्जित अंतिम डिग्री की तरह गिना जा सके।

विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2020

समाचार –

- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2020 जारी की गई। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है।

मलेरिया –

- मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है।
- यह आमतौर पर एक संक्रमित एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
- संक्रमित मच्छर प्लास्मोडियम परजीवी को ले जाते हैं।
- जब यह मच्छर आपको काटता है, तो परजीवी आपके रक्तप्रवाह में निकल जाता है।
- एक बार जब परजीवी आपके शरीर के अंदर होते हैं, तो वे यकृत की यात्रा करते हैं, जहां वे परिपक्व होते हैं।
- कई दिनों के बाद, परिपक्व परजीवी रक्तप्रवाह में प्रवेश करते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करने लगते हैं।
- नोट– एक संक्रमित माँ अपने बच्चे को जन्म के समय भी इस बीमारी से गुजार सकती है। इसे जन्मजात मलेरिया के रूप में जाना जाता है।

रिपोर्ट का विवरण –

- विश्व मलेरिया रिपोर्ट, सालाना प्रकाशित। यह वैश्विक और क्षेत्रीय मलेरिया डेटा पर एक व्यापक अपडेट और रुझान प्रदान करता है
- रिपोर्ट मलेरिया कार्यक्रमों और रोकथाम, निदान, उपचार और निगरानी जैसे सभी हस्तक्षेप क्षेत्रों में अनुसंधान प्रगति में निवेश को ट्रैक करती है।
- इसमें मलेरिया उन्मूलन पर और मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण खतरों पर समर्पित अध्याय भी शामिल हैं।
- यह रिपोर्ट राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों और अन्य साझीदार देशों से प्राप्त सूचना पर आधारित है।

रिपोर्ट क मुख्य अंश–

- भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की।
- 2000 में केस संख्या 20 मिलियन से घटकर 2019 में 5. 6 मिलियन हो गई है।
- वैश्विक मलेरिया मामले की गिनती पिछले चार वर्षों से अपरिवर्तित है। 2019 में यह संख्या लगभग 229 मिलियन थी।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, भारत विश्व के 11 सबसे अधिक मलेरिया वाले देशों में से एक था।
- भारत दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया मामलों का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। इस क्षेत्र में मलेरिया के लगभग 88% मामले भारत के हैं।
- भारत ने 2018 एवं 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 21% की कमी की है।
- भारत ने पिछले दो वर्षों में मलेरिया से होने वाली मौतों को भी कम किया है। 2019 में, भारत में मलेरिया के कारण मौतों की संख्या 409,000 थी। यह 2018 में 411,000 था। इसने भारत को दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी योगदानकर्ताओं में से एक बना दिया है।
- सबसे अधिक मलेरिया वाले देशों में कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, माली, घाना, भारत, नाइजीरिया एवं संयुक्त गणराज्य तंजानिया थे। इन देशों के वैश्विक अनुमानित मलेरिया मामलों का 70% हिस्सा था।
- अफ्रीकी क्षेत्र में कुल मलेरिया रोग का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा था।
- हालांकि, 2000 के बाद से महाद्वीप में मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या में 44% की कमी आई है।

- WHO की रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया के खिलाफ प्रगति नहीं हुई है।
- ऐसा मुख्य रूप कोविड–19 महामारी के कारण से जीवन रक्षक उपकरणों तक पहुंच में आए अंतराल के कारण है।
- ऐसा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर वित्त पोषण में कमी के कारण भी है।
- 2019 में मलेरिया फंड 5.6 बिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य के मुकाबले 3 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच गया।

'डमरू' प्रेरित लैटिस

समाचार –

- IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने तन डमरू से प्रेरित लैटिस विकसित किया है जिसका उपयोग पनडुब्बियों एवं उच्च गति वाली गाड़ियों में होता है।

विवरण –

- आईआईटी कानपुर ने प्रदर्शित किया है कि जाली इकाई में एक माइक्रो–संरचित अवर–ग्लास के आकार के मेटास्ट्रक्चर के उपयोग के साथ कैसे, प्रचार एवं स्टॉप बैंड की व्यापक विविधता प्राप्त कर सकता है।
- अवर–ग्लासेस को एडिटिव विनिर्माण का उपयोग करके आईआईटी कानपुर की स्मार्ट सामग्री प्रयोगशाला में विकसित किया गया है।
- जाली आधारित मेटा–संरचनाओं ने इलेक्ट्रो–मैग्नेटिक एवं सोनिक वेव अवशोषण में जबरदस्त उपयोग दिखाया है जो सिद्धांत रूप में ऑप्टिकल या ध्वनिक डोमेन में किसी वस्तु की अदृश्यता पैदा कर सकता है।
- मौजूदा जाली एवं क्रिस्टल आधारित फोनोनिक सामग्री में हालांकि, कस्टमिजेबिलिटी के संदर्भ में व्यावहारिक सीमाएं हैं एवं इसलिए, उन्हें आमतौर पर आवृत्ति के संकीर्ण बैंड में उपयोग किया जा सकता है।
- उनके द्वारा विकसित किए गए जाली की प्रेरणा डमरू नामक वाद्य यंत्र से आई है जिसका उपयोग प्राचीन हिंदू धर्म एवं तिब्बती बौद्ध धर्म में किया जाता है।

मुख्य निष्कर्ष –

- आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि नियमित रूप से छत्ते से लेकर सुक्ष्म छत्ते तक जाली सूक्ष्म संरचना को नियंत्रित करके एक वाइब्रेटिंग माध्यम की कठोरता की प्रकृति में भारी संरचना बदलाव किया जा सकता है।
- इसमें उच्च गति वाली ट्रेनों, स्टील्थ पनडुब्बियों एवं हेलीकॉप्टर रोटार में कंपन अलगाव के क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग हैं।
- शोधकर्ताओं ने यह भी दिखाया कि गतिशील प्रणालियों के लिए, हम बहुत प्रभावी ढंग से प्रसार एवं बैंड–गैप को नियंत्रित कर सकते हैं जो चिकित्सा चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य प्रबंधन उद्योग को सशक्त बनाने वाली उप–तरंग लंबाई इमेजिंग की क्षमता के साथ नए अल्ट्रासोनिक उपकरणों के विकास की शुरूआत कर सकते हैं।
- यह कार्य एमएचआरडी की एक स्पार्क परियोजना द्वारा प्रायोजित है।
- यह काम 1 दिसंबर, 2020 को 'डमरू आकार के जाली मेटास्ट्रक्टर्स की गतिशीलता की खोज' शीर्षक के साथ वैज्ञानिक रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है।

लैटिस (आर्डर)

- एक लैटिस क्रम सिद्धांत एवं अमूर्त बीजगणित के गणितीय उपविषयकताओं में अध्ययन की गई एक सार संरचना है।
- इसमें एक आंशिक रूप से आदेशित सेट होता है, जिसमें प्रत्येक दो तत्वों का एक अनोखा सुप्रीमम होता है (जिसे लिस्ट अपर बाउंड या जॉइन भी कहा जाता है) एवं एक अनोखा मिनीमम (जिसे ग्रेटेस्ट लोअर बाऊँड या मीट भी कहा जाता है)।
- एक उदाहरण प्राकृतिक संख्याओं द्वारा दिया जाता है, जो आंशिक रूप से विभाज्यता द्वारा ऑर्डर होती हैं जिसमें यूनिक सुप्रीमम लघुत्तम समापवर्त्य तथा यूनिक मिनीमम महत्तम समापवर्त्य होता है।

शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना (स्पार्क) –

- शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएआरसी) का लक्ष्य भारतीय चयनित संस्थानों एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच 28 चयनित देशों से संयुक्त रूप से राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने एवं/या अंतरराष्ट्रीय प्रासंगिकता के लिए भारत के उच्च शैक्षिक संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है।
- इस योजना के तहत, 600 संयुक्त अनुसंधान प्रस्तावों को 2 वर्षों के लिए सम्मानित किया जाएगा ताकि भारतीय अनुसंधान समूहों के बीच अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए कक्षा के संकाय एवं विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों में प्रसिद्ध अनुसंधान समूहों के साथ काम कर सकें।
- 5 थ्रस्ट क्षेत्रों का एक सेट जो मौलिक अनुसंधान, प्रभाव के उभरते हुए क्षेत्र, अभिसरण, एक्शन–ओरिएंटेड रिसर्च, एवं प्रत्येक थ्रस्ट एरिया में इनोवेशन–ड्रिवेन एवं सब–थीम क्षेत्र हैं की पहचान की गई है।

1.5 गुना सूत्र –

समाचार –

- फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करने के लिए 1.5 गुना सूत्र का उपयोग किया जाता है। यह केंद्रीय बजट 2018–19 के दौरान पेश किया गया था।

सूत्र –

- इस फॉर्मूले के अनुसार, एमएसपी को–पूर्व–निर्धारित सिद्धांत 'के रूप में फसलों के लिए उत्पादन लागत का 1.5 गुना निर्धारित किया गया है।

- इस फार्मूले के तहत, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (एमएसपी का निर्धारण करने वाला आयोग) को केवल एक सीजन के लिए उत्पादन लागत का निर्धारण करना है एवं फार्मूला लागू करना है।

मुद्दा –

- भारत सरकार एवं किसान यूनियनों के बीच वार्ता 1 दिसंबर, 2020 को संकल्प तक पहुंचने में विफल रही।
- किसानों ने बिजली संशोधन विधेयक 2020 एवं तीन हालिया कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग को खारिज करने से इनकार कर दिया।
- वार्ता में मुख्य असहमति न्यूनतम समर्थन मूल्य के आसपास है।
- किसानों को डर है कि नए कानून केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की पेशकश को दूर करेंगे।

फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे तय होता है?

- प्रतिवर्ष कृषि मंत्रालय के तहत संचालित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। इसमें मानसून या खरीफ मौसम के दौरान पैदा होने वाली 14 फसलें एवं सर्दियों या रबी मौसम में उगाई जाने वाली छह फसलें शामिल हैं।
- कीमतों को तय करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कई कारकों पर विचार करता है जैसे कि बाजार मूल्य के रुझान, आपूर्ति एवं वस्तु की मांग, मुद्रास्फीति, गैर–कृषि क्षेत्रों एवं कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, पर्यावरण (मिट्टी एवं पानी) एवं खेती की लागत।
- 2018–19 के केंद्रीय बजट के दौरान, यह घोषणा की गई थी कि फसलों के लिए उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा।
- सरल शब्दों में अब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का एकमात्र काम मौसम के लिए फसलों की उत्पादन लागत का अनुमान लगाना एवं 1.5 गुना फार्मूला लागू कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करना है।

उत्पादन लागत कैसे आती है?

- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कोई भी क्षेत्र आधारित लागत अनुमान नहीं लगाता है।
- यह केवल फसल विशिष्ट एवं राज्य विशिष्ट उत्पादन लागत अनुमानों का उपयोग करके अनुमान लगाता है। यह डेटा कृषि मंत्रालय के तहत संचालित अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रदान किया जा रहा है।
- हालाँकि, इस डेटा में 3 वर्ष का अंतराल है एवं इसे अक्सर अपडेट नहीं किया जाता है।
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भी प्रत्येक फसल के लिए उत्पादन लागत के तीन अन्य प्रकार के प्रोजेक्ट करता है। वे A2, C2 एवं A2+FL है।
- A2 किसान द्वारा किए गए सभी लागतों को शामिल करता है। इसमें उर्वरक, बीज, कीटनाशक, कम से कम अंतर्देशीय, उच्च श्रम, सिंचाई शामिल हैं।
- A2 + FL में A2 के तहत आने वाली सभी लागत एवं अवैतनिक पारिवारिक श्रम का मूल्य शामिल है।
- C2 एक व्यापक लागत है जिसमें A2+FL लागत के साथ–साथ किराये, अपनी जमीन पर ब्याज एवं निश्चित पूंजीगत संपत्ति शामिल है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) –

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों को खेत की कीमतों में किसी भी तीव्र गिरावट के खिलाफ बीमा करने के लिए बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है।
- भारत सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों के लिए बुवाई के मौसम की शुरुआत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है।
- भारत सरकार द्वारा उत्पादक – किसानों की बम्पर उत्पादन के वर्षों के दौरान कीमत में अत्यधिक गिरावट से रक्षा के लिए, एमएसपी तय की जाती है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार से उनकी उपज के लिए गारंटी मूल्य हैं।
- किसानों को संकट से उबारने एवं सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों की खरीद इसका प्रमुख उद्देश्य है। यदि बाजार में बम्पर उत्पादन एवं ग्लूट के कारण कमोडिटी के लिए बाजार मूल्य घोषित न्यूनतम मूल्य से नीचे आता है, तो सरकारी एजेंसियां किसानों द्वारा दी जाने वाली पूरी मात्रा खरीद लेती हैं।

HSN कोड

समाचार –

- सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स जारी करते समय 49 केमिकल–आधारित उत्पादों के लिए 8–अंकीय HSN (हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर) या टैरिफ कोड का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में, व्यवसाय चालान जारी करते समय 4–अंकीय टैरिफ कोड का उल्लेख करते हैं।

विवरण –

- व्यापार समानता में, हर उत्पाद को HSN कोड के तहत वर्गीकृत किया गया है। यह विश्व भर में माल के व्यवस्थित वर्गीकरण में मदद करता है।
- यह अपनी तरह का पहला नोटिफिकेशन है जिसके तहत आपूर्तिकर्ताओं की एक विशिष्ट श्रेणी को प्रत्येक इनवॉइस पर 8 अंकों के एचएसएन कोड का उपयोग करने के लिए कहा जाता है।

HSN कोड –

- हार्मोनाइज्ड सिस्टम उत्पादों के वर्गीकरण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय नामकरण है। यह भाग लेने वाले देशों को सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए एक सामान्य आधार पर व्यापार के सामान को वर्गीकृत करने की अनुमति देता है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) छह अंकों की कोड प्रणाली है। कोड में पहले दो अंक एचएस अध्याय को दर्शाते हैं, अगले दो अंक एचएस हेडिंग हैं एवं अंतिम दो अंक एचएस सबहडिंग हैं।
- एचएस 'हार्मोनाइज्ड सिस्टम' विश्व सीमा शुल्क द्वारा विकसित किया गया था
- यह एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद नामकरण संगठन है।
- माल के लिए कोड को सार्वभौमिक आर्थिक भाषा कहा जाता है। कोड में 5000 से अधिक कमोडिटी समूह शामिल हैं।
- भारत में कोड 8 अंकों का उपयोग करता है। भ्ैछ कोड में 21 सेक्शन, 99 चौप्टर, 1,244 हेडिंग एवं 5,224 सबहेडिंग शामिल हैं।
- उदाहरण के लिए, प्याज का HSN 07031010 है।

- '07' "खाद्य सब्जियों" के अध्याय को दर्शाता है, 03 'प्याज, लहसुन, लीक जैसे अध्याय में शीर्षकों को दर्शाता है। बाकी सबहाइडिंग को दर्शाता है।

HSN कोड क्यों महत्वपूर्ण है?

- HSN कोड मुख्य रूप से कराधान के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। यह देश में किसी उत्पाद पर लागू कर की दर की पहचान करने में मदद करता है।
- कोड का उपयोग सांख्यिकीय एजेंसियों, सीमा शुल्क अधिकारियों एवं अन्य सरकारी नियामक निकायों द्वारा वस्तुओं के आयात एवं निर्यात को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
- कोड मुख्य रूप से कस्टम टैरिफ, इंटरनेट एक्सेस के संग्रह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंकड़ों का संग्रह, परिवहन टैरिफ एवं सांख्यिकी, कस्टम नियंत्रण एवं प्रक्रियाओं के क्षेत्र, नियंत्रित माल की निगरानी जैसे कि नशीले पदार्थों, रासायनिक हथियारों, लुप्तप्राय प्रजातियों, ओजोन परत के संग्रह में उपयोग किया जाता है।
- लगभग 200 देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आँकड़े, कस्टम टैरिफ इकट्ठा करने एवं माल की निगरानी करने एवं व्यापार नीतियां बनाने के लिए प्रणाली का उपयोग करते हैं।
- इसलिए, प्रणाली व्यापार प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है एवं अंततः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागत को कम करती है।

मत्स्य प्रबंधन

समाचार –

- भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें हानिकारक मत्स्य पालन पर रोक लगाने पर बातचीत चल रही है।
- विकासशील देशों के लिए विशेष एवं अंतर उपचार (एसएंडटी) पर एक स्पष्ट गतिरोध से बचने के लिए वार्ता समिति में प्रयास किए जा रहे हैं एवं निष्कर्ष की ओर वार्ता को आगे बढ़ा रहे हैं।
- सदस्य प्रति वर्ष 14–20.5 बिलियन डॉलर की अनुमानित 'हानिकारक' मत्स्य सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, जिससे विश्व भर में मछली पकड़ने में कमी हो।

भारत का नया प्रस्ताव –

- विश्व व्यापार संगठन के अपने प्रस्ताव के तहत, भारत ने सुझाव दिया है कि तटीय क्षेत्रों के मत्स्य प्रबंधन में विवाद निपटान पैनल की भूमिका सीमित होनी चाहिए।
- भारत ने यह भी सुझाव दिया है कि एक सदस्य को मामले में अपनी संप्रभुता बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- भारत के अनुसार विश्व व्यापार संगठन को क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों के निर्धारकों द्वारा प्रबल होने की आवश्यकता है।

भारत के पहले के प्रस्ताव एवं मुद्दे –

- भारत के राष्ट्रीय आय पर आधारित सब्सिडी कटौती प्रतिबद्धताओं से छूट वाले देशों के पहले प्रस्ताव को वार्ता समिति ने आगे शोधन के लिए रखा है।
- बातचीत करने वाले समूह की बैठक में, कई देशों ने बताया कि भारत के S-DT विकासशील देशों को $5,000 प्रति वर्ष से कम सकल आय (लगातार तीन वर्षों के लिए) एवं मत्स्य पालन सब्सिडी कटौती से एक निश्चित स्तर से नीचे मछली पकड़ने की मात्रा में छूट का प्रस्ताव पर सहमति नहीं थी।

भारत के लिए प्रस्तावों का महत्व –

- भारत डब्ल्यूटीओ मछली पालन वार्ता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जो कि सब्सिडी को सीमित करने के लिए एक समझौते के रूप में महत्वपूर्ण है, भारतीय मछुआरों की आजीविका पर इससे गहरा प्रभाव पड़ेगा, उनमें से कई छोटे व्यवसायी हैं।
- देश द्वारा किए गए दो प्रस्ताव कमजोर मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- भारत द्वारा प्रस्तावित थ्रेशोल्ड स्तर देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चीन के बहिष्कार के साथ सबसे अधिक मत्स्य सब्सिडी वाले देश को बाहर करने के लिए प्रेरित करेगा।

आगे को राह –

- डब्ल्यूटीओ मत्स्य वार्ता के समापन के लिए एक वर्ष की समय सीमा देख रहा है, लेकिन अब 2021 तक फैलने की संभावना है।

महत्वपूर्ण जानकारी –

- विश्व व्यापार संगठन ने दोहा में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान वर्ष 2001 में 'मत्स्य सब्सिडी' पर वार्ता शुरू की। मत्स्य पालन में दी जाने वाली सब्सिडी पर मौजूदा डब्ल्यूटीओ दिशानिर्देशों को बेहतर बनाने एवं स्पष्ट करने के उद्देश्य से बातचीत शुरू की गई थी।
- 2005 में हांगकांग मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान मत्स्य वार्ता के दायरे को और अधिक बड़ा किया गया, जिसमें मछली पकड़ने की सब्सिडी के कुछ प्रकार जो मछली पकड़ने की ओर ले जाते हैं, निषिद्ध थे।
- 2017 में ब्यूनस आयर्स में आयोजित मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में मत्स्य पालन के संबंध में एक सतत विकास लक्ष्य को अपनाया गया था।
- सतत विकास लक्ष्य 14.6 में कहा गया है कि 2020 तक, मत्स्य पालन सब्सिडी के कुछ प्रकार जो ओवरकिप्सी एवं ओवरफिशिंग में योगदान करते हैं, को समाप्त किया जाना चाहिए।

विश्व व्यापार संगठन –

- विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन से चिंतित है।
- डब्ल्यूटीओ ने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को मारकेश समझौते के तहत शुरू किया, 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों द्वारा हस्ताक्षरित, टैरिफ एवं व्यापार (GATT) पर सामान्य समझौते की जगह, जो 1948 में शुरू हुआ था।
- यह विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन है।
- डब्ल्यूटीओ व्यापार समझौते, व्यापार समझौतों के लिए एक ढांचा प्रदान करने एवं एक विवाद समाधान प्रक्रिया, जो विश्व व्यापार संगठन के समझौतों का पालन करने के लिए प्रतिभागियों को लागू करने के उद्देश्य से एक रूपरेखा प्रदान करके व्यापार देशों के बीच माल, सेवाओं एवं बौद्धिक संपदा के विनियमन से संबंधित है।

3 आरएफ फ्रेमवर्क

समाचार –

- 3RF का अर्थ रिफॉर्म, रिकवरी एवं रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क है। इसकी रूपरेखा संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक एवं यूरोपीय संघ द्वारा तैयार की गई थी।
- यह बेरूत को फिर से बसाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था। 4 अगस्त, 2020 को लेबनान की राजधानी बेरुत में एक घातक विस्फोट में 200 से अधिक लोग मारे गए तथा एक लाख बेघर हो गए।

पृष्ठभूमि –

- लेबनान में वर्तमान में उच्च वित्तीय दिवालियापन चल रहा है।
- लेबनान की वर्तमान गरीबी दर 55% है। यह बारह महीने पहले 28% थी।
- राजनीतिक अस्थिरता के कारण आवश्यक सुधार अवरुद्ध हैं।

3 आर एफ –

- 3RF का लक्ष्य तीन केंद्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करना है –
- लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली एक जन–केंद्रित वसूली, उनकी आजीविका को पुर्नस्थापित करती है, सभी के लिए सामाजिक न्याय में सुधार करती है एवं भागीदारी निर्णय लेने को सुनिश्चित करती है।
- महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों, सेवाओं एवं बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण जो सभी के लिए गुणवत्ता की बुनियादी सेवाओं तक समान पहुंच प्रदान करता है एवं स्थायी आर्थिक वसूली को सक्षम बनाता है।
- विश्वास को बहाल करने, पुनर्निर्माण का समर्थन करने एवं शासन में सुधार करने के लिए एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में सुधारों का कार्यान्वयन।

3RF दो समानांतर स्तरों पर कार्य करता है –

- एक सामाजिक–आर्थिक सुधार ट्रैक ('ट्रैक 1'), जो विस्फोट से प्रभावित सबसे कमजोर आबादी एवं छोटे व्यवसायों की तत्काल जरूरतों को संबोधित करता है।
- एक सुधार एवं पुनर्निर्माण ट्रैक ('ट्रैक 2'), लेबनान में शासन एवं पुनर्प्राप्ति चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो रिकवरी ट्रैक से परे पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए आवश्यक शर्तहैं।

फंड एवं उनका प्रबंधन –

- पुनरोद्धार योजना को विश्व बैंक, यूरोपीय संघ एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित मल्टी–डोनर ट्रस्ट फंड द्वारा समर्थित किया जाना है।
- धन का उपयोग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए किया जाना है। 3 आर एफ योजना में स्वास्थ्य, सुशासन, शिक्षा, आवास, सामाजिक संरक्षण, संस्कृति एवं विरासत को प्राथमिकता दी गई है। योजना छोटे एवं मध्यम आकार के उद्यमों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान देगी।
- शहर की बंदरगाह सुविधाओं को प्रमुखता साथ 'बेहतर प्रबंधन, बेहतर पुनर्निर्माण एवं पारदर्शी तरीके से निर्णय लेने' के साथ पुनर्निर्माण किया जाना है।

तरलता समायोजन की सुविधा

समाचार –

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) में अधिक कुशल तरलता प्रबंधन की सुविधा देने का निर्णय लिया है।
- आरबीआई ने आरआरबी को एलएएफ एवं एमएसएफ (सीमांत स्थायी सुविधा) का विस्तार करने का निर्णय लिया है।
- इसने आरआरबी को कॉल/नोटिस मनी मार्केट में उधारकर्ता एवं ऋणदाता दोनों के रूप में भाग लेने की अनुमति देने का फैसला किया है।
- आरआरबी को वर्तमान में रिजर्व बैंक की तरलता खिड़कियों के साथ–साथ कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंचने की अनुमति नहीं है।
- रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा एवं एक 'निवारक' रुख बनाए रखा।

तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) '

- यह सुविधा बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के आधार पर RBI में 1998 में पेश की गई थी।
- एलएएफ एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।
- आरएएफ की मदद से आरबीआई तरलता प्रबंधन करता है एवं बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों या रेपो के माध्यम से धन उधार लेने या रिवर्स रेपो एग्रीमेंट्स के माध्यम से आरबीआई को ऋण देने का अवसर प्रदान करके आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है।
- LAF मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि एवं कमी करके अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रबंधन कर सकता है।

तरलता को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरण –

- आरबीआई देश में तरलता के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए चार उपकरणों का उपयोग करता है। वो हैं –
- नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)
- तरलता समायोजन सुविधाएं (रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर शामिल हैं)
- वैधानिक तरलता अनुपात
- खुला बाजार परिचालन

नरसिम्हम समिति –

- नरसिम्हम समिति ने मूल रूप से बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणालियों के कामकाज में बदलाव की सिफारिश की थी।

कमेटी की सिफारिशें –

- नकद आरक्षित अनुपात एवं सांविधिक तरलता अनुपात के उच्च अनुपात को कम करना।
- समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कम करने एवं देश में तीन से चार बड़े बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंक में विकसित करने की सिफारिश की।
- इसने एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड की स्थापना की सिफारिश की। यह बैंकों को अपने बुरे ऋणों से छुटकारा पाने में मदद करता है।

- म्युचुअल फंड, मर्चेंट बैंक, लीजिंग कंपनियों, कारक कंपनियों, आदि जैसे वित्तीय संस्थानों की निगरानी के लिए नई एजेंसी की स्थापना करना।
- आरआरबी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सरकारी बैंक) हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं।
- वे मुख्य रूप से बुनियादी बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के साथ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।
- आरआरबी के शहरी परिचालन के लिए शाखाएँ हो सकती हैं एवं उनके संचालन के क्षेत्र में शहरी क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं।

RRB निम्नलिखित क्षेत्रों में विभिन्न कार्य करते हैं –

- ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना।
- मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का वितरण, पेंशन का वितरण आदि जैसे सरकारी कार्यों को पूरा करना।
- लॉकर सुविधाएं, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई आदि जैसे पैरा–बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना।
- छोटे वित्तीय बैंक।

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)

- सीमांत स्थायी सुविधा आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को रेपो दर से अधिक ब्याज दर के साथ रातोरात दी जाने वाली तरल सहायता है।
- MSF का उपयोग बैंक LAF रेपो जैसे अन्य विकल्पों के तहत उधार लेने के लिए अपनी योग्य सुरक्षा होल्डिंग्स को समाप्त कर देने के बाद करता है।
- आमतौर पर, जब बैंकों को आरबीआई से अल्पावधि ऋण की आवश्यकता होती है, तो वे अपनी सुरक्षा होल्डिंग्स को गिरवी रखते हैं जो रेपो के तहत एक दिन के ऋण प्राप्त करने के लिए आरबीआई के साथ एसएलआर होल्डिंग्स के ऊपर होती हैं।
- एमएसएफ के तहत, एक बैंक आरबीआई का एक दिन का ऋण ले सकता है, भले ही इसके एसएलआर की आवश्यकता के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिभूति न हो (केवल एसएलआर रखता है)।
- MSF को 2011–12 के लिए अपनी मौद्रिक नीति में RBI द्वारा पेश किया गया था।

जीएसटी मुआवजा

समाचार –

- झारखंड जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए विकल्प –1 के लिए जाने वाला नवीनतम राज्य बन गया है।

विकल्प 1 –

- विकल्प –1 की शर्तों के तहत, राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए उधार के लिए एक विशेष खिड़की की सुविधा प्राप्त करने के अलावा, राज्यों को केंद्र द्वारा अनुमत 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधारों में से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत की अंतिम किस्त उधार लेने के लिए बिना शर्त अनुमति प्राप्त करने का भी अधिकार है।
- यह 1.1 लाख करोड़ रुपये की विशेष सीमा के ऊपर है।

विवरण –

- सभी 28 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने कर संग्रह में कमी को पूरा करने के लिए केंद्र की उधार योजना को स्वीकार कर लिया है।
- विकल्प–1 का चयन करने वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र द्वारा रखी गई एक विशेष उधार खिड़की के माध्यम से जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली कमी की मात्रा मिल रही है।
- उधार योजना (विकल्प –1) के तहत, केंद्र बाजार से 1.10 लाख करोड़ रुपये उधार लेगा जो कि जीएसटी कार्यान्वयन के कारण राजस्व की कमी है।
- केंद्र द्वारा दिया गया दूसरा विकल्प यह था कि राज्य पूरे 1.83 लाख करोड़ रुपये की संग्रह की कमी को पूरा करें।

पृष्ठभूमि –

- जीएसटी मुआवजे पर, केंद्र राज्यों को 2 विकल्प देता है। 1 सितंबर को, केंद्र ने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत 2.35 लाख करोड़ रुपये के चालू वर्ष के मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को प्रस्तावित उधार विकल्पों को विस्तृत किया।
- विकल्प 1 में राज्यों के लिए एक विशेष खिड़की है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वित है।
- विकल्प 2 में महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखा गया है, जो राज्यों को पूरे 2.35 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का प्रस्ताव देता है एवं ब्याज के बोझ को वहन करता है, हालांकि प्रिंसिपल उपकर से चुकाया जाएगा। जीएसटी की कमी की राशि को राज्यों के ऋण के रूप में नहीं गिना जाएगा, जबकि शेष राशि को राज्यों के खातों में गिना जाएगा।

वस्तु एवं सेवा कर

- गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर इस्तेमाल होने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है।
- यह एक व्यापक, मल्टीस्टेज, गंतव्य–आधारित कर है क्योंकि इसमें कुछ राज्य करों को छोड़कर लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) –

- जीएसडीपी विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों (कृषि, उद्योग एवं सेवाएँ) द्वारा जोड़े गए मूल्य का कुल योग है जो राज्य की सीमाओं के भीतर एक वर्ष के दौरान दोहराव के बिना गणना की जाती है। यह किसी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास के उपाय है।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) से, फिक्स्ड कैपिटल (सीएफसी) का उपभोग एनएसडीपी यानी पर पहुंचने के लिए घटाया जाता है।
- एनएसडीपी = जीएसडीपी – सीएफसी
- फिक्स्ड कैपिटल (सीएफसी) का उपभोग निश्चित पूंजी का मूल्य है जो उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान खपती है। इसकी गणना अचल संपत्ति के जीवन काल के आधार पर की जाती है।

एचएएल–आईआईएससी कौशल विकास केंद्र

समाचार –

- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने एचएएल– इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस (IISc) स्किल डेवलपमेंट सेंटर (SDC) के तहत आयोजित किया जा रहा पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम चालाकेरी, चित्रदुर्ग में औपचारिक रूप से शुरू किया।
- केंद्र की गतिविधियाँ पाँच पाठ्यक्रमों के साथ शुरू होंगी, जिन्हें दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के दौरान वर्चुअल मोड में पहले कॉहोर्ट में पेश किए जाने की योजना है।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) –

- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) भौतिक वस्तुओं के नेटवर्क का वर्णन करता है– 'वस्तुएँ' – सेंसर एवं सॉफ्टवेयर द्वारा इंटरनेट पर अन्य उपकरणों एवं प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ने एवं आदान–प्रदान करने के उद्देश्य से के साथ सन्निहित हैं।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स की परिभाषा, कई तकनीकें रीयल–टाइम एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, कॉमोडिटी सेंसर एवं एम्बेडेड सिस्टम के अभिसरण के कारण विकसित हुई है।
- एम्बेडेड सिस्टम के पारंपरिक क्षेत्र, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, नियंत्रण प्रणाली, स्वचालन (घर एवं भवन स्वचालन सहित), एवं अन्य सभी वस्तुए इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सक्षम करने में योगदान करती हैं।

एंबेडेड एप्लीकेशन –

- एक एंबेडेड एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है जिसे कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्यों को करने के लिए किसी प्रकार के उपकरण के अंदर स्थायी रूप से रखा जाता है।
- माइक्रोवेव ओवन में लगने वाले जैसे कुछ छोटे एम्बेडेड एप्लीकेशन को नियंत्रित करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) की आवश्यकता नहीं होती है।

पाठ्यक्रम का विवरण –

- प्रस्तावित कार्यक्रम एयरोस्पेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों के आला इंजीनियरिंग क्षेत्रों में हैं, एवं 'मेक इन इंडिया' मिशन के अनुरूप हैं।
- विभिन्न तकनीकी संस्थानों के अनुभवी इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों एवं संकाय सदस्यों को केंद्र में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- संकाय सदस्यों का चयन भारतीय विज्ञान संस्थान एवं एचएएल सहित अन्य प्रमुख संगठनों से किया जाएगा।

लाभ –

- एचएएल–आईआईएससी कौशल विकास कार्यक्रम महत्वाकांक्षी है एवं प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करके देश की जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए इसका अधिक प्रभाव पड़ता है।
- प्रशिक्षण कौशल उन्नयन के साथ–साथ नए कौशल विकसित करने का कार्य भी करेगा।
- अद्वितीयता स्वयं कर के सीखने पर जोर देने में निहित है। प्रशिक्षु प्रयोगों का संचालन करते हुए, प्रयोगशालाओं में पाठ्यक्रम की अवधि का 50% से अधिक खर्च करेंगे।

केंद्र का विवरण –

- रक्षा मंत्री ने 13 अगस्त 2020 को चालाकेरी में कौशल विकास केंद्र का औपचारिक उद्घाटन किया था।
- यह एयरोस्पेस डोमेन एवं विनिर्माण से संबंधित उच्च स्तर का कौशल प्रदान करने के लिए HAL एवं IISc के बीच एक साझेदारी के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह केंद्र आईआईएससी के नए 1500 एकड़ परिसर में स्थित है, जो कि एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शहर के रूप में विकसीत होना है। कौशल विकास केंद्र 75000 वर्ग फुट में फैला है।
- यह 250 प्रशिक्षुओं एवं संकाय सदस्यों के लिए आधुनिक लैब, क्लास रूम, ऑडिटोरियम एवं आवास से सुसज्जित है।
- IISc के पड़ोसियों में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) एवं भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) शामिल हैं।
- आईआईएससी ने राष्ट्र में महत्वपूर्ण कौशल विकास अंतराल को संबोधित करने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों का एक बड़ा पूल बनाने के लिए एक केंद्र की स्थापना की कल्पना की थी। 2016 में, IISc ने HAL से इस अनोखे प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप की।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड –

- एचएएल एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली एयरोस्पेस एवं रक्षा कंपनी है, जिसका मुख्यालय भारत के बैंगलोर में है। यह भारतीय रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के तहत शासित है।

फ्लोटिंग जेटी के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश

समाचार –

- पोर्ट्स, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय ने फ्लोटिंग संरचनाओं की तकनीकी विशिष्टताओं के लिए मसौदा दिशा–निर्देश जारी किए, जिसमें समुद्र तट के साथ–साथ विश्व स्तर के फ्लोटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने एवं तैनात करने के लिए एक विजन जारी किया एवं सार्वजनिक परामर्श के लिए भी इसे जारी किया।
- जनता से प्रतिक्रिया एवं सुझाव मांगने के लिए प्रस्तावित विनिर्देशों/तकनीकी आवश्यकताओं की अनुसूची (एसओटीआर) के साथ मसौदा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- मंत्रालय ने आईआईटी चेन्नई को फ्लोटिंग जेटी, वाटर–एयरोड्रोम, फ्लोटिंग मरीना, फिश लैंडिंग सुविधा आदि जैसे टिकाऊ अस्थायी संरचनाओं के तकनीकी विनिर्देशों को काम करने के लिए सौंपा है ताकि सटीक एवं कड़े तकनीकी विनिर्देश स्थापित किए जा सकें।

फ्लोटिंग जेटी के लाभ –

- पारंपरिक क्वाइल एवं फिक्स्ड कंक्रीट संरचनाओं पर फ्लोटिंग जेटी के कई लाभ हैं –
- लागत प्रभावशीलता
- पारंपरिक संरचनाओं की तुलना में बहुत सस्ता
- परंपरागत जेट की तुलना में फ्लोटिंग संरचनाओं की स्थापना बहुत तेज है
- पारंपरिक संरचनाओं के लिए 24 महीने की तुलना में छह से आठ महीनों में फ्लोटिंग संरचनाएं बनाई जा सकती हैं
- पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम है
- मॉड्यूलर निर्माण तकनीकों के कारण विस्तार आसानी से संभव है
- बंदरगाह के पुनर्निर्माण के मामले में आसानी से परिवहनीय
- जेटी एवं नौकाओं के बीच निरंतर फ्रीबोर्ड प्रदान करता है
- फ्लोटिंग जेटी की तैनाती, विशेष रूप से एक बड़ी ज्वारीय सीमा वाले स्थानों में, जहां पारंपरिक ज्वार कम ज्वार की अवधि के दौरान समस्याएं पैदा करता है, सुविधाजनक है।
- ऐसे स्थानों पर फ्लोटिंग जेटी, निरंतर फ्रीबोर्ड प्रदान करते हैं, जहाज के स्टोरों को आसानी से तैयार करते हैं एवं मछुआरों की पकड़ को सीधा उतारते हैं।
- इसके परिणामस्वरूप लंबे समय में मछुआरों की सुरक्षा के साथ–साथ उत्पादकता में वृद्धि होती है।

अन्य सूचना –

- शिपिंग मंत्रालय ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करके हाल ही में कुछ पायलट परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है।

इसमें शामिल है–

- गोवा में यात्री फ्लोटिंग जेटी की स्थापना
- साबरमती नदी पर एवं सरदार सरोवर बांध में (सीप्लेन सेवाओं के लिए) जल–एयरोड्रोम

हाथियों के लिए गलियार

समाचार –

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्य सरकार को ओडिशा में हाथियों के लिए गलियारों पर एशिया प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन (एएनसीएफ) की रिपोर्ट पर एक कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का समय दिया है।

रिपोर्ट क मुख्य अंश –

- एएनसीएफ की रिपोर्ट ने राज्य में 14 हाथी कॉरिडोरों को उनके कार्यात्मक अस्तित्व एवं पारिस्थितिक व्यवहार्यता के अनुसार वर्गीकृत किया था, साथ ही उन प्रस्तावों एवं सुझावों के साथ, जिनके द्वारा कॉरिडोर को मजबूत किया जा सकता था।
- एएनसीएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती हुई भीड़ को बेअसर करने के लिए पारंपरिक आंदोलन के मार्ग को बचाने एवं बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि

- एनजीटी ने 2017 में एक निषेध आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि ऐसी सभी गतिविधियाँ जिनके इको सेंसिटिव जोन (ईएसजेड), में किए जाने की अनुमति नहीं हैं, को नही करना चाहिए।
- एनजीटी ने अधिकारियों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर गलियारों के सीमांकन में तेजी लाने का निर्देश दिया।

ओडिशा सरकार का रुख –

- ओडिशा सरकार ने 870.61 वर्ग किमी के कुल क्षेत्र में 14 गलियारों का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया था। जिसकी लंबाई 420.8 किमी है। कई वर्षों के बाद भी, सरकार के प्रस्ताव पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई।

हाथीयों के गलियारं

- वे भूमि की संकीर्ण पट्टियाँ हैं जो हाथियों के दो बड़े आवासों को जोड़ती हैं।
- वे दुर्घटनाओं एवं अन्य कारणों से जानवरों की मृत्यु को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- वनों का विखंडन, प्रवासी गलियारों को संरक्षित करने के लिए इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है।
- हाथियों के इस आने–जाने से प्रजातियों के अस्तित्व एवं जन्म दर को बढ़ाने में मदद मिलती है।
- राष्ट्रीय हाथी गलियारे परियोजना के तहत भारत के वन्यजीव ट्रस्ट द्वारा 88 हाथी गलियारों की पहचान की गई है।

चिंता –

- मानव बस्तियों, सड़कों, रेलवे लाइन, विद्युत लाइनों, नहर एवं खनन जैसे चौतरफा विकास गलियारे के निर्माण का मुख्य कारण हैं।

गलियारों की सुरक्षा के लिए कारण –

- हाथियों की आवाजाही यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उनकी आबादी आनुवंशिक रूप से व्यवहार्य हो। यह जंगलों को पुनर्जीवित करने में भी मदद करता है, जिस पर बाघ सहित अन्य प्रजातियां निर्भर हैं।
- लगभग 40% हाथी संरक्षण स्थल खराब हालत में हैं, क्योंकि वे संरक्षित पार्कों एवं अभयारण्यों के भीतर नहीं हैं। इसके अलावा, माइग्रेशन कॉरिडोर का कोई विशिष्ट कानूनी संरक्षण नहीं है।
- जो जंगल खेतों एवं अनियंत्रित पर्यटन में बदल गए हैं, वे पशु पथों को अवरुद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार जानवरों को वैकल्पिक मार्गों की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप हाथी–मानव संघर्ष बढ़ जाता है।
- इकोटूरिज्म का कमजोर नियमन महत्वपूर्ण निवास स्थान को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। यह उन जानवरों को विशेष रूप से प्रभावित करता है जिनके हाथियों की तरह बड़ी होम रेंज होती हैं।

एशिया प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन (ANCF) –

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान को संभालने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण के निर्माण में सक्षम बनाता है।

- यह भारत के संवैधानिक प्रावधान (भारत का संविधान / भाग III) से प्रेरित है। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, जो भारत के नागरिकों को एक स्वस्थ वातावरण का अधिकार देता है।
- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला एक विभाग है।

सार्वजनिक वाई–फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PMWANI)

समाचार –

- मंत्रिमंडल ने देश भर में सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) के माध्यम से सार्वजनिक वाई–फाई सेवा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स (पीडीओएएस) द्वारा सार्वजनिक वाई–फाई नेटवर्क स्थापित करने के लिए दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
- यह सार्वजनिक वाई–फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम–वानी के रूप में जाना जाएगा एवं इन सार्वजनिक वाई–फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने के लिए कोई लाइसेंस शुल्क नहीं होगा।

विवरण–

- देश भर में सार्वजनिक डेटा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस, शुल्क या पंजीकरण नहीं होगा।
- सार्वजनिक वाई–फाई का प्रसार न केवल रोजगार पैदा करेगा बल्कि छोटे एवं मध्यम उद्यमियों के हाथों में डिस्पोजेबल आय को बढ़ाएगा एवं देश के सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) को बढ़ावा देगा।
- पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) केवल WANI वाई–फाई पहुंच बिंदुओं की स्थापना, रखरखाव एवं संचालन करेगा एवं ग्राहकों को ब्रॉडबैंड सेवाएं देगा, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (पीडीओए) पीडीओ का एक एग्रीगेटर होगा जो प्राधिकरण से संबंधित एवं लेखांकन कार्य करेगा।
- PM-WANI विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पक्षों द्वारा संचालित किया जाएगा।
- निजी ऐप प्रदाताओं के पास उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने एवं पास के क्षेत्र में WANI अनुरूप वाई–फाई हॉटस्पॉट खोजने के लिए ऐप विकसित करने एवं इंटरनेट सेवा तक पहुंचने के लिए ऐप के भीतर ही प्रदर्शित करने की संभावना है।
- शुरूआत में केंद्रीय रजिस्ट्री ऐप प्रदाताओं, पीडीओए एवं पीडीओ के विवरण को बनाए रखेगी।
- शुरुआत में सेंट्रल रजिस्ट्री का रखरखाव C–DoT द्वारा किया जाएगा।

प्रस्ताव के लाभ –

- देश में सार्वजनिक वाई–फाई नेटवर्क का विकास
- ब्रॉडबैंड इंटरनेट के प्रसार में मदद
- आय एवं रोजगार में वृद्धि
- लोगों का सशक्तिकरण

एक और घोषणा –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य भूमि (कोच्चि) एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान को भी मंजूरी दी है।

ऑप्टिकल फाइबर केबल –

- फाइबर–ऑप्टिक केबल एक हाई–स्पीड नेटवर्क केबल है, जो ग्लास फाइबर के स्ट्रैंड से बनी होती है।
- फाइबर–ऑप्टिक्स प्रकाश के स्पंदनों का उपयोग करते हैं, जो छोटे लेजर या प्रकाश–उत्सर्जक डायोड द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो उनके संचार संकेतों या डेटा को एक बिंदु से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं।
- फाइबर कनेक्टिविटी उपकरण अंततः इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की प्रक्रिया है।

वायु से पानी निकालना

समाचार –

- आईआईटी–गुवाहाटी की अनुसंधान टीम ने पहली बार नम हवा से प्रभावी रूप से पानी निकालने के लिए रासायनिक रूप से तैयार SLIPS की अवधारणा का उपयोग किया है।

विवरण –

- इस तरह की जल–संचयन तकनीक कुछ सामग्रियों की हाइड्रोफोबिसिटी या जल–जमाव प्रकृति की अवधारणा का उपयोग करती है।
- हाइड्रोफोबिसिटी की अवधारणा को कमल के पत्ते को देखकर समझा जा सकता है।

तरीका –

- शोधकर्ताओं ने कीट–खाने वाले पौधे की कार्रवाई का उपयोग किया है जिसकी फिसलन भरी सतह पर कीट फिसलकर पौधें की खुराक बन जाते हैं।
- उन्होंने नमी भरी हवा से प्रभावी रूप से पानी निकालने के लिए स्लिपरी लिक्विड–इनफ्यूज्ड पोरस सरफेस (SLIPS) का उपयोग किया।
- SLIPS बाहरी शीतलन व्यवस्था के उपयोग के बिना हवा से पानी को निकालने में सक्षम हैं।
- परंपरागत रूप से, वायुमंडलीय जल जनरेटर (AWG) जो आर्द्र परिवेशी वायु से पानी निकालता है, संघनन का उपयोग करता है।

रासायनिक पैटर्न SLIPS की अवधारणा –

- एक साधारण हाइड्रोकार्बन एसएलआईपी को एक साधारण सीपीयू पेपर पेपर के शीर्ष पर स्पंज जैसी छिद्रयुक्त पॉलिमरिक सामग्री का छिड़काव करके उत्पादित किया गया था।
- इसके अलावा, रासायनिक रूप से संशोधित हाइड्रोफिलिक स्पॉट दो अलग–अलग प्रकार के तेलों के साथ चिकनाई करने से पहले, कोटिंग पर जुड़े हुए थे।
- यह सतह किसी भी शीतलन व्यवस्था की आवश्यकता के बिना नमी/जल वाष्प से लदी हवा से पानी निकाल सकती है।

समय की आवश्यकता –

- विश्व भर में पानी की कमी के कारण गैर–पारंपरिक साधनों के माध्यम से पानी को इकट्ठा करने एवं संरक्षित करने का प्रयास किये गये है एवं आईआईटी–गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने जल संचयन के तरीकों को डिजाइन करने के लिए प्रकृति की ओर रुख किया है।

भारत में पानी की कमी –

- भारत वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े जल संकट में से एक का सामना कर रहा है।
- 50% से अधिक भारतीय आबादी के पास पीने के पानी की कोई सुरक्षित पहुँच नहीं है।
- 200,000 से अधिक लोग सुरक्षित पानी तक पहुंच की कमी से मर जाते हैं।
- 82% से अधिक घरों में बिना पाइप जलापूर्ति होती है।
- समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, 2018 ने नोट किया कि भारत 2050 तक अपने आर्थिक सकल घरेलू उत्पाद का 6% खो देगा।

डेटा सोनीफिकेशन

समाचार –

- नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने क्रेब नेबुला के सोनिफिकेशन का वीडियो साझा किया।
- वीडियो में नेबुला को उसके अलग–अलग रंगों के आधार पर संगीत में रूपांतरित किया गया है।
- नीले रंगों का बास एवं सफेद रंगों को वुड–विंड्स में बदला गया है।
- नेबुला हाइड्रोजन, धूल, हीलियम एवं आयनित गैसों का एक बादल होता है।

नासा के अनुसार, क्रैब नेबुला एक सुपरनोवा का परिणाम है एवं इसे 1054 इस्वी में खोजा गया था। यह पृथ्वी से 6,500 से अधिक प्रकाश वर्ष दूर वृषभ के नक्षत्र में स्थित है।

डेटा सोनिफिकेशन –

- डेटा को ध्वनि में बदलना की प्रक्रिया है। यह डेटा विजुअलाइजेशन का श्रवण संस्करण है। यह परियोजना उपयोगकर्ताओं को कई खगोलीय घटनाओं को सुनने में मदद करती है जैसे कि तारे का जन्म, ब्लैक होल, बादल का जन्म या धूल।

खगोलीय छवियों का परिवर्तन ध्वनियों में –

- नासा के अंतरिक्ष दूरबीन छवियों में परिवर्तित करने से पहले विशाल डिजिटल डेटा एकत्र करते हैं।
- यह डिजिटल डेटा अंतरिक्ष में विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश एवं विकिरण का प्रतिनिधित्व करता है।
- उन्हें मानव आँख से नहीं देखा जा सकता है।
- नासा की चंद्र परियोजना ने इन डिजिटल डेटा का ध्वनि में अनुवाद किया।
- नेबुला के निर्माण की हालिया रिलीज चंद्र परियोजना एवं नासा के सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत की गई थी। चंद्र परियोजना ने अब तक गैलेक्टिक सेंटर, पिलर्स ऑफ क्रिएशन एवं कैसिओपिया की आवाजें जारी की हैं।

गेलेक्टिक केंद्र –

- गेलेक्टिक केंद्र मिल्की वे आकाशगंगा का घूर्णी केंद्र है।
- इसमें न्यूट्रॉन तारे, बौने तारे, धूल एवं गैस के बादल एवं एक सुपर बड़े पैमाने पर ब्लैक होल होता है जिसे धनु ए कहा जाता है।
- गैलेक्टिक सेंटर का वजन सूरज की तुलना में 4 मिलियन गुना अधिक है।

कैसिओपेआ –

- यह एक तारामंडल है जो पृथ्वी से लगभग 11,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह एक बड़े पैमाने पर स्टार के अवशेष हैं।
- लगभग 325 वर्ष पहले सुपरनोवा विस्फोट से विशाल तारा नष्ट हो गया था।
- नक्षत्र की छवि विभिन्न रंगीन फिलामेंट की एक गेंद को दिखाती है। नक्षत्र में प्रत्येक रंग एक विशेष तत्व का प्रतिनिधित्व करता है जैसे कि सिलिकॉन के लिए लाल, बैंगनी लोहे को दर्शाता है, सल्फर के लिए पीला, कैल्शियम के लिए हरा।
- इन तंतुओं से प्राप्त तरंग–दैर्ध्य के डिजिटल डेटा को ध्वनि परियोजना द्वारा ध्वनि में परिवर्तित किया जाता है।

प्लास्मोडियम आवल मलेरिया

समाचार –

- एक दुर्लभ प्रकार का मलेरिया, प्लास्मोडियम ओवल, केरल के कन्नूर जिले में एक सैनिक सूडान से आने के लगभग एक वर्ष बाद जहाँ उन्हें भारतीय शांति अभियानों के हिस्से के रूप में तैनात किया गया था, में पाया गया।
- प्लाजमोडियम ओवल मलेरिया उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अफ्रीका के लिए स्थानिक है।
- इसमें, भारत में मलेरिया के सामान्य प्रकारों जैसे जैसे प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम एवं प्लास्मोडियम विवैक्स से अधिक गंभीर परिणाम मिलते हैं।

मलेरिया –

- मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, यदि मच्छर स्वयं मलेरिया परजीवी से संक्रमित होता है।
- मलेरिया परजीवी के पांच प्रकार हैं – प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लास्मोडियम विवैक्स (सबसे सामान्य), प्लास्मोडियम मलेरिया, प्लास्मोडियम ओवल एवं प्लास्मोडियम नॉलेसी।

भारत में मलेरिया –

- भारत में, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय एवं मध्य प्रदेश के 2019 के उच्च दर वाले राज्यों में 1.57 लाख मलेरिया मामलों में से 1.1 लाख मामले (70%) फाल्सीपेरम मलेरिया के मामले थे।
- 2018 में, राष्ट्रीय वेक्टर–जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) ने अनुमान लगाया कि लगभग 5 लाख लोग मलेरिया से पीड़ित थे (63% प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम के थे)।
- हालिया विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 में कहा गया कि भारत में मामले 2000 में 20 मिलियन से घटकर 2019 में लगभग 5.6 मिलियन हो गए।

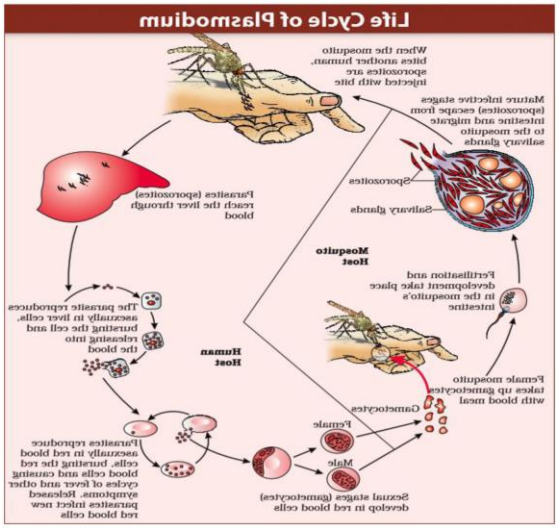

प्लास्मोडियम डिंब –

- पी डिंब शायद ही कभी गंभीर बीमारी का कारण बनता है एवं घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
- ओवले पी विवैक्स के समान है, जो कि हत्यारा रूप नहीं है।
- लक्षणों में 48 घंटों के लिए बुखार, सिरदर्द एवं मतली शामिल है, एवं उपचार का तरीका वैसा ही है जैसा कि पी विवैक्स से संक्रमित व्यक्ति के लिए है।
- वायरल इंफेक्शन होने की तुलना में पी ओवल ज्यादा खतरनाक नहीं है।
- इसे ओवल कहा जाता है क्योंकि लगभग 20% परजीवी कोशिकाओं का आकार अंडाकार होता है।
- अफ्रीका एवं अन्य जगहों पर मलेरिया –
- पी ओवल मलेरिया उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अफ्रीका के लिए स्थानिक है।
- अफ्रीका के बाहर पी ओवल अपेक्षाकृत असामान्य है। यह फिलीपींस, इंडोनेशिया एवं पापुआ न्यू गिनी में भी पाया गया है, लेकिन अभी भी इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम है।
- चीन–म्यांमार सीमा पर 2016 के एक अध्ययन में, यह पाया गया कि पी ओवल एवं पी मलेरिया बहुत कम प्रचलन में थे।

जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2020

समाचार –

- संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम एवं फ्रांस ने जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2020 की सह–मेजबानी की, वस्तुतः 12 दिसंबर को आयोजित किया गया। जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को अपनाने के पांच वर्षों को चिह्नित किया।

विवरण –

- संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में कहा कि 2015 में पेरिस में की गई प्रतिबद्धताएँ 'तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए पर्याप्त' थीं।
- भारत न केवल अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर है, बल्कि उन्हें अपेक्षाओं से अधिक हासिल किया है।
- भारत ने 2005 के स्तर पर उत्सर्जन की तीव्रता में 21% की कमी की है।
- भारत की सौर क्षमता 2014 में 2.63 गीगावाट से बढ़कर 2020 में 36 गीगावाट हो गई है जो अक्षय ऊर्जा क्षमता में विश्व में चौथी सबसे बड़ी है। यह 2022 से पहले 175 गीगावाट तक पहुंच जाएगा।
- भारत ने अब – 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के 450 गीगावाट के साथ और भी अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- भारत ने वन आवरण का विस्तार करने एवं हमारी जैव विविधता की रक्षा करने में भी सफलता प्राप्त की।
- विश्व मंच पर, भारत ने दो प्रमुख पहल की हैं–
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन।

चिंता –

- उपयुक्त कदम नहीं उठाए जाने पर विश्व में इस सदी के अंत तक 3.0 डिग्री से अधिक के भयावह तापमान के बढ़ने की संभावना है।

आगे को राह –

- शिखर सम्मेलन में नेताओं को नए, अधिक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (एनडीसी) के साथ आगे आने के लिए तैयार करने की मांग की गई, जो कि नेट शून्य, दीर्घकालिक 2020 के वित्त वित्त प्रतिज्ञाओं एवं अनुकूलन योजनाओं के लिए दीर्घकालिक रणनीति है।

पेरिस समझौता –

- पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है।
- इसे 196 पार्टियों ने 12 दिसंबर, 2015 को पेरिस में COP 21 पर अपनाया एवं 4 नवंबर, 2016 को प्रवेश किया।

लांसेट नागरिक आयोग –

समाचार –

- भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को महामारी द्वारा फिर से ध्यान में लाया गया है। इस लक्ष्य की ओर एक कदम उठाया गया था, जिसमें लैंसेट सिटीजन्स कमिशन ऑन रीमैजिनिंग इंडियाज हेल्थ सिस्टम लॉन्च किया गया था। यह यूएचसी को प्राप्त करने के लिए नागरिक के रोडमैप को विकसित करने की एक पहल है।

पृष्ठभूमि –

- आयोग को कोविड –19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था, जिसने सभी नागरिकों को व्यापक एवं सस्ती गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली लचीली स्वास्थ्य प्रणाली की आवश्यकता को पूर्ण करने का बीड़ा उठाया है।

यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज –

- यूनिवर्सल हेल्थकेयर एक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है जिसमें किसी विशेष देश या क्षेत्र के सभी निवासियों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का आश्वासन दिया जाता है।

- यह आम तौर पर सभी निवासियों या केवल उन लोगों को प्रदान करने के आसपास आयोजित किया जाता है जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के अंतिम लक्ष्य के साथ या तो स्वास्थ्य सेवाओं या उन्हें प्राप्त करने के साधन अपने आप हासिल नहीं कर सकते।

आयोग का उद्देश्य –

- प्रत्येक भारतीय को गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच की गारंटी देना है।

आयोग की संरचना –

- आयोग का नेतृत्व चार स्वास्थ्य एवं व्यापारिक नेता करेंगे।
- वैज्ञानिक समुदाय, नागरिक समाज एवं निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के तेरह विशेषज्ञ भी आयोग में उनके साथ काम करेंगे।

कमीशन का कार्य –

- यह आयोग भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य में प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने वाले एक परामर्शी एवं भागीदारी प्रयास पर अपनी सिफारिशों को आधार बनाएगा।
- इसके निष्कर्षों एवं सिफारिशों की एक अंतिम रिपोर्ट अगले दो वर्षों में प्रकाशित की जाएगी।
- आगामी वर्ष भर में, जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण, सार्वजनिक परामर्श एवं ऑनलाइन चर्चा के माध्यम से भारत भर से इनसाईट्स इकट्ठा करेगा।
- यह साझेदारियों का भी निर्माण करेगा एवं अकादमिक संस्थानों, नागरिक समाज एवं अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि पूरे क्षेत्र में संवाद एवं ज्ञान साझाकरण को उत्प्रेरित किया जा सके।
- यह सरकार के साथ जुड़ना जारी रखेगा, जिसे यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण भंडार के रूप में देखता है।

आयोग के सिद्धांत –

- आयोग को चार सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा जो हैं –
- UHC सभी स्वास्थ्य चिंताओं को कवर करता है।
- रोकथाम एवं दीर्घकालिक देखभाल प्रमुख हैं।
- चिंता सभी स्वास्थ्य लागतों के लिए वित्तीय सुरक्षा है।
- एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली की आकांक्षा करना जो सभी को समान गुणवत्ता का आनंद दे सके।

आगे को राह –

- एक स्थायी यूएचसी मॉडल के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लागत, गुणवत्ता एवं पहुंच के बीच एक संतुलित व्यापार बंद बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अभिनव साझेदारी के साथ रोगियों, दाताओं एवं प्रदाताओं को संरेखित करने वाला एक सहयोगी दृष्टिकोण, जोखिमों को कम करने, प्रभाव को कम करने, मजबूत सामाजिक रिटर्न बनाने एवं स्थायी यूएचसी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शीघ्रता से प्रयास करेगा।

एकीकृत विकास नियंत्रण एवं संवर्धन विनियम

समाचार –

- एकीकृत विकास नियंत्रण एवं संवर्धन विनियम (यूडीसीपीआर) का महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में रियल एस्टेट विकास को मजबूत करने के लिए अनावरण किया गया था।

विवरण –

- मुंबई नागरिक निकाय, NAINA, MIDC, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट एवं विशेष योजना क्षेत्रों के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों को छोड़कर पूरे राज्य में नए विकास नियंत्रण नियम (DCR) नियम लागू होंगे।
- ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नासिक, नागपुर, सोलापुर एवं कोल्हापुर नए नियमों के दायरे में आएंगे।
- नए नियमों से सड़कों की चौड़ाई, कमरों के आकार आदि में एकरूपता आने की संभावना है। इमारतों की ऊँचाई अलग–अलग होगी, जो भूखंड के आकार एवं इसके फर्श के स्थान सूचकांक (एफएसआई) की क्षमता पर निर्भर करती है।
- नया विनियमन डेवलपर्स को अपने वित्त को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में भी मदद करेगा।
- नए नियम 18 मीटर एवं उससे अधिक की सड़कों की चौड़ाई के लिए 4 के अधिकतम फ्लोर स्पेस इंडेक्स की अनुमति देंगे।
- यह सरकारी विभागों, वैधानिक निकायों एवं नियोजन प्राधिकरणों के लिए कर्मचारियों के क्वार्टरों के विकास एवं पुनर्विकास के लिए न्यूनतम 4,000 वर्ग मीटर का भूखंड क्षेत्र भी निर्धारित करता है।
- नियमों के अनुसार, आवासीय जोन R1 में विकास योजना पर दिखाए गए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में 9 मीटर से नीचे की सड़कों पर एवं आसपास के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में 12 मीटर से कम चौड़ाई वाली सड़कों पर आवासीय भूखंड शामिल हैं।

विनियम की मुख्य विशेषताएं –

- विनियम प्राकृतिक झीलों के 100 मीटर ऊंची बाढ़ लाइन के भीतर नीली बाढ़ लाइन लगाने एवं नदी तट के समीप के क्षेत्रों में निर्माण पर रोक लगाते हैं। पच्चीस वर्ष की बाढ़ लाइन में ब्लू बाढ़ लाइन का निशान है। सौ वर्ष की बाढ़ रेखा लाल बाढ़ लाइन का निशान है। बाढ़ की रेखा, बाढ़ के पानी के पहुँचने का अधिकतम स्तर है।
- नियमों में कहा गया है कि किसी भी लेआउट का 10% मनोरंजन प्रयोजनों के लिए रखा जाना चाहिए।
- नियम यह भी कहते हैं कि 10,000 वर्ग मीटर तक के लेआउट का 5% एवं 10,000 वर्ग मीटर से ऊपर के लेआउट का 10% सुविधाओं के लिए आरक्षित होगा।
- जॉगिंग, रास्ते एवं साइकिल ट्रैक के निर्माण की अनुमति केवल नदी के किनारों से 15 मीटर की दूरी पर है।
- 24 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों के साथ सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होनी चाहिए।यह 15 मीटर होना चाहिए यदि इमारतें 50 मीटर ऊंची हैं।

- भीड़भाड़ वाले एवं गैर–भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कुछ उपयोगों के लिए हाई फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) प्रस्तावित किया गया है। नौ मीटर से कम चौड़ी सड़कों के लिए 1.10 का एफएसआई आधार प्रस्तावित किया गया है एवं 30 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों के लिए 1. 20 प्रस्तावित किया गया है।
- नियम अन्य प्रावधानों जैसे स्लम पुनर्वास, विरासत संरक्षण, विकास अधिकारों के हस्तांतरण आदि पर भी लागू होते हैं। नियम अत्यधिक भीड़भाड़ वाले मुंबई शहर एवं राज्य के अन्य आगामी महानगरों के विकास में मदद करेंगे।

इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (GRIHA) समिट के लिए ग्रीन रेटिंग

समाचार –

- हाल ही में, 12 वीं ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (GRIHA) समिट के उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया। 12 वें GRIHA वर्चुअल समिट का विषय 'रिज्यूनीवेटिंग, रिसिलियंट, हैबीटेट' है।

मुख्य विचार –

- इसका उद्देश्य नवीन प्रौद्योगिकियों एवं समाधानों पर विचार–विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में सेवा करना है जो पूरे समुदाय के लाभ के लिए स्थायी एवं लचीला समाधान विकसित करने के लिए मजबूत तंत्र बनाने में मदद करेगा।
- उपराष्ट्रपति ने आयोजन के दौरान SHASHWAT पत्रिका एवं पुस्तक '30 स्टोरीज बियॉन्ड बिल्डिंग्स' का लोकार्पण किया, जो GRIHA परिषद एवं लोक निर्माण विभाग, महाराष्ट्र सरकार के बीच व्यापक सहयोग का दस्तावेज है।

GRIHA –

- GRIHA ग्रीन रेटिंग के लिए एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए एक संक्षिप्त नाम है।
- GRIHA एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है – 'निवास'। ह्यूमन हैबिटेट्स (इमारतें) पर्यावरण के साथ विभिन्न तरीकों से इंटरएक्ट करती हैं।
- उनके जीवन चक्र में, निर्माण से लेकर संचालन एवं फिर विध्वंस तक, वे ऊर्जा, पानी, सामग्री आदि के रूप में संसाधनों का उपभोग करती हैं एवं कचरे को सीधे नगरपालिका के कचरे के रूप में या अप्रत्यक्ष रूप से बिजली उत्पादन से उत्सर्जन के रूप में उत्सर्जित करती हैं।
- GRIHA एक इमारत की संसाधन खपत, अपशिष्ट उत्पादन एवं समग्र पारिस्थितिक प्रभाव को कुछ राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य सीमाओं / मानदंड के भीतर कम करने का प्रयास करता है।
- जीआरआईएचए ऊर्जा खपत, अपशिष्ट उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने आदि जैसे पहलुओं को निर्धारित करने का प्रयास करता है ताकि प्रबंधन, नियंत्रण सबसे अच्छी संभव सीमा तक कम हो सके।

GRIHA परिषद –

- ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबीटेट असेसमेंट (GRIHA) परिषद, भारत सरकार द्वारा भारत में हरित इमारतों का निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, द एनर्जी एवं रिसोर्स इंस्टीट्यूट (TERI) एवं मिनीस्टरी ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (MNRE) द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र, गैर–लाभकारी संस्थान है।
- GRIHA को 2007 में MNRE द्वारा भारत में ग्रीन बिल्डिंग के लिए राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली के रूप में अपनाया गया था।
- GRIHA मात्रात्मक एवं गुणात्मक मानदंडों के आधार पर, अपने पूरे जीवन चक्र पर समग्र रूप से एक इमारत के पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, जिससे हरित इमारतों एवं स्थायी निवास के लिए एक निश्चित मानक प्रदान किए गए है।
- यह संसाधनों की खपत, अपशिष्ट उत्पादन एवं इमारतों एवं आवास के समग्र पारिस्थितिक/पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है।

सरकार द्वारा अन्य पहल –

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने जनवरी 2019 में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया (GHTCIndia) का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य सर्वोत्तम उपलब्ध एवं सिद्ध निर्माण प्रौद्योगिकियां जो आवास निर्माण में एक प्रतिमान बदलाव को सक्षम करने के लिए टिकाऊ, हरित एवं आपदा–प्रतिरोधी हैं की पहचान करना एवं उन्हें मुख्यधारा में लाना है।
- एफोर्डेबल सस्टेनेबल हाऊसिंग एक्सीलरेटर्स – इंडिया (ASHA–इंडिया) पहल के अंर्तगत संसाधन–कुशल, लचीला एवं टिकाऊ निर्माण तथा अभिनव सामग्री, प्रक्रियाओं एवं प्रौद्योगिकी की पहचान के लिए पांच ऊष्मायन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

सीएमएस – 01

समाचार –

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश के नए संचार उपग्रह CMS–01 को अंतरिक्ष में इच्छित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।
- उपग्रह को ले जाने वाले वर्कहॉर्स रॉकेट PSLV–C50 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी।
- उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इंजेक्ट किया गया।

विवरण –

- अगले कुछ दिनों में उपग्रह को कक्षा में थोड़ा ऊपर उठाने एवं भू–समकालिक कक्षा में अपनी सही स्थिति में स्थानांतरित करने के प्रयास किए गए, ताकि यह भारत के ठीक ऊपर हो।
- एक बार उपग्रह तैयार होने के बाद, यह भारतीय मुख्य भूमि एवं अंडमान–निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह के लिए कम से कम सात वर्षों के लिए सी–बैंड संचार प्रदान करेगा।
- CMS–01, GSAT–12 की सेवाओं की जगह लेगा जिसे 2011 में आठ वर्ष के अपेक्षित मिशन जीवन के साथ लॉन्च किया गया था।

संचार उपग्रह

- एक कृत्रिम उपग्रह होता है जो ट्रांसपोंडर के माध्यम से रेडियो दूरसंचार संकेतों को रिले करता एवं बढ़ाता है, यह एक स्रोत ट्रांसमीटर एवं पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर रिसीवर के बीच एक संचार चैनल बनाता है।
- संचार उपग्रहों का उपयोग टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट एवं सैन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।
- कईयों को भूमध्यरेखीय कक्षा में भूमध्य रेखा से ऊपर 22,236 मील (35,785 किमी) पर स्थापित किया गया हैं, ताकि उपग्रह आकाश में एक ही बिंदु पर स्थिर दिखाई दे, इसलिए ग्राउंड स्टेशनों के उपग्रह डिश एंटेना को उस स्थान पर स्थायी रूप से लक्षित किया जा सकता है एवं इसे ट्रैक करने के प्रयास नही करना पड़ते।
- दूरसंचार लिंक के लिए उपयोग की जाने वाली उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगें दृष्टि की रेखा से यात्रा करती हैं एवं इसलिए पृथ्वी की वक्रता से बाधित होती हैं।
- संचार उपग्रहों का उद्देश्य पृथ्वी की वक्र के आसपास सिग्नल को रिले करना है जो व्यापक रूप से अलग भौगोलिक बिंदुओं के बीच संचार की अनुमति देता है।
- संचार उपग्रह रेडियो एवं माइक्रोवेव आवृत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करते हैं।
- सिग्नल हस्तक्षेप से बचने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पास ऐसे नियम हैं जिनके लिए फ्रीक्वेंसी रेंज या 'बैंड' कुछ संगठनों को उपयोग करने की अनुमति है। बैंड का यह आवंटन सिग्नल के हस्तक्षेप के जोखिम को कम करता है।

आगामी परियोजनाएँ –

- 2021 की शुरुआत में, भारत को जियो इमेजिंग सैटेलाइट जीआईएसएटी –1 (मार्च से विलंबित) एवं पीएसएलवी–सी 51 लॉन्च करने की उम्मीद है, जो तीन निजी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजेगा – जिसमें पिक्ससेल इंडिया नामक एक स्टार्टअप भी शामिल है। आनंद नामक उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के एक समूह का हिस्सा होगा।
- गगनयान के पहले चालक दल के 2022 की शुरुआत में उड़ान भरने की उम्मीद है।

भारत के फार्मास्युटिकल उत्पादकों का संगठन (OPPI)

समाचार –

- केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने नई दिल्ली में ओपीपीआई के भारत के फार्मास्यूटिकल उत्पादकों के संगठन के दो दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।

विवरण –

- मंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान आजीवन उपलब्धि एवं विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया।
- इस महामारी वर्ष के दौरान भारतीय दवा क्षेत्र के योगदान को प्रबल किया है।
- भारत को अक्सर 'विश्व की फार्मेसी' के रूप में जाना जाता है एवं यह चल रहे कोविड–19 महामारी के दौरान पूरी तरह से सच साबित हुआ है जब भारत विश्व के बाकी हिस्सों में महत्वपूर्ण जीवन–रक्षक दवाओं का उत्पादन एवं निर्यात करता रहा।

ओपीपीआई –

- फार्मास्युटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया (ओपीपीआई) का संगठन 1965 में स्थापित किया गया था एवं यह भारत में अनुसंधान आधारित दवा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है।
- OPPI देश के स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों का समर्थन करने एवं स्थायी समाधान खोजने के लिए सभी हितधारकों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- भारत में स्वास्थ्य सेवा के विस्तार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है एवं ओपीपीआई का मानना है कि दवा उद्योग समाधान का हिस्सा बन सकता है।
- OPPI के कड़े फार्मास्युटिकल प्रैक्टिस कोड हमारी सभी सदस्य कंपनियों को बांधते हैं। ओपीपीआई ने एक नैतिकता एवं व्यापार अखंडता कार्य समूह का गठन किया है।
- OPPI भारत की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध अनुसंधान एवं नवाचार संचालित दवा कंपनियों का एक संगठन है।
- इसके प्रमुख लक्ष्य निम्न प्रकार हैं –
- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल समाधानों के लिए अधिक पहुंच की सुविधा
- अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना
- ज्ञान का प्रसार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना
- नीतिगत संवादों में सार्थक योगदान देना

केजी बेसिन में गैस का उत्पादन

समाचार –

- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं ब्रिटिश पेट्रोलियम (BP) ने एशिया में सबसे गहरे ऑफ–किनारे गैस क्षेत्र केजी बेसिन के आर क्लस्टर से गैस उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है।
- केजी–डी 6 ब्लॉक में आरआईएल की भागीदारी 66.7% है एवं ब्लॉक में बीपी की भागीदारी 33.3% है।
- केजीडी 6 ब्लॉक में तीन गहरे जल गैस परियोजनाओं में से पहला क्षेत्र है।

केजी–बेसिन का महत्व –

- कृष्णा गोदावरी बेसिन में सैटेलाइट क्लस्टर एवं एमजे गैस क्षेत्रों के साथ आर क्लस्टर, प्राकृतिक गैस के लगभग 30 MMSCMD (मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन) या 2023 तक प्राकृतिक गैस के लिए भारत की अनुमानित मांग का उत्पादन करने की उम्मीद है। ।
- अकेले आर क्लस्टर क्षेत्र में 12.9 MMSCMSD का उत्पादन या भारत के वर्तमान प्राकृतिक गैस उत्पादन का लगभग 10% होने की उम्मीद है।

भारत के ऊर्जा सुरक्षा के प्रयास –

- तीन परियोजनाएँ भारत की ऊर्जा टोकरी में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6.2% से बढ़ाकर अब 2030 तक प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
- आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने एवं ऊर्जा सुरक्षा में सुधार के लिए प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाना एक महत्वपूर्ण पहलू है।

- यह सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनियों के लिए फायदेमंद होगा एवं भारत के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा।

तीन फील्ड का विवरण –

- आरआईएल एवं बीपी संयुक्त रूप से इन तीन क्षेत्रों पर कुल 40,000 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए तैयार हैं।
- आर क्लस्टर से गैस का उत्पादन मई 2020 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन कोविद –19 महामारी के प्रभाव के कारण देरी हुई।
- अगले वित्तीय वर्ष में उपग्रह क्लस्टर का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।
- क्षेत्र (R क्लस्टर) काकीनाडा तट से मौजूदा KG D6 नियंत्रण एवं रिसर प्लेटफॉर्म (CRP) से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एवं इसमें एक उप–उत्पादन केंद्र के माध्यम से CRP के लिए एक उप–उत्पादन प्रणाली शामिल है।

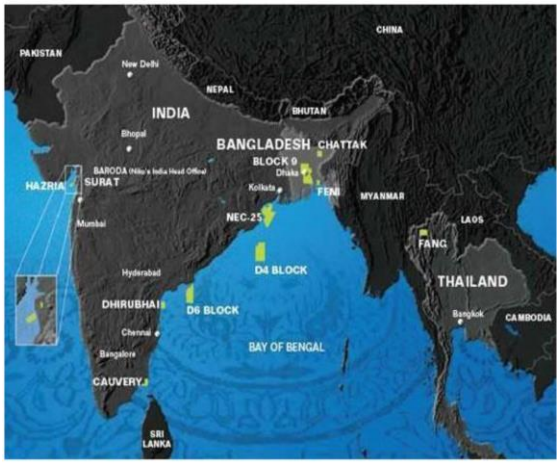

गैस टैरिफ में वृद्धि–

- गैस परिवहन टैरिफ के फार्मूले में हाल के बदलावों से इन तीन क्षेत्रों में रिलायंस एवं बीपी के निवेशों को लाभ होने की संभावना है।
- नियम मौजूदा प्रणाली से अलग हैं जो गैस के स्रोत से दूरी एवं पाईपलाईनों की संख्या के आधार पर उपभोक्ताओं से शुल्क लेते हैं। इसके बजाए अब एक यूनिफाईड टैरिफ एक 300 किलोमीटर के भीरत गैस परिवहन के लिए एक अन्य टैरिफ प्राकृतिक गैस को स्रोत से 300 कि.मी.से अधिक दुर ले जाए जाने पर लगाये जाते है।
- इस कदम का उद्देश्य प्राकृतिक गैस को ग्राहकों के लिए सस्ता बनाना है। इससे रिलायंस को लाभ होगा क्योंकि केजी–डी 6 बेसिन की गैस के अधिकांश ग्राहक 300 किमी दूर होंगे।
- कम परिवहन शुल्क से रिलायंस की गैस के लिए चार्ज करने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।

तटीय रडार नेटवर्क

समाचार –

- तटीय राडार श्रृंखला नेटवर्क के विस्तार के लिए भारत के प्रयासों के तहत, समुद्रों की वास्तविक समय पर निगरानी को सक्षम करने का प्रयास किया गया, हिंद महासागर के तटीय देशों मालदीव, म्यांमार एवं बांग्लादेश में तटीय रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए उन्नत चरणों में प्रयास किए जा रहे हैं।

तटीय रडार चेन नेटवर्क –

- इसका उद्देश्य रणनीतिक हिंद महासागर क्षेत्र में सूचना एवं समुद्री डोमेन जागरूकता का एक नेटवर्क तैयार करना है।
- इससे हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में क्षमता निर्माण के लिए भारत की सहायता का विस्तार करने में भी मदद मिलेगी।
- इन देशों को दी जाने वाली सहायता भारत के कार्यक्रम के तहत आती है जिसे SAGAR – सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन कहा जाता है।

झलकियाँ –

- मॉरीशस, सेशेल्स एवं श्रीलंका को पहले ही देश के तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क में एकीकृत किया जा चुका है।
- तटीय राडार श्रृंखला नेटवर्क के चरण–I के तहत, देश के समुद्र तट पर 46 तटीय राडार स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
- परियोजना के दूसरे चरण के तहत, जो वर्तमान में चल रहा है, 38 स्थिर राडार स्टेशन एवं चार मोबाइल रडार स्टेशन तटरक्षक द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं एवं पूरा होने के उन्नत चरण में हैं।
- भारतीय नौसेना का सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र (IMAC) गुरुग्राम में स्थित है, जिसे 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद समुद्री डेटा संलयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था।
- समुद्रों पर यातायात के संबंध में सूचना के आदान–प्रदान के हिस्से के रूप में, नौसेना को 36 देशों एवं तीन बहुपक्षीय निर्माणों के साथ सफेद शिपिंग समझौतों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है।
- अब तक 22 देशों एवं एक बहुपक्षीय निर्माण के साथ समझौते संपन्न हुए हैं।

हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सूचना संलयन केंद्र –

- IFC को गुरुग्राम में स्थापित किया गया है एवं इसे सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र के साथ मिलाया गया है जिसे भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित किया जाता है।
- भारतीय नौसेना का सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र (IMAC), 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद स्थापित, समुद्री डेटा संलयन के लिए नोडल एजेंसी है।
- यह शीघ्र ही एक राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता (NDMA) केंद्र बन जाएगा।

भारत में स्वास्थ्य सेवा

समाचार –

- यह ऐसे देश में 70% निजी एवं 30% सार्वजनिक है जहाँ 80% लोगों को स्वास्थ्य के लिए कोई सुरक्षा नहीं है एवं आऊट–ऑफ–पॉकेट खर्च 62% है।
- जीडीपी के 1.13% सार्वजनिक खर्च के साथ, स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों विशेष रूप से नर्सों एवं दाइयों की भारी कमी है।

निजी क्षेत्र एवं बीमा संयोजन के साथ मुद्दे –

- निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल पूंजी पर वापसी द्वारा संचालित होती है।
- बीमा बैकअप बिल का विस्तार करने के लिए अस्पतालों को प्रोत्साहित करता है लेकिन रोगियों को उनके सर्वोत्तम हित में हिस्सा नहीं मिलता है।
- दूसरी ओर, सरकार के पास प्रक्रियाओं की कीमत कम करने के लिए प्रोत्साहन है, नतीजतन, अस्पताल कुछ सेवाओं एवं प्रक्रियाओं का चयन करते हैं (जबकि कुछ को नकारते हुए)।
- लेकिन बीमा की सीमा का स्तर अस्पताल के हित में परवाह किए बिना दावा किया जाता है।
- जब सरकार एक ट्रस्ट मॉडल के तहत ऐसा करने की क्षमता के बिना दावे को स्थगित करती है, तो सिस्टम आज नही तो कल सुलझ जाएगा।
- ऐसे मामले में, डॉक्टर एवं रोगी भुगतान करने की क्षमता से विवश नहीं होंगे एवं जबकि सीमांत निजी लागत शून्य है, सामाजिक लागत अधिक हो सकती है।

बीमा–निजी क्षेत्र के संयोजन का प्रभाव –

- स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि के मामले में व्यापक मांग में वृद्धि का प्रभाव पड़ता है।
- इसके परिणामस्वरूप बीमा प्रीमियम में वृद्धि होती है, जो लंबी अवधि में राजकोषीय हानि का कारण बनाता है।
- किसी भी मामले में, माध्यमिक एवं तृतीयक देखभाल का बीमा देश एवं लोगों द्वारा दीर्घकालिक निवेश को धक्का देता है एवं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की निरंतर उपेक्षा की ओर जाता है।
- यह इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि आयुष्मान भारत के तहत 12 करोड़ कार्ड धारकों में से केवल 1.27 करोड़ लोगों ने योजना का लाभ उठाया है।
- अंत में, हमारे जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के साथ इस प्रकार की एक सामाजिक बीमा योजना केवल सरकारी अस्पताल की उपेक्षा करने की कीमत पर होती है।

आगे को राह –

- ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए प्रतिपक्ष दायित्व वाले डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना।
- ग्रामीण इलाकों में आजादी से पहले के लाइसेंसधारी चिकित्सा व्यवसायी को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है।
- नर्सिंग व्यवसायी बनने के लिए बीएससी (नर्सिंग) के स्नातकों को सशक्त बनाना – जैसा कि कई देशों में प्रचलित है।
- लिंग के नजरिए से भी, यह मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के कोण से बेहतर है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बजट में तीन गुना अधिक आवंटन प्राप्त करना चाहिए एवं जनसंख्या वृद्धि के आधार पर डॉक्टर एवं पैरामेडिक बल को दोगुना किया जाना चाहिए।
- राज्यों को स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं डॉक्टरों की नियुक्तियों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- भारत में प्रति डॉक्टर 0.6 नर्सों का अनुपात है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का विनिर्देश प्रति डॉक्टर तीन नर्सों का है।

स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 'रिपोर्ट

समाचार –

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 'स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018' रिपोर्ट जारी की गई।

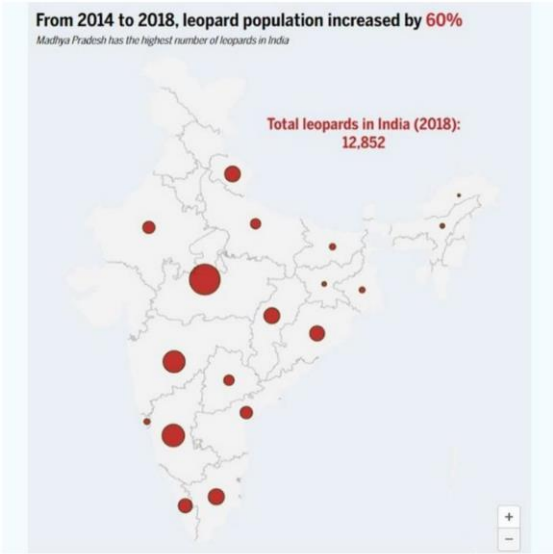

झलकियाँ –

- भारत में तेंदुए की आबादी में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत में अब 12,852 तेंदुए हैं।
- मध्य प्रदेश (3,421), कर्नाटक (1783) एवं महाराष्ट्र (1690) जिन्होंने सबसे अधिक तेंदुए का अनुमान दर्ज किया है।
- तेंदुए सबसे अनुकूल मांसाहारी जानवरों में से हैं, एवं मानव आवास के बहुत करीब मौजूद हैं।
- पहले एक अध्ययन में भारत में तेंदुओं के चार अलग–अलग उप–समूह पाए गए थे जिनमें उच्च आनुवंशिक विविधताएँ थीं– पश्चिमी घाट के तेंदुए, दक्खन का पठार अर्ध–शुष्क क्षेत्र, शिवालिक पर्वत एवं तराई उत्तर भारत में क्षेत्र।
- तेंदुए की स्थिति एवं वितरण के हालिया मेटा–विश्लेषण का सुझाव है कि अफ्रीका में प्रजातियों के लिए 48–67% रेंज नुकसान एवं एशिया में 83–87% है।
- भारत में, तेंदुओं ने पिछले 120–200 वर्षों में संभवतः मानव–प्रेरित 75–90% जनसंख्या में गिरावट का अनुभव किया है।

- भारतीय उपमहाद्वीप में अवैध शिकार, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक शिकार में कमी एवं संघर्ष तेंदुए की आबादी के लिए बड़े खतरे हैं। इन सभी के कारण इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) द्वारा प्रजाति की स्थिति को 'नियर थ्रेटेन्ड' से 'वल्नरेबल' में डाल दिया गया।

भारतीय तेंदुआ –

- भारतीय तेंदुआ (Panthera pardus fusca) एक तेंदुआ उप–प्रजाति है जो व्यापक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में वितरित है।
- पैंथेरा परदूस को IUCN रेड लिस्ट में 'वल्नरेबल' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि आबादी ने निवास स्थान के नुकसान खाल एवं शरीर के अंगों के अवैध व्यापार के लिए अवैध शिकार, एवं संघर्ष स्थितियों के कारण उत्पीड़न एवं विखंडन के बाद गिरावट आई है।
  - भारतीय तेंदुआ भारतीय उपमहाद्वीप पर होने वाली बड़ी बिल्लियों में से एक है, इसके अलावा एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, हिम तेंदुए एवं बादल वाले तेंदुए हैं।

B-1-1-7 लाइनेज

समाचार –

- यूके ने SARS–CoV–2 का एक नया संस्करण देखा, जो वहां 'तेजी से फैल रहा है'।

विवरण –

- दक्षिण एवं पूर्वी इंग्लैंड में कोविड–19 मामलों में तेजी से वृद्धि के पीछे नए SARS–CoV–2 संस्करण का कारण बताया गया।
- इसे VUI (वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन) 202012/01 या B-1-1-7 लाइनेज के रूप में संदर्भित किया जा रहा है।

वेरिएंट क्या है?

- वेरिएंट की पहचान जीनोमिक सर्विलांस में कोविड–19 Genomics UK (COG–UK) द्वारा की गई थी, जो एक संघ था जो यूके से जीनोम अनुक्रमण डेटा का विश्लेषण करता है। वैश्विक Covid–19 डेटाबेस (GISAID) में COGUK का सबसे बड़ा योगदान है।
- वैरिएंट नए कोरोनोवायरस एसएआरएस–सीओवी –2 के स्पाइक प्रोटीन में कई म्यूटेशन का परिणाम है, साथ ही साथ आरएनए वायरस के अन्य जीनोमिक क्षेत्रों में भी उत्परिवर्तन होता है।
- प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि यह पहले प्रसारित वेरिएंट की तुलना में अधिक पारगम्य है।
- COG– यूके ने इनमें से एक म्यूटेशन की पहचान 'N501Y' के रूप में की, स्पाइक प्रोटीन के एक क्षेत्र में जो मानव में एक प्रमुख प्रोटीन को बांधता है।
- COG– यूके ने इनमें से एक म्यूटेशन की पहचान 'N501Y' के रूप में की, जो स्पाइक प्रोटीन के एक क्षेत्र में मानव कोशिका ACE2 रिसेप्टर में एक प्रमुख प्रोटीन को बांधता है। यह एक संकेत था कि परिवर्तन, सैद्धांतिक रूप से, वायरस अधिक संक्रामक हो सकता है।

IUCN निष्कर्ष

समाचार –

- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हाल ही में पाया कि शार्क, किरणें एवं चिमेरेस विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना कर रहे हैं।

मुख्य निष्कर्ष –

- शार्क विशेषज्ञ समूह ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक आकलन किया एवं पाया कि देश के महासागरों में पाई जाने वाली शार्क की 170 प्रजातियों में से 19 विलुप्त होने का सामना कर रही हैं।
- भारत के महासागरों में लगभग 11% प्रजातियाँ विलुप्त होने का सामना कर रही हैं।
- भारत के महासागरों में 170 प्रजातियों में से, 30 को खतरे की प्रजातियों के लिए IUCN रेड लिस्ट के अनुसार लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 2014 में हुए अंतिम मूल्यांकन में, शार्क, किरणों एवं चिमेरों के केवल 3% को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
- हालाँकि, यह 2020 में बढ़कर 11% हो गया है।
- लुप्तप्राय श्रेणी में प्रजातियों की संख्या 2014 में 5% से बढ़कर 2020 में 18% हो गई है।
- हाल ही में आईयूसीएन रेड लिस्ट अपडेट ने भारतीय स्वेल शार्क को पहली बार सीमित भौगोलिक सीमा एवं जनसंख्या में गिरावट के कारण गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया।
- इंडियन स्वेल शार्क एक छोटी गहरी पानी की बिल्ली शार्क है। यह केरल, श्रीलंका, कोल्लम के तटों में पाया जाता है। वे महाद्वीपीय ढलान पर 100–500 मीटर की गहराई पर होते हैं।
- समुद्री सफेद टिप शार्क जिसे लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया था, अब इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूचीबद्ध किया गया है। व्हाइट टिप शार्क के लीवर में स्क्वेलीन की उच्च मात्रा होती है।
- स्क्वालेन एक प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक है जो शार्क के जिगर के तेल में पाया जाता है एवं व्यापक रूप से दवा उद्योग में उपयोग किया जाता है।
- टारगेट फिशिंग एवं बाय–कैच के कारण किरणों एवं शार्क की संख्या में भारी गिरावट आई है।
- टारगेट फिशिंग तब होती है जब किसी विशेष प्रकार की मछली को लक्षित किया जाता है। दूसरी ओर, मछली पकड़ने वाली मछली है, दूसरी मछली बगल में पकड़ी जाती है।
- IUCN आकलन के अनुसार, 38 शार्क को वल्नरेबल, 23 को लिस्ट कंसर्न के रूप में, 27 को नियर थ्रेटन्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ –

- आईयूसीएन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम कर रहा है।
- यह डेटा एकत्र करने एवं विश्लेषण, अनुसंधान, क्षेत्र परियोजनाओं, वकालत एवं शिक्षा में शामिल है।
- IUCN का मिशन प्रकृति के संरक्षण एवं किसी भी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विष्व भर के समाजों को प्रभावित करना, प्रोत्साहित करना एवं सहायता करना है।

- IUCN ने संरक्षण पारिस्थितिकी से परे अपना ध्यान केंद्रित किया है एवं अब अपनी परियोजनाओं में सतत विकास से संबंधित मुद्दों को शामिल करता है।
- संगठन को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक रूप से धमकी प्रजातियों के IUCN रेड लिस्ट को संकलित एवं प्रकाशित करने के लिए जाना जाता है, जो विश्व भर में प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का आकलन करता है।
- इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है।

कंपनियां (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (CARO)

समाचार –

- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (CARO) की अधिसूचना की घोषणा की है। CARO 2020, 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों से लागू होगा।
- पृष्ठभूमि –
- इससे पहले, CARO 2020 को 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू होना था।
- CARO 2020 की नई रिपोर्टिंग शासन प्रणाली – जिसे MCA ने इस वर्ष फरवरी में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से पेश किया था – CARO 2016 को अलग कर दिया था।

नए आदेश का विवरण –

- नए शासन के तहत, एक लेखा परीक्षक को कई विवरणों को रिपोर्ट करने/प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी जिसके अब तक प्रमाणित होने की आवश्यकता नहीं थी।
- नए CARO–2020 में 21 आइटमों की आवश्यकता है।

विवरण –

- CARO को कंपनियों को व्हिसलब्लोअर शिकायतों एवं उधार की अदायगी में चूक सहित विभिन्न मुद्दों पर प्रकटीकरण का पालन करने की आवश्यकता है।
- बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कार्यवाही के विवरण का खुलासा।
- लेखा परीक्षक को कंपनी द्वारा किए गए निवेश का विवरण प्रदान करना चाहिए।
- कंपनी या कंपनी द्वारा किए गए धोखाधड़ी की सूचना दी जानी चाहिए।
- वित्तीय वर्ष में नकदी के नुकसान एवं पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के बारे में बताया जाना चाहिए।
- रिपोर्ट में ऋण चुकौती अवधि एवं चुकाए जाने वाली राशि का विवरण होना चाहिए।

महत्व –

- CARO 2020 निवेशकों एवं वित्तीय संस्थानों दोनों के लिए उपलब्ध जानकारी को बढ़ाता है। यह खातों में पारदर्शिता के लिए एक बड़ा कदम है।

सकारात्मक वेतन प्रणाली

समाचार –

- भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी, 2021 से 50,000 रुपये से अधिक के चेक लेनदेन के लिए 'सकारात्मक वेतन प्रणाली' की शुरुआत की।
- चेक लेनदेन के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली –
- सकारात्मक वेतन की अवधारणा में लार्जवेल चेक के प्रमुख विवरणों को फिर से जोड़ने की एक प्रक्रिया शामिल है।
- इस प्रक्रिया के तहत, चेक जारी करने वाला व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से, एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग एवं एटीएम जैसे चैनलों के माध्यम से, उस चेक का कुछ न्यूनतम विवरण (जैसे दिनांक, लाभार्थी का नाम, या भुगतानकर्ता एवं राशि) बैंक को देता है जिनका विवरण चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) द्वारा प्रस्तुत चेक के साथ क्रॉस–चेक किया जाता है।
- किसी भी विसंगति को सीटीएस द्वारा अदाकर्ता बैंक एवं प्रस्तुतकर्ता बैंक को भेजा जाता है, जो तब निवारण के उपाय करते हैं।

विवाद निवारण तंत्र –

- केवल नई प्रणाली के साथ अनुपालन करने वाले चेक को विवाद निवारण तंत्र के तहत स्वीकार किया जाता है। सदस्य बैंक चेक ट्रंकेशन सिस्टम के बाहर एकत्र चेक के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करेंगे।
- पॉजिटिव पे के तहत किस तरह के चेक आएंगे?
- बैंक 50,000 रुपये एवं उससे अधिक की राशि के लिए चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों के लिए नई प्रणाली को सक्षम करेंगे।
- जबकि इस सुविधा का लाभ खाताधारक के विवेक पर है, बैंक 5,00,000 एवं उससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं।
- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) CTS में सकारात्मक वेतन की सुविधा विकसित करेगा, एवं इसे सहभागी बैंकों को उपलब्ध कराएगा।
- सकारात्मक वेतन प्रणाली का हिस्सा
- चेक ट्रंकेशन सिस्टम वर्तमान में पूरे भारत में उपलब्ध है। यह वर्तमान में खुदरा भुगतान का 2% मात्रा के संदर्भ में एवं 15% खुदरा भुगतान मूल्य के संदर्भ में शामिल करता है।

वर्तमान परिदृश्य –

- वर्तमान में, CTS–2010 मानक जो चेक पत्तियों पर न्यूनतम सुरक्षा सुविधाओं को निर्दिष्ट करता है, चेक धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करता है। दूसरी ओर, चेक फॉर्म पर फील्ड प्लेसमेंट का मानकीकरण छवि चरित्र या ऑप्टिकल चरित्र पहचान तकनीक के उपयोग द्वारा प्रसंस्करण के माध्यम से सीधे सक्षम होता है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया –

- यह भारत में खुदरा भुगतान एवं निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एकछत्र संगठन है।
- 2008 में स्थापित, एनपीसीआई एक गैर–लाभकारी संगठन है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित किया गया है।

CHAHAL ACADEMY

Chahal Academy has pan India presence

VISIT US AT

N New Delhi: 982-155-3677
Corporate Office
Office No.B-7, Lower Ground floor, Apsara Arcade Near Karol Bagh, Metro Gate No. 7, New Delhi - 110060

M Mumbai Branch: 990-911-1227
415, Pearl Plaza Building, 4th Floor, Exactly opp Station Next to Mc Donalds. Andheri West, Andheri West, Mumbai, Maharasthra,-

K Kolkata : 728-501-1227
31/3, Bankim Mukherjee Sarani, New Alipore, Block J- Siddharth Apartment, 3rd Floor, Opposite Corporation Bank, Kolkata - 700053, West Benga

A Ahmedabad: 726-599-1227
Office No. 104, First Floor Ratna Business Square, Opp. H.K.College, Ashram Road, Ahmedabad - 380009

A Anand: 720-382-1227
Head Office
T9-3rd Floor Diwaliba Chambers,Vallabh Vidyanagar, Near ICICI Bank, Bhai Kaka Statue, Anand - 388120

B Bhubaneswar : 720-191-1227
1899/3902, First Floor, Lane No. 2, Near Laxmi Narayan Temple, Nilakantha Nagar, Nayapalli, Bhubaneswar - 751006, Odisha.

C Chandigarh : 726-591-1227
2nd Floor, SCO-223, Sector-36-D, Above Chandigarh University Office, Chandigarh - 160036.

D Dehradun Branch: 721-119-1227
Near Balliwala Chowk, General Mahadev Singh Road, Kanwali, Dehradun, Uttarakhand- 248001.

G Gandhinagar: 6356061801
Office No. 122 , 1st Floor , Siddhraj Zori , KH, O, Sargasan Cross Road, Gandhinagar, Gujarat 382421

K Kanpur : 720-841-1227
2nd Floor, Clyde House, Opposite Heer Palace Cinema, The Mall Road, Kanpur Cantonment, Kanpur - 208004, Uttar Pradesh.

P Patna : 726-591-1227
3rd Floor, Pramila mansion, Opposite Chandan Hero Showroom, Kankarbagh Patna - 800020, Bihar

R Raipur Branch: 728-481-1227
D-117, first floor, Near Shri Hanuman Mandir, Sector-1, Devendra Nagar, Raipur, Chattisgarh- 492009.

R Rajkot Branch: 762-401-1227
3rd Floor,Balaji House 52 Janta Society Opp LIC Of IndiaTagore Road Rajkot 360001

R Ranchi: 728-491-1227
3rd Floor, SMU Building, Above Indian Overseas Bank, Purulia Road, New Barhi Toli, Ranchi - 834001, Jharkhand.

S Surat: 720-391-1227
Office No. 601, 6th Floor, 21st Century Business Centre, Besides World Trade Centre, Near Udhna Darwaja, Ring Road Surat - 395002

V Vadodara: 720-390-1227
102-Aman Square, Besides Chamunda Restaurant, Behind Fatehgunj Petrol Pump, Vadodara, Gujarat- 390002

COMING SOON : BENGALURU| GUWAHATI |HYDRABAD | JAIPUR | JAMMU | KOCHI | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE

Write us at: chahalacademy@gmail.com | www.chahalacademy.com

Follow us at: YouTube Linked in